चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 05 सितंबर–11 सितंबर 2011

मूल्य 5 रुपये

एक कहानी बेहतर मैनेजमेंट की

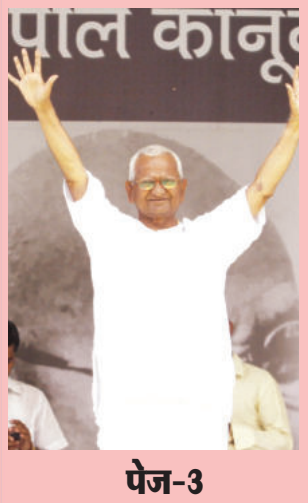

पेज-3

अन्ना, अनशन और अवाम

पेज-4

मैं भी अन्ना तू भी अन्ना

पेज-5

साई की महिमा

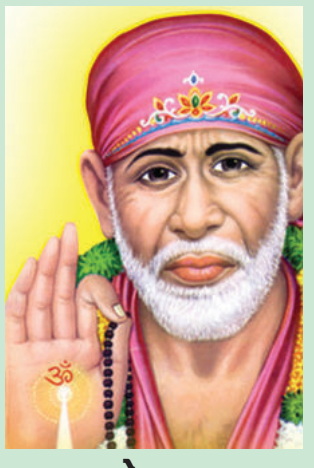

पेज-12

ऐसे ख़त्म हुआ

अन्ना का अनशन

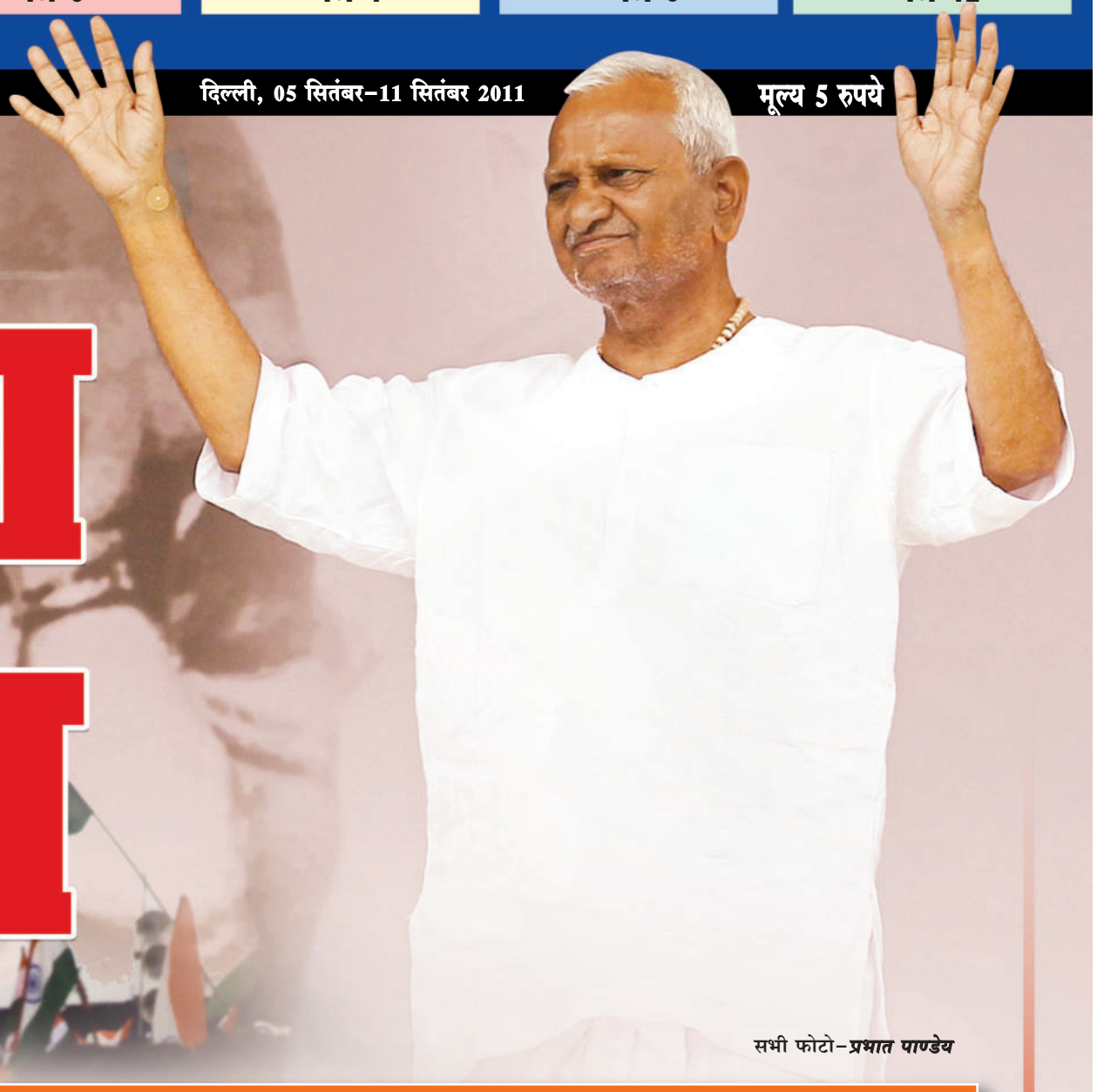

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

राजनीति बड़ी जटिल चीज है और उससे भी जटिल हैं हमारे राजनेता. ये जो सोचते हैं, वह बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं, वह कभी करते नहीं हैं. सरकार ने जन लोकपाल बिल को फिर से उलझा दिया है. टेबल थपथपा कर सांसदों और राजनीतिक दलों ने बता दिया कि प्रजातंत्र में लोकमत का कोई महत्व नहीं रह गया है. जब अनशन शुरू हुआ था, तब भी लोकपाल बिल स्थायी समिति के पास था और आज भी स्थिति वही है. अन्ना का अनशन ख़त्म हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गया. जब वह अनशन पर बैठे, तब उन्होंने यह ऐलान किया था कि जब तक संसद से जन लोकपाल बिल पास नहीं होगा, तब तक वह अनशन और धरना करते रहेंगे. टीम अन्ना और सरकार के मंत्रियों के बीच अनशन के दौरान क्या-क्या बातचीत हुई, किसने क्या वायदे किए और किसने विश्वासघात किया? अन्ना के अनशन और समझौते की पूरी कहानी बता रही है यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.

संतोष भारतीय

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने एक मंत्रिमंडलीय साथी से कहा कि अन्ना बदमाश हैं और उनके साथी बदमाशी कर रहे हैं. आम तौर पर मनमोहन सिंह इस भाषा के लिए जाने नहीं जाते, लेकिन शायद देश में चल रहे अन्ना हजारे के आंदोलन का दबाव इतना था कि वह भाषा की शालीनता भूल गए. उसी तरह, जैसे मनीष तिवारी उम्र और राजनैतिक शिष्टाचार के सामान्य नियम भूलकर अन्ना हजारे को तुम और भ्रष्टाचार में लिप्त बता बैठे. प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगी से यह भी कहा कि वह समझ नहीं पा रहे हैं, जब बातचीत में एक क़दम बात बढ़ती है तो बात बन क्यों नहीं पा रही है, तो उस सहयोगी ने कहा कि वार्ता करने वालों की टीम तो आपने ही बनाई है. इस पर प्रधानमंत्री का जवाब था कि इन लोगों ने जो कहा, मैंने वैसा कर दिया. इस सहयोगी के अनुसार, प्रधानमंत्री ख़ुद अभी परेशान हैं.

प्रधानमंत्री शायद इसलिए परेशान हैं, क्योंकि उन्हें आज भी समझ में नहीं आ रहा कि आंधी-पानी के बावजूद, एक ऐसे आदमी के साथ, जिसके पास न पैसा है और न संगठन, कैसे सारा देश खड़ा हो गया. देश के हर हिस्से में हर वर्ग के लोग, हर जाति और धर्म से रिश्ता रखने वाले लोग, हर उम्र के लोग, बच्चों से लेकर बूढ़े तक भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई में अन्ना हजारे के साथ खड़े हो गए, मानों ख़ुद अन्ना हजारे हों. नारा लगना शुरू हो गया, मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना. जो बाज़ार में जुलूस नहीं निकाल सकते, वे अपने मुहल्लों में जुलूस निकालने लगे. औरतें-बच्चे प्रभात फेरी निकालने लगे.

प्रधानमंत्री के पास कोई राजनैतिक कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाता. उनकी आंख का काम उनका गृह मंत्रालय करता है. जब चौदह अगस्त को कैबिनेट की एक समिति में प्रधानमंत्री ने जानना चाहा कि यदि सोलह अगस्त से अन्ना अनशन करते हैं तो क्या होगा, तो गृहमंत्री चिदंबरम का कहना था कि पांच सौ से पांच हज़ार तक मुश्किल से लोग आएंगे. इस पर दूसरे कैबिनेट मंत्री कमल नाथ ने कहा कि आप तो रामदेव के समय भी यही कह रहे थे, लेकिन बीस हज़ार आ गए. पर रामदेव के आंदोलन को कुचलने के गुमान में डूबे गृहमंत्री ने कहा कि उनके पास आई बी है, जिसने उन्हें ख़बर दी है.

अगर ऐसी आई बी, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो इस बात का आकलन नहीं कर पाई कि अन्ना हजारे के साथ देश के आम आदमी की भावना जुड़ गई है और वह इस लड़ाई को लड़ने निकल पड़ेगा, तो आई बी को सुधारने की ज़रूरत है. वैसे इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इस आंदोलन में हर स्तर के अधिकारियों के परिवार वाले या उनके नज़दीकी सक्रिय रूप से शामिल हैं. मुझसे एक केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव ने बताया कि वह रामलीला मैदान में अन्ना के आंदोलन को देखने गया तो वह इतना प्रभावित हो गया कि उसने अपनी बेटी के नाम पर पांच हज़ार एक रुपये की रसीद कटवा ली और

अपना समर्थन इस आंदोलन को दे दिया. रामलीला मैदान में तीस से चालीस हज़ार आदमी-औरतें हमेशा डटे रहे. उनके खाने-पीने के लिए सामान देने में दिल्ली वालों में होड़ मच गई. आलू, आटा, केला, जूस, मिठाई, जिसके जो वश में था, लेकर वहां पहुंच गया. अन्ना की रसोई खुल गई. कोई भूखा न रहा. ज़बरदस्ती सामान की मदद देने वाले दिल्ली के बाहर से भी आने लगे.

जिस गांधी टोपी को कांग्रेस और पूरी राजनैतिक बिरादरी ने दफ़न कर दिया था और जो सिर्फ़ कांग्रेस सेवा दल के आधिकारिक समारोहों की औपचारिकता रह गई थी, उसे अन्ना के आंदोलन ने भ्रष्टाचार की लड़ाई का प्रतीक बना दिया. बच्चे, बूढ़े और जवान सारे देश में इस टोपी को पहने नज़र आने लगे. आज़ादी के बाद का राष्ट्रीय ध्वज आज़ादी की लड़ाई के तिरंगे के स्वरूप में लोगों के हाथ में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई का मुख्य हथियार बन गया. लोगों से कटी सरकार और विपक्ष यह समझ ही नहीं पाए कि अन्ना की लड़ाई में लोग कैसे और क्यों शामिल हो गए.

इसीलिए विपक्ष शुरू में ख़ामोश रहा और उसे लगा कि इसे कांग्रेस के राजनैतिक नुक़सान में बदलने देना चाहिए, जिसका फ़ायदा उसे ही मिलेगा. जब सोलह अगस्त को अन्ना को उनके साथियों के साथ गिरफ़्तार किया गया तो संपूर्ण विपक्ष की एक ही प्रतिक्रिया थी कि अन्ना को ग़लत गिरफ़्तार किया गया है. उन्हें अनशन करने देना चाहिए था. तीन दिनों के बाद लोग अपने आप घरों में वापस चले जाते. उन्होंने अन्ना को सलाह दी कि उन्हें संसदीय मर्यादा और तंत्र का सम्मान करना चाहिए. दरअसल उन्हें लग रहा था कि अन्ना की भाषा राजनैतिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ एक बग़ावत है, जिसमें कांग्रेस के साथ वे भी लपेट में आ जाएंगे.

चौदह अगस्त से अन्ना से निपटने की कमान कपिल सिब्बल और चिदंबरम के हाथ में थी. दोनों बड़े वकील हैं. दोनों की भाषा महान है. दोनों को लगता है कि हथियार बंद आंदोलन भी उनका दुश्मन है और अहिंसक आंदोलन भी उनका दुश्मन है. पहले नक्सलवादियों को सेना द्वारा गोलियों से भुनवाने की घोषणा करने वाले गृहमंत्री अचानक ख़ामोश हो गए. सोलह अगस्त को एक तरफ़ अन्ना को गिरफ़्तार किया गया तो दूसरी तरफ़ कपिल सिब्बल, चिदंबरम और अंबिका सोनी ने एक प्रेस कांफ्रेंस की. इस प्रेस कांफ्रेंस को सारे देश ने देखा और देश को लगा कि ये उसके मंत्रियों जैसी प्रेस कांफ्रेंस नहीं है. यह तो घमंड में डूबी सरकार का भ्रष्टाचार के समर्थन में किया गया शंखनाद है.

कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम बड़े वकील हैं. सुप्रीम कोर्ट में इनके साथियों का कहना है कि ये दोनों मंत्री बनने से पहले एक क्लाइंट से एक पेशी पर जाने का चार से पांच लाख रुपया लेते थे, भले जज आकर अगली तारीख़ दे दे. इनके संपर्क में आज भी वे ही हैं, जो एक पेशी पर पांच लाख रुपये देने की हैसियत रखते हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, कांग्रेस सांसद भी दोनों से नहीं मिल सकते. इसीलिए दोनों को देश की जनता का आंदोलन करना

(शेष पृष्ठ 2 पर)

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें फिजूलख़र्ची पर ध्यान देने की हिदायत दी गई है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

कैसे घटेगा सरकारी ख़र्च

वित्त मंत्री प्रणब दा इन दिनों खासे परेशान हैं. उनकी परेशानी की वजह विपक्षी दल नहीं, बल्कि बढ़ रहा सरकारी खर्च है. उन्होंने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें फिजूलखर्ची पर ध्यान देने की हिदायत दी गई है. वर्ष 2008–09 की वार्षिक खर्च समीक्षा की तुलना में मौजूदा चालू वित्तीय वर्ष ज़्यादा खर्चीला साबित हो रहा है, लेकिन यह अब तक साफ नहीं हुआ है कि इस संदर्भ में मंत्रालयों एवं मंत्रियों की कार्यशैली और कार्यक्षमता की समीक्षा होगी या नहीं. सूत्रों के मुताबिक, सरकार को यह पता चल गया है कि विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा करना एक बेहद खर्चीला काम है. इसके लिए होने वाली बैठकों और टास्क फोर्स बनाने में लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं. सरकार ने इस काम के लिए कैबिनेट सचिवालय के भीतर ही एक विभाग बनाया है, जो मंत्रालयों की समीक्षा करने का काम करता है. अब इस बात पर निगाहें टिकी हैं कि क्या वित्तीय घाटे से उबरने के लिए प्रणब मुखर्जी द्वारा किए जा रहे उपायों का प्रभाव विभिन्न विभागों पर पड़ता है या नहीं.

बाबुओं में काम करने की चाहत

महाराष्ट्र में बाबुओं के ढेर सारे पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार इन पदों को भरने के मामले में कछुआ चाल चल रही है. सूत्रों की मानें तो सरकारी महकमों की हालत ऐसी हो गई है कि बाबुओं को नए काम के लिए औसतन एक से तीन महीनों का इंतज़ार करना पड़ता है. 1976 बैच के आईएएस अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव जे एस साहनी को भी एक महीने से नए काम का इंतज़ार है. उसी तरह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी एवं पुणे नगर निगम के पूर्व आयुक्त महेश जागड़े अपने वर्तमान पद से सात जून को हटने के बाद से अभी तक नया कम मिलने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव राधेश्याम मोपालवर को भी इसी साल जून महीने से अपनी अगली नियुक्ति का इंतज़ार है. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही का अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है, जबकि वह खुद स्वीकार कर चुकी है कि राज्य में 50 वरिष्ठ पद खाली पड़े हैं.

दूषित ट्रैक रिकॉर्ड

भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे देशव्यापी जनांदोलन के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने संसद में एक बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा भी भ्रष्टाचार से ही जुड़ा है. पीएमओ ने बताया कि वर्ष 2008 से अब तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत लेने के आरोप में केंद्र सरकार के 955 बाबुओं को गिरफ्तार किया है. दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में रेल विभाग पहले पायदान पर है, जिसके 156 बाबू सीबीआई के शिकंजे में फंसे. इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राजस्व एवं सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं. हालांकि बाबूशाही पर नज़र रखने वालों का अभी भी मानना है कि यह आंकड़ा अधूरा है, क्योंकि कई ऐसे भ्रष्ट विभाग और अधिकारी हैं, जिन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है. इन आंकड़ों में दर्ज सारे मामले ऐसे हैं, जिनकी जांच सीबीआई ने की है और कई लोगों का मानना है कि जब सीबीआई खुद निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर पाती है तो ऐसे में इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर कितना भरोसा किया जा सकता है.

dilipcherian@gmail..com

ऐसे ख़त्म हुआ अन्ना का अनशन

पृष्ठ एक का शेष

और अन्ना का समर्थन करना अपने ख़िलाफ़ बग़ावत लगा. इनके टीवी पर आते ही लोग टीवी बंद करने लगे, क्योंकि उन्हें इनकी बॉडी लैंग्वेज अब अपने प्रतिनिधि या राजनेता जैसी नहीं लगती.

तिहाड़ जेल में बंद अन्ना और तिहाड़ के बाहर हज़ारों लोग अन्ना के समर्थन में. सारे देश में लोग अन्ना के समर्थन में लामबंद होने लगे. सोलह अगस्त की शाम सरकार को समझ में आया कि उससे ग़लती हुई. अब अन्ना ने जेल से निकलने से इंकार कर दिया. लेकिन सरकार को चार दिनों बाद समझ में आया कि चिदंबरम और कपिल सिब्बल को सामने से हटा लेना चाहिए. कपिल सिब्बल के बयानों ने देश में अन्ना के समर्थन में और लोगों को खड़ा कर दिया. सरकार ने सलमान ख़ुर्शीद को सामने किया. सलमान ख़ुर्शीद की ज़िम्मेदारी थी कि पर्दे के पीछे होने वाले फ़ैसलों को वह जनता के सामने रखें. सलमान ख़ुर्शीद का चेहरा और भाषा सौम्य हैं, पर समस्या का कोई हल इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था. सरकार चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी अनशन टूटे, क्योंकि उसे मीडिया से पता चल रहा था कि हर बीता दिन अन्ना का समर्थन बढ़ा रहा है.

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से बाहर हाथ–पांव मारने शुरू कर दिए. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि भैय्यू जी महाराज को बुलाकर अन्ना से बात की जाए. केंद्रीय मंत्री एस एम कृष्णा ने श्री श्री रविशंकर को बुलाने का सुझाव दिया. प्रधानमंत्री ने दोनों को बुला लिया, पर दोनों को एक–दूसरे के बारे में नहीं बताया. भैय्यू जी महाराज राष्ट्रसंत कहे जाते हैं और लगभग हर महाराष्ट्रियन नेता के गुरु भी हैं और सहोदर भी. अन्ना हजारे से भी उनके अंतरंग संबंध हैं. दिल्ली आते ही वह पहले सलमान ख़ुर्शीद से, फिर प्रधानमंत्री से और बाद में अन्ना हजारे से मिले. अब तक अन्ना हजारे मंच पर ही सबसे मिलते रहे हैं, पर वह भैय्यू जी महाराज से बंद टैंट में एक घंटे तक मिले. उनके हाथ में एक काग़ज़ था. अन्ना ने उस काग़ज़ को पढ़ा तथा भैय्यू जी महाराज की व्यक्तिगत गारंटी पर वह उस पर दस्तख़त करने को तैयार हो गए. उन्होंने पेन भी निकाल लिया, लेकिन उसी समय टैंट में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया. उसे देखते ही अन्ना बिफर से गए. यह थे महाराष्ट्र के अतिरिक्त गृह सचिव सारंगी. सारंगी को किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन उन्हें लगा कि वह यदि बातचीत में अपना चेहरा दिखाएं तो उन्हें प्रशंसा मिल सकती है. अन्ना ने भैय्यू जी से कहा कि वह बाद में बात करेंगे. वह काग़ज़ अन्ना के पास रह गया, जिसे अरविंद केजरीवाल ने बाद में देखा और अस्वीकार कर दिया. इन सबने अन्ना को बताया कि यह सरकार का धोखा है.

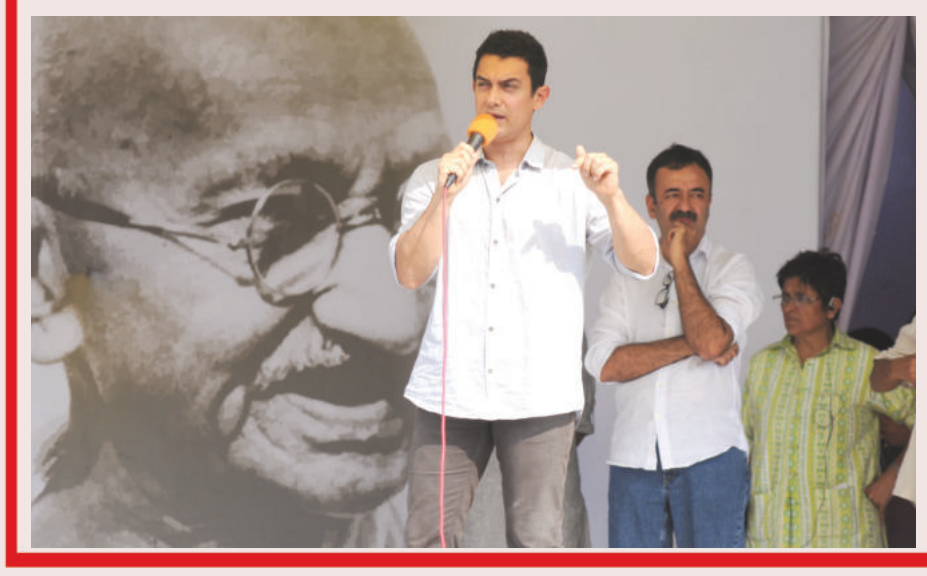

दूसरी तरफ़ श्री श्री रविशंकर मंच पर कई बार आकर अन्ना से मिले और नीचे उतर कर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वह समझौता करा देंगे और यह कि उनके पास अच्छी ख़बर है, लेकिन यह अच्छी ख़बर कभी सच्चाई में बदल ही नहीं पाई. अन्ना का अनशन कौन संत समाप्त कराए, यह भी प्रतिस्पर्धा का विषय बन गया. श्री श्री के पास प्रधानमंत्री और आडवाणी थे तो भैय्यू जी के पास प्रधानमंत्री और गडकरी थे. भैय्यू जी के पास एक अतिरिक्त पत्ता था और वह थे स्वयं अन्ना हजारे.

अचानक भैय्यू जी भी नेपथ्य में चले गए और सलमान ख़ुर्शीद तथा संदीप दीक्षित सामने आ गए. प्रधानमंत्री ने हर उस आदमी से समाधान निकालने के लिए कह दिया, जिसने उनसे कहा कि वह समाधान निकाल सकता है. अजीब–अजीब प्रस्ताव आए. कोशिश यह हो रही थी कि किसी तरह अन्ना अनशन समाप्त करें, बाक़ी बातें होती रहेंगी. इसी बीच सरकार ने अरुणा राय को आगे कर नया दांव खेला. अरुणा राय ने एक अलग लोकपाल का बिल बनाया. अरुणा राय राजस्थान में स्वयंसेवी संगठन चलाती हैं तथा सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष करने वालों में एक हैं. इन दिनों वह सोनिया गांधी की सलाहकार समिति में हैं. अरुणा राय हर टेलीविज़न चैनल पर आईं, विशेषकर अंग्रेजी चैनलों पर और उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि अन्ना का आंदोलन और उनका बिल ख़तरनाक और अलोकतांत्रिक है.

जब हम और तह में गए तो पता चला कि अरुणा राय ने उन एनजीओ का नेतृत्व संभाल लिया है, जो बड़े आंदोलन में विश्वास इसलिए नहीं करते, क्योंकि उन्हें आज तक बड़ा आंदोलन खड़ा करने में सफलता मिली ही नहीं. वे छोटे–छोटे आंदोलन कर विदेशी पैसों से संगठन चलाते हैं. उन्हें लगता है कि उनकी कमीज़ से अन्ना की कमीज़ ज़्यादा सफ़ेद कैसे है. बहुत से स्वयंसेवी संगठनों को लगा कि आगे उनसे सवाल होंगे कि क्यों वे बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं. इन सबने मिलकर अरुणा राय के नेतृत्व में अन्ना की शैली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए. उनकी यह हरकत ऐसी थी, जैसे कोई पड़ोसी का अपशकुन करने के लिए अपनी आंख फोड़ ले. लोगों ने अरुणा राय की बात सुनने से इंकार कर दिया. देश में कोई जगह ऐसी नहीं थी, जहां अन्ना हजारे के पक्ष में माहौल न बना हो और नारे नहीं लग रहे हों. एक और कोशिश हुई. कुछ मुस्लिम नेताओं और दलित नेताओं ने सवाल उठाए कि यह आंदोलन उनके हित में नहीं है और यह मध्य वर्ग का आंदोलन है. देश के मुसलमानों और दलितों ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और वे बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चल

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

रहे इस आंदोलन में शामिल हो गए. जिस तरह सरकार ने और विपक्षी दलों ने अन्ना हजारे को लेकर चालें चलीं, उनसे पहले श्री श्री निराश हुए और बाद में भैय्यू जी. दोनों को यह भी लगा कि अन्ना के कुछ साथी, विशेषकर अरविंद केजरीवाल समझौता नहीं होने देना चाहते. भैय्यू जी महाराज ने कोशिशें जारी रखीं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को समझाना चाहा कि अन्ना की ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. पर ख़ुद अन्ना ने कहा कि उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके मुद्दे हैं, खासकर वे मुद्दे, जिनसे आम जनता का नाता है.

कांग्रेस और उसकी सरकार ने सारे मामले को ग़ैर ज़िम्मेदारी के साथ, टालने वाले अंदाज़ में लिया, वहीं भाजपा ने अन्ना का पहले चरण में विरोध किया, लेकिन जब अन्ना ने सांसदों को घेरने का आह्वान किया और देश भर में सांसदों को घेरा जाने लगा तो भाजपा दसवें दिन इस नतीजे पर पहुंची कि उसे अन्ना का समर्थन करना चाहिए, ताकि कांग्रेस के ख़िलाफ़ पैदा हुए गुस्से का उसे राजनीतिक फ़ायदा मिल सके. उसने यू टर्न लिया और अन्ना के लोगों के पास संदेश भेजा कि वे लोग उससे मिलें तो वह समर्थन कर देगी. संयोग से उसी दिन सलमान ख़ुर्शीद के साथ बातचीत में प्रशांत भूषण एवं केजरीवाल को लगा कि वे पांच अप्रैल की स्थिति में पहुंच गए हैं. उन्होंने भाजपा नेताओं से मिलने का फ़ैसला लिया. भाजपा नेताओं ने उनका समर्थन कर दिया. अब कांग्रेस को लगा कि वह ट्रैप हो रही है.

कांग्रेस ने फिर भैय्यू जी महाराज को बीच में डाला और उनसे कहा कि वह अन्ना हजारे को तैयार करें. भैय्यू जी ने सलमान ख़ुर्शीद, कपिल सिब्बल और प्रधानमंत्री से मिलकर मांगें तैयार कीं. उधर केजरीवाल को लगा कि कांग्रेस को ही फ़ैसला लेना है और उन्हें कुछ संकेत देना चाहिए. वह पहले भैय्यू जी महाराज से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब मिलने के लिए तैयार हो गए. कांग्रेस ने पतंग को थोड़ी ढील और दी. लोकसभा में चर्चा को टाला. शुक्रवार की रात और शनिवार की सुबह सलमान ख़ुर्शीद से भैय्यू जी महाराज, प्रशांत भूषण, केजरीवाल एवं मेधा पाटेकर मिले. अब मांग सिर्फ़ इतनी बची थी कि लोकसभा में चर्चा हो और लोकसभा आश्वासन दे.

शनिवार को लोकसभा की बैठक शुरू हुई, जिसमें उस पर पहला दबाव था अन्ना हजारे के अनशन का और दूसरा दबाव था अन्ना की उस घोषणा का कि अगर शनिवार तक फ़ैसला नहीं हुआ तो देश भर से लोग दिल्ली की ओर कूच करें. दिल्ली आने का अन्ना का आह्वान लोकसभा भंग करने के आंदोलन में भी बदल सकता था. इस सारी बहस और आंदोलन के बीच सोनिया गांधी अमेरिका में अपने कैंसर का इलाज करा रही हैं. कैंसर फैल चुका है. सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में पार्टी और सरकार बिखरी दिखाई दी. राहुल गांधी से जिस परिपक्वता की अपेक्षा थी, वह दिखाई नहीं दी. ऐसे समय में, जब संकट हो, तब आवश्यकता होती है नेतृत्व की. राहुल गांधी के पास नेतृत्व देने का वक़्त नहीं है. उनके लिए यह सुनहरा मौक़ा था, जब वह सामने आ सकते थे और देश के सामने अपना दावा ठोंक सकते थे. उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया, जिसका सारांश था कि उन्होंने मसले को और उलझा दिया. इसीलिए लोकसभा की बहस में किसी ने उनके सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया.

देश के मीडिया ने, जिसमें अंग्रेजी न्यूज़ चैनल आते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करने की पूरी कोशिश की. उन्होंने इस बात को फैलाया कि यह आंदोलन मध्य वर्ग का आंदोलन है, जबकि हिंदी न्यूज़ चैनलों ने अपने को अन्ना के आंदोलन का एक हिस्सा बना दिया. सरकार के लिए यही चिंता की बात रही कि वह हिंदी न्यूज़ चैनलों को अन्ना से दूर करने में सफलता हासिल नहीं कर पाई. जिस तरह जनता का दबाव कांग्रेस, भाजपा, अन्य राजनैतिक दलों तथा संसद पर पड़ा, उसी तरह इस दबाव ने हिंदी चैनलों को भी मजबूर कर दिया. अधिकांश हिंदी चैनलों ने मुंबई से अपने वरिष्ठ संवाददाताओं को दिल्ली बुला लिया, ताकि उन्हें अन्ना हजारे से संपर्क करने में आसानी रहे. पर सबसे ज़्यादा रोल जनता का रहा, जिसमें अस्सी प्रतिशत भागीदारी नौजवानों की रही. नौजवानों ने जिस शांति के साथ, संयम के साथ अन्ना के आंदोलन का साथ दिया, वह बेमिसाल है. न झगड़ा, न झंझट, न लूट और न खसोट. यही नेताओं पर दबाव का सबसे कारगर हथियार बना. सरकार और राजनैतिक दलों के लिए एक और ख़तरा था. अगर वे शांतिपूर्ण आंदोलन की बात नहीं सुनते तो उन्हें नक्सलवाद को तर्क देने का अपराधी माना जाता. इस आंदोलन की सुनवाई न होने का दुष्परिणाम बड़ी संख्या में नौजवानों को नक्सलवाद के साथ जोड़ देता. अन्ना का आंदोलन देश में एक विश्वास जगा गया कि लोगों में भी ताक़त होती है. यह साबित कर गया कि नौजवानों में देश के लिए प्यार है तथा वे भी देश की समस्याओं के प्रति चिंतित हैं.

अन्ना का अनशन ख़त्म हो गया. अन्ना की तबीयत बिगड़ रही थी, शायद इसलिए टीम अन्ना सरकार के जाल में फंस गई. यह आंदोलन पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए चुनौती बनकर सामने आया. देश की जनता भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए अन्ना के साथ खड़ी हो गई. सभी राजनीतिक दलों ने इस जनसैलाब की भावनाओं को समझने में न सिर्फ़ ग़लती की, बल्कि उन्होंने अपनी साख को भी खो दिया. राजनीतिक चालबाजी से अनशन ख़त्म तो हो गया, लेकिन देश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है. अन्ना ने जन लोकपाल बिल को क़ानून बनाने के लिए आंदोलन किया था, लेकिन तेरह दिनों के आंदोलन के बाद यह तीन सुझावों तक सिमट कर रह गया. जन लोकपाल बिल संसद में न तो पेश किया गया और न ही इसे पास किया गया. अन्ना के तीन सुझावों पर सिर्फ़ बहस हुई और इसे स्थायी समिति में भेज दिया गया. समझने वाली बात यह है कि स्थायी समिति सरकारी लोकपाल बिल पर विचार कर रही है. अन्ना के तीनों सुझावों को सरकारी लोकपाल बिल के लिए एक सुझाव माना जाएगा. स्थायी समिति में इन तीनों सुझावों पर फिर से चर्चा होगी. फिर यह फ़ैसला होगा कि इन सुझावों को मानना है या नहीं. यानी यह मामला पूरी तरह उसी जगह पहुंच गया, जहां यह अन्ना के अनशन से पहले था. राजनीतिक दलों का यह विश्वासघात देश को महंगा पड़ने वाला है. इससे माओवादियों को यह कहने का मौक़ा मिल जाएगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 26
दिल्ली, 05 सितंबर–11 सितंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अन्ना का अनशन

एक कहानी बेहतर मैनेजमेंट की

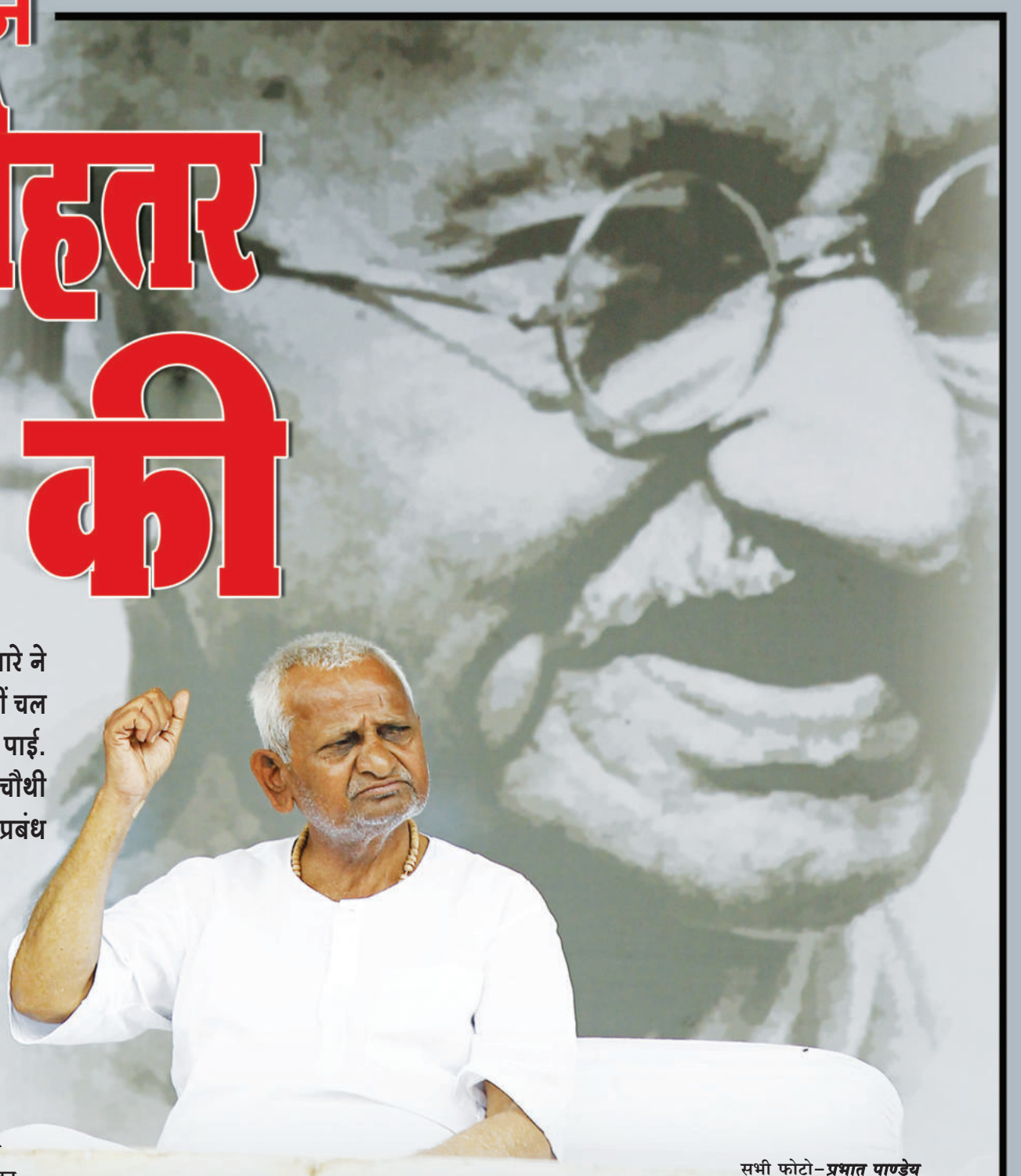

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

बाबा रामदेव दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में अनशन करने आए थे, जहां अन्ना हजारे ने अनशन किया. लेकिन ऐसी क्या बात थी कि बाबा रामदेव का अनशन एक दिन भी नहीं चल सका, जबकि अन्ना के अनशन को सरकार से लेकर पुलिस तक, चाहकर भी नहीं रोक पाई. आख़िर इन दोनों आंदोलनों के स्वरूप और संगठन में ऐसे कौन से बुनियादी फ़र्क़ थे? चौथी दुनिया अन्ना हजारे के कुछ ऐसे सहयोगियों के बारे में आपको बता रहा है, जिनके प्रबंध कौशल के बूते अन्ना हजारे का आंदोलन देशव्यापी बन गया...

शशि शेखर

ज़रा सोचिए, आख़िर एक फकीर के आंदोलन की आग इतने कम समय में पूरे देश भर में कैसे फैल गई? क्यों सरकार को बार-बार झुकना पड़ रहा है? क्यों पुलिस वालों के तेवर भी अन्ना के आंदोलन के दौरान नरम हो जाते हैं? क्यों मंत्रियों तक की बोलती बंद हो जाती है? ज़ाहिर है, एक देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए जितनी ज़रूरत जज़्बे की होती है, उतनी ही ज़रूरत संसाधनों की भी होती है. फिर संसाधन जुटाने के लिए पैसों और ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है, जो आंदोलन को सफल बनाने के लिए जी-जान से मेहनत करें. टीम अन्ना में भी कुछ ऐसे ही लोग शुरू से शामिल हैं, जो बेहतर रणनीति बना सकते हैं, जो क़ानून की हर एक बारीकियों से परिचित हैं, जो पुलिस की हर एक नब्ज़ को पहचान सकते हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट का गुर जानते हैं और जो सरकार और सिविल सोसायटी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने में भी माहिर माने जाते हैं.

अरविंद केजरीवाल

चंपारण सत्याग्रह को जब भी याद किया जाता है, तब उस एक शख्स का नाम लोग ज़रूर याद करते हैं, जिसने अपने आग्रह के ज़रिए मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण आने के लिए मजबूर किया था. उस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल. आज एक बार फिर वही किरदार है, सिर्फ़ नाम बदल गए हैं. अन्ना अगर दूसरे गांधी हैं तो अरविंद केजरीवाल दूसरे राजकुमार शुक्ल. दरअसल, सूचना अधिकार क़ानून पर काम करने वाले अरविंद केजरीवाल 2008 से ही यह महसूस कर रहे थे कि अब सिर्फ़ सूचना के अधिकार से काम नहीं चलने वाला. इसलिए उन्होंने दिल्ली में स्वराज (लोकल सेल्फ गवर्नेंस) अभियान की शुरुआत की. दिल्ली के कुछ इलाक़ों में समर्थन भी मिला, लेकिन एक बार फिर अरविंद को यह लगा कि इस अभियान से जनता को भारी संख्या में जोड़ पाना मुश्किल हो रहा है और यह भी बात सामने आई कि जब तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तब तक किसी भी अभियान या आंदोलन का सफल होना आसान नहीं है. नतीजतन, 2010 से ही अरविंद ने जन लोकपाल बिल पर काम करना शुरू कर दिया. इस दौरान वह क़ानून के जानकारों से मिलते रहे, उनकी सलाह लेते रहे और उन्होंने जन लोकपाल बिल के निर्माण में शांति भूषण, प्रशांत भूषण और संतोष हेगड़े जैसे लोगों को जोड़ा. लगभग साल भर की मेहनत के बाद जनवरी 2011 में रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले जन लोकपाल की मांग को लेकर पहली बार रैली हुई. फिर वहां शुरू हुआ काफिला पूरे देश भर में घूमा और अब 8 महीने बाद फिर रामलीला मैदान पहुंच गया और इस बार अरविंद के साथ अन्ना थे. दरअसल, अरविंद ने इस बीच अन्ना को जन लोकपाल मुद्दे के बारे में बताया, उन्हें यह समझाया कि कैसे यह क़ानून इस देश की तकदीर बदल सकता है. अरविंद 1992 में आईआरएस बने थे, लेकिन अपने ही विभाग के भ्रष्टाचार को देखते हुए उन्होंने जनवरी 2000 में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने के लिए परिवर्तन नामक एक संस्था का गठन किया. रेमन मैगसेसे अवॉर्ड मिलने के बाद उन्होंने पीसीआरएफ नामक संस्था बनाई, जहां से नेशनल आरटीआई अवॉर्ड की शुरुआत हुई और आरटीआई को बचाने की लड़ाई भी. अरविंद केजरीवाल को सरकारी नीतियां और उनकी कमज़ोरियां बख़ूबी पता हैं. उन्हें यह मालूम है कि कहां, कैसे और कब वार करना है. जब पूरे देश में सीडब्लूजी, 2-जी और आदर्श की गूंज थी, तभी उन्होंने जन लोकपाल और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई का शंखनाद किया और भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी जनता इस आंदोलन में कूद पड़ी.

प्रशांत भूषण

देश के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण को जितनी अच्छी समझ क़ानून की है, उतनी ही अच्छी समझ भ्रष्टचार से जुड़े मुद्दों की भी है. उन्हें मालूम है कि किस मुद्दे को कैसे उछालना है. राडिया टेप कांड को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ले जाने में भी उनका खासा योगदान है. इसके अलावा वह लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर जनहित याचिका भी डालते रहते हैं. प्रशांत भी अन्ना टीम के एक अहम सदस्य हैं. प्रशांत नर्मदा बचाओ आंदोलन के क़ानूनी पक्षों से जुड़े रहे हैं और देश भर में फैले ऐसे कई आंदोलनों को क़ानूनी जानकारी के माध्यम से सहायता देते रहे हैं. साथ ही वह सरकार से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद भी रहते हैं. इस तरह टीम अन्ना के सदस्य के रूप में प्रशांत भूषण न सिर्फ़ ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी में शामिल हुए, बल्कि अपने ऊंचे संबंधों का फ़ायदा भी इस आंदोलन को दिला रहे हैं.

अन्ना की रसोई

रामलीला मैदान में आने वाले आंदोलनकारियों के लिए पानी, जूस, फल से लेकर खाने तक की व्यवस्था की गई. विभिन्न संगठनों की ओर से यहां अन्ना की रसोई नाम से भंडारा चलाया गया. दूरदराज से आए आंदोलनकारी जब थक जाते या जब उन्हें भूख सताती, तब इस रसोई में जाकर वे चावल-कढ़ी, चावल-राजमा, पूड़ी-सब्जी से पहले अपनी भूख मिटाते और फिर नई ऊर्जा के साथ आंदोलन में जुट जाते. ऐसा नहीं है कि अन्ना की रसोई को चलाने के लिए आयोजकों को अपनी तरफ से खर्च करना पड़ा हो. दरअसल, यहां आने वाले लोग अपनी तरफ से ही तेल, घी, आटा एवं चावल की बोरियां पहुंचा दिया करते थे. अन्ना की रसोई के अलावा भी कई लोग व्यक्तिगत रूप से इस काम में सहायता करते नज़र आए. मसलन, कई लोग जब रामलीला मैदान पहुंचते तो उनकी गाड़ियों में केले भरे होते थे, जिन्हें सड़क पर ही आने-जाने वाले आंदोलनकारियों के बीच बांट दिया जाता था. कोई पानी की बोतलें और थैलियां बांटता नज़र आया तो कोई मीडिया वालों को जूस पिलाकर इस आंदोलन में अपना योगदान कर रहा था. इसके अलावा सैकड़ों युवा भी दिन-रात एक करके अन्ना के आंदोलन को सफल बनाने में जुटे हुए थे. रामलीला मैदान में मंच से लेकर मैदान के हर कोने तक फैले ये कार्यकर्ता लोगों को पानी पिलाने से लेकर साफ-सफाई का भी काम करते दिखे.

शांति भूषण

जनता पार्टी की सरकार में शांति भूषण को क़ानून मंत्री बनाया गया था. शायद कम ही लोगों को यह बात मालूम होगी कि शांति भूषण ही वह शख्स हैं, जिनकी वजह से इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया था. दरअसल, राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी मामले में शांति भूषण ने राज नारायण की ओर से मुक़दमा लड़ा था. इंदिरा गांधी ने इसी हार के बाद देश में आपातकाल लगाया था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है. एक बार फिर शांति भूषण के लिए सारी स्थितियां इतिहास की पुनरावृत्ति होने जैसी हैं. टीम अन्ना की ओर से शांति भूषण ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी के को-चेयरमैन बने. न्यायिक सुधार के प्रमुख पैरोकार शांति भूषण की सलाह पर ही जन लोकपाल के दायरे में न्यायपालिका को शामिल करने का निर्णय लिया गया.

किरण बेदी

किरण बेदी को भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है. दिल्ली पुलिस में रहते हुए उन्होंने जो अनुभव हासिल किए या पुलिस वालों के बीच अपनी जो छवि बनाई, आज उनका सीधा-सीधा फ़ायदा अन्ना के आंदोलन को मिलता दिख रहा है. जब अन्ना को तिहाड़ ले जाया गया, तब किरण बेदी जिस ढंग से इस पूरे मामले में सामने आईं, वह दरअसल यही बता रहा था कि आज भी तिहाड़ जेल के अधिकारियों के बीच किरण बेदी किसी नायक से कम नहीं हैं. या फिर जब वह जनता की भारी भीड़ के बीच पुलिस वालों को निर्देश देती हैं, तब शायद ही कोई पुलिस वाला ऐसा हो, जो उस निर्देश को न मानता हो. अन्ना की गिरफ्तारी के बाद भी किरण बेदी लगातार यह कहती रहीं कि इसमें दिल्ली पुलिस की कोई गलती नहीं है और न इसमें दिल्ली पुलिस का कोई दिमाग़ है, बल्कि वह सिर्फ़ ऊपर का आदेश मान रही है. उसी दिन यह बात सच भी साबित हो गई. ज़ाहिर है, दिल्ली पुलिस को जितना अच्छा किरण बेदी समझती हैं, उसका भी फ़ायदा अन्ना के आंदोलन को मिल रहा है.

मनीष सिसौदिया

मनीष सिसौदिया वैसे तो शुरू से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ कर काम करते रहे हैं, लेकिन उनकी एक पहचान पत्रकार के तौर पर भी रही है. मीडिया में अपने संबंधों का फ़ायदा वह इस आंदोलन को भी दिला रहे हैं.

shashishekhar@chauthiduniya.com

अन्ना, अनशन और अवाम

अभिषेक रंजन सिंह

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) के समीप अचानक एक ऑटो रिक्शा वहां खड़े कुछ लोगों के पास आकर रुका. ऑटो चालक ने उनसे पूछा, क्या रामलीला मैदान जाएंगे? वहां मौजूद लोगों ने आश्चर्य भरे लहज़े में कहा, हां जाना तो है, लेकिन कितने पैसे लोगे? इस पर ऑटो चालक बोला, साहब, कमाना-खाना तो रोज है, लेकिन अन्ना जी की मुहिम में हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए. यह सुनते ही चार-पांच लोग मुस्कराते हुए उसके ऑटो में जा बैठे. ऑटो रिक्शा वाला हो, कैब वाला हो या निजी कार मालिक, सभी अन्ना के आंदोलन में लोगों की मदद करते नज़र आ रहे थे. इसके पीछे उनका सिर्फ़ यही मक़सद था कि अधिक से अधिक लोग रामलीला मैदान में एकत्र हों, ताकि सरकार पर दबाव बन सके. अमूमन चालान और ट्रैफिक पुलिस से खौफ़ खाने वाले मोटरसाइकिल सवार और ऑटो चालक अन्ना के आंदोलन के दौरान पूरी तरह बेफिक्र नज़र आए. दिल्ली की सड़कों पर अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हों तो पुलिस की निगाह से बच नहीं सकते, लेकिन अन्ना के आंदोलन में युवाओं ने हेलमेट की अनिवार्यता को भी नज़रअंदाज़ कर दिया. हालांकि क़ानून और सुरक्षा के मद्देनज़र यह ग़लत था, लेकिन दिल्ली पुलिस भी सब कुछ जानते-समझते हुए अन्ना के समर्थकों की इस हरकत को नज़रअंदाज़ कर रही थी. यही वजह थी कि रैली में शामिल नौजवान पुलिस को देखकर नारा लगाते थे, यह अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है. यह सुनकर दिल्ली पुलिस के जवान भी अपनी मुस्कराहट रोक नहीं पाते थे.

अन्ना हजारे को युवाओं, किसानों, मज़दूरों, महिलाओं, बूढ़ों और बच्चों यानी हर वर्ग का ज़बरदस्त समर्थन मिला. स्कूल-कॉलेज, खेत-खलिहान और दफ्तर को छोड़कर ये सभी लोग बदलाव का एक सपना लिए ऐतिहासिक रामलीला मैदान पहुंचे. लोगों ने नए-नए नारों, रोचक तस्वीर एवं संदेश वाले बैनरों, टी-शर्ट्स और टोपियों के साथ भागीदारी करके आंदोलन में जोश भर दिया. ढोल-नगाड़ों के साथ देश भक्ति के गीत गाकर उन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर वे देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं. अन्ना के आंदोलन को समर्थन देने आए लोगों में एक बड़ी संख्या उन युवाओं की थी, जिन्हें अभी तक केवल फेसबुक एवं ट्विटर केशौक़, ब्रांडेड कपड़े ख़रीदने, महंगे रेस्तरां में खाने, मौजमस्ती करने और अक्सर बड़ों की डांट-फटकार सुनने के लिए जाना जाता था. उसी युवा पीढ़ी ने अन्ना के आंदोलन में अपनी भागीदारी के ज़रिए यह संदेश दिया कि बेशक, उसके जीने का अंदाज़ अलग है, बावजूद इसके उसे इस बात का एहसास है कि देश का भविष्य उसके कंधों पर टिका हुआ है. यह अलग बात है कि आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी के तौर-तरीक़े अन्य लोगों से भिन्न रहे. मसलन वे अपने दोस्तों को इस आंदोलन से जुड़ने की गुज़ारिश फेसबुक और एसएमएस से करते थे. विरोध प्रदर्शन में जहां वे जमकर नारे लगा रहे थे, वहीं अपने स्मार्ट फोन की मदद से प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें अपलोड कर रहे थे. इस दौरान थकान और प्यास लगने पर वे कोल्ड ड्रिंक्स से अपनी प्यास भी बुझाते थे और फिर वापस उसी जोश-ओ-ख़रोश के साथ नारे बुलंद करने लगते थे. चौथी दुनिया ने जब रामलीला मैदान में देश के दूरदराज़ के इलाक़ों से आए लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की वजह पूछी तो इस बारे में सबकी राय अलग-अलग थी. बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िला अंतर्गत चकिया तहसील के मूल निवासी और दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर धीरज गौतम ने बताया कि मैंने न तो 1947 की आज़ादी की लड़ाई देखी और न 1975 का जेपी आंदोलन, लेकिन इतना ज़रूर है कि जन लोकपाल विधेयक की ख़ातिर अन्ना हज़ारे का संघर्ष देखकर मैं कह सकता हूं कि उस जमाने में हुए आंदोलन की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही रही होगी. धीरज ने कहा कि भ्रष्टाचार भारत की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है. बिहार से ही केसरिया ब्लॉक के ढेकहां गांव से आए एमबीए के छात्र सुधांशु कुमार ने अपनी बात एक शेर से शुरू की, अगर सच कहना बग़ावत है तो समझो हम भी बाग़ी हैं. उन्होंने कहा कि अन्ना का आंदोलन यूपीए सरकार के लिए एक चेतावनी है, जिसने देश की जनता को महंगाई और भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के निवासी कंप्यूटर इंजीनियर आनंद मूर्ति श्रीवास्तव ने कहा, मैंने पिछले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन कांग्रेस राज में देश जिस कदर चौतरफ़ा समस्याओं से घिर गया है, उससे मुझे काफी निराशा हुई. लिहाज़ा यहां अन्ना के पक्ष में नारे लगाकर मैं प्रायश्चित कर रहा हूं. दिल्ली में एक होटल कंपनी से जुड़े अभिषेक कुमार ने कहा कि आंदोलन का असर काफी व्यापक है. संयोग से कैलेंडर भी अन्ना के समर्थकों का साथ दे रहा है, क्योंकि बीच-बीच में छुट्टियां होने की वजह से यहां आना हमारे लिए आसान हो गया.

अन्ना के आंदोलन में विविध आयाम देखने को मिले. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनमानस को खड़ा करने के अलावा इस आंदोलन ने यह भी बताया कि अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति देशहित में किसी मुहिम की अगुवाई करे तो उसके साथ हर पीढ़ी के लोग न केवल जुड़ सकते हैं, बल्कि अनुशासित भी रह सकते हैं. जिन लोगों ने 1990 में पूरे उत्तर भारत में फैले आरक्षण विरोधी आंदोलन को देखा है, उन्हें पता है कि उस समय गुस्से से भरे नौजवानों ने राष्ट्रीय और निजी संपत्ति को कितना नुक़सान पहुंचाया था. आंदोलनकारी युवाओं की एक ही कोशिश होती थी कि कब मौक़ा मिले और कब वे अपना क्रोध सरकारी संपत्ति पर निकालें. यह सच है कि उस आंदोलन का एक सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था. ध्यान देने योग्य बात यह है कि नब्बे के दशक में आंदोलनरत पीढ़ी उदारवाद के दौर की पीढ़ी नहीं थी. उनमें से ज़्यादातर का जन्म साठ के दशक के अंत और सत्तर के दशक की शुरुआत में हुआ था. अन्ना हजारे के आंदोलन में हर उम्र के लोगों ने भाग लिया. जनता ने इसके ज़रिए भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के ख़िलाफ़ अपनी भड़ास निकाली. अन्ना को जेल भेजने के बाद राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में जोरदार आंदोलन हुआ. रामलीला मैदान आने वालों में किसानों की तादाद देखने लायक़ थी. एक ऐसे ही किसान थे महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में रहने वाले सतीश राउत. सतीश ने कहा कि देश के किसानों को अन्ना के आंदोलन से काफी उम्मीदें हैं. पंचायत, तहसील और ज़िलाधिकारी कार्यालय में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है. किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हो या खेती के लिए कर्ज़ लेना हो, बग़ैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता. सतीश का कहना था कि यूपीए सरकार बिना शर्त अन्ना की मांग पूरी करे, वरना उसे इसकी एक बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ेगी. हरियाणा के गुड़गांव ज़िले से आए किसानों ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार की वजह से किसान तंगहाली के दौर में पहुंच चुके हैं. किसान तेज सिंह एवं रोहताश सिंह ने बताया कि पटवारी से लेकर तहसीलदार तक बग़ैर पैसा लिए कोई काम नहीं करते. ऐसे में हम लोग अन्ना हज़ारे के रूप में एक दूसरा गांधी देख रहे हैं.

जयपुर से आए बुज़ुर्ग सुमन कुमार गुप्ता ने कहा कि वह जन लोकपाल और अन्ना हजारे का समर्थन करने दिल्ली आए हैं, लेकिन जन लोकपाल विधेयक तब तक कारगर साबित नहीं होगा, जब तक देश की युवा पीढ़ी इसके प्रति जागरूक नहीं होगी. हमें आज़ादी भी काफी क़ुर्बानियों के बाद मिली थी, लेकिन हमारी उदासीनता और आत्मकेंद्रित सोच की वजह से आज़ादी के 64 सालों बाद अन्ना हज़ारे जैसे वृद्ध आदमी को स्वाधीनता की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है. पंजाब के होशियारपुर ज़िले के धूतकलां गांव निवासी और पेशे से ट्रक ड्राइवर अनिल कमल सिंह ने कहा कि तारीख़ गवाह है कि अधिकार कभी भी थाली में सजाकर नहीं मिला है. मुग़लों के जमाने से लेकर अंग्रेजों तक देश के लोगों को अपने हक़ों के लिए हुक्मरानों से लोहा लेना पड़ा. लिहाज़ा, जन लोकपाल आने से ही देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा. होशियारपुर ज़िले के ही एक किसान अजैब सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं. सरकार किसानों की क़ीमत पर पूंजीपतियों का भला करने में लगी है. ऐसे में अन्ना हज़ारे देश की जनता के बीच एक फरिश्ता बनकर सामने आए हैं. राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर निवासी सब्जी विक्रेता महेंद्र प्रसाद अपना धंधा छोड़कर रामलीला मैदान में डटे हुए थे. उन्होंने कहा कि भूखे पेट सोना मंजूर है, लेकिन अन्ना के इस आंदोलन में वह अंतिम क्षणों तक साथ रहेंगे. वह सड़क किनारे सब्जी बेचते हैं, लेकिन पुलिस और एनडीएमसी वाले उनसे अवैध वसूली करते हैं, मना करने पर धंधा तबाह करने की धमकी देते हैं. केरल से आईं पप्पनी अय्यर ने कहा कि अन्ना जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे देशवासियों का काफी भला होगा और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा. जन लोकपाल विधेयक पर यूपीए सरकार से निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले अन्ना हज़ारे और उनकी टीम को जैसा अपार समर्थन मिला, उसे देखकर राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक भी हैरत में थे. उनका कहना था कि अन्ना को मिले इस जन समर्थन के लिए कहीं न कहीं मौजूदा सरकार ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में जनता जिस क़दर महंगाई और भ्रष्टाचार का शिकार हुई है, उसे देखते हुए उसकी नाराज़गी स्वाभाविक है.

arsingh@chauthiduniya.com

अजब-ग़ज़ब नारे

दुनिया भर के आंदोलनों पर नज़र डालें तो हर जगह आंदोलनकारियों ने सरकार के ख़िलाफ़ गीतों, दोहों और नारों का जमकर इस्तेमाल किया. भारत में 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान राष्ट्रकवि दिनकर रचित *सिंहासन खाली करो कि जनता आती है...* काफी लोकप्रिय हुआ था. उसी तरह 37 वर्षों के बाद एक मज़बूत क़ानून जन लोकपाल की ख़ातिर आंदोलन कर रहे अन्ना हज़ारे के समर्थन में भी राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश भर में अन्ना के पक्ष में और सरकार के ख़िलाफ़ कई तरह के नारे सुनने को मिले. अन्ना को तिहाड़ जेल भेजने पर एक नारा चहुंओर लगा, *वाह रे कांग्रेस तेरा खेल, कसाब को बिरयानी, अन्ना को जेल.* सबसे लोकप्रिय नारे थे-*मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना* और *सोनिया जिसकी मम्मी है, वह सरकार निकम्मी है.* इसी तरह *अन्ना के हैं चार सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई* और *भरी है अन्ना ने हुंकार, जेल जाएंगे गद्दार* जैसे नारों से समूचा रामलीला मैदान गूंज रहा था. कुछ ने तो अपने कपड़ों, कलाइयों एवं बैनरों पर नारे लिख रखे थे. अन्ना की तस्वीर के साथ नारे लिखी टी-शर्ट की मांग भी काफी बढ़ गई थी. अमूमन 15 अगस्त और 26 जनवरी को लहराने वाला तिरंगा अन्ना के आंदोलन के दौरान पूरे देश में बराबर लहराता रहा. राहुल गांधी को देश का युवा चेहरा कहने वाली कांग्रेस से भी आंदोलन में शामिल लोग नारे के ज़रिए पूछ रहे थे, *सारा यूथ यहां है, राहुल गांधी कहां है.* आंदोलनकारियों के निशाने पर कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह भी थे.

देश भर से आई आवाज़

मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना

मी मराठी, मी अन्ना

अन्ना तो हैं ही मराठी, इसलिए महाराष्ट्र में अन्ना का आंदोलन पूरे उफान पर चल रहा है. चाहे बात उनके गांव राले सिद्धी की हो या पूरे महाराष्ट्र की, हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ अन्ना की टोपी ही दिखाई दे रही है. हर कोई मी मराठी, मी अन्ना के नारे लगा रहा है. मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद और राज्य के लगभग हर शहर में अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे गूंज रहे हैं. अन्ना का एक समर्थक तो उनके गांव से महाराष्ट्र तक का सफर बैलगाड़ी में सिर्फ़ इसलिए पूरा करके आया, क्योंकि वह अन्ना के साथ है. लगभग यही नारा पूरे प्रदेश में आम है. राजनीतिक दलों की बात की जाए तो अन्ना की इस मुहिम में कई दलों के नेता, जो अब तक अपनी पार्टी की ज़ुबान बोल रहे थे, आज पार्टी की टोपी उतार कर अन्ना के सुर में गा रहे हैं. जहां संजय निरूपम अन्ना की टोपी पहन कर आंदोलन में शामिल हुए, वहीं उत्तर पश्चिम मुंबई की सांसद प्रिया दत्त ने भी अन्ना का खुलकर समर्थन किया. प्रिया ने अन्ना समर्थकों को भरोसा दिलाया कि वह इस मसले को संसद में उठाएंगी. इतना ही नहीं, अन्ना समर्थकों ने नवी मुंबई के सांसद संजीव नाईक के घर के सामने प्रदर्शन किया. मुंबई के सभी छह सांसदों के घरों पर प्रदर्शन हुआ. संजय और प्रिया के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री गुरुदास कामत, संजय पाटिल, एकनाथ गायकवाड़ एवं मिलिंद देवड़ा के घरों के सामने भी अन्ना समर्थकों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और उन्हें गुलाब का फूल एवं राष्ट्रध्वज भेंट किया. जो सांसद शहर से बाहर थे यानी अपना आवास छोड़कर दिल्ली दरबार में दुबक गए थे, आंदोलनकारियों ने मोमबत्ती जलाकर उनके घरों के सामने रखी और उन्हें सद्बुद्धि की कामना के साथ भजन-कीर्तन किया. उसे जन लोकपाल के समर्थन में संसद में आवाज़ बुलंद करने की अपील भी की गई. वहां पुलिस भी पहुंची. चूंकि इस कार्यक्रम की सूचना पुलिस को नहीं थी, इसीलिए वह सकते में आ गई. आंदोलनकारियों ने अचानक कार्यक्रम बनाया और सीधे सांसदों के घर पहुंच गए. अब जब भी सांसद वापस अपने घर आएंगे तो उन्हें जनता का सामना करना पड़ेगा. महाराष्ट्र में इस मुहिम में लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है. ज़्यादातर महाराष्ट्रियन अन्ना के समर्थन और उनके दर्शन के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान की ओर रवाना हो रहे हैं.

महाराष्ट्र

राजेश एस कुमार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अन्ना हजारे का आमरण अनशन किसी कुंभ से कम नहीं है. जिस तरह कुंभ किसी एक जगह पर न होकर प्रयाग से लेकर नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में संपन्न होता है, उसी तरह आज़ादी की दूसरी लड़ाई का यह कुंभ सिर्फ़ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कोने-कोने में फैल चुका है. जिसने भी इस कुंभ में डुबकी नहीं लगाई, वह हमेशा भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गले तक डूबा रहेगा. यूं तो समय-समय पर जनता को जगाने के लिए हमेशा से ही रैलियां और आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन हर आंदोलन और रैली के नसीब में जनता की इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती, लेकिन अन्ना के इस आंदोलन ने जनता का नसीब बदलने के निए न सिर्फ़ उसे जगाया, बल्कि अंदर तक झकझोर कर रख दिया. आज देश के हर छोर से यही आवाज़ आ रही है कि मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना.

किन्नर, महिला, बुजुर्ग और बच्चे

भ्रष्टाचार को देश से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध उत्तर प्रदेश का तो नज़ारा ही अलग है. यहां एक तरफ़ जहां बुज़ुर्ग गांधीवादी नेता, बच्चे, महिलाएं और युवा अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं अब तक समाज की उपेक्षा के शिकार किन्नर भी इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं. राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद, सदर बाजार और कुछ अन्य क्षेत्रों में किन्नरों ने सड़क पर उतर कर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपने विशेष अंदाज़ में जमकर नारेबाज़ी की और हजारे के आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया. वे कहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें भी अपने देश से प्यार है. लगभग पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अन्ना समर्थकों का अनशन, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा, जनसंवाद और हस्ताक्षर अभियान जारी है. एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि जन लोकपाल बिल पारित होने के पहले ही अन्ना हजारे के अनशन और जनांदोलन के चलते सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम हो गया है. जिन महकमों को बेहद अच्छी कमाई वाला माना जाता है, वहां के अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेने में हिचकने लगे हैं. तमाम कमाऊ विभागों के कर्मचारी अन्ना के आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं. यह अपने आप में एक सकारात्मक परिवर्तन है. हाल में कानपुर के पनकी बी ब्लाक में 3500 रुपये में मीटर में रिमोट ऑपरेटेड डिवाइस लगाने वाले कर्मचारी को उपभोक्ता ने रंगे हाथों पकड़वा दिया. लोगों का कहना है कि अन्ना के आंदोलन ने काफी हद तक लोगों को जागरूक किया है. उधर कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, सांसद रेवती रमण सिंह, कपिल मुनि करवरिया, शैलेंद्र कुमार और प्रमोद तिवारी के घरों को भी अन्ना समर्थकों ने घेरा. सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस अनशन की गूंज अब देश के आख़िरी गांव माणा में भी पहुंच गई है. उत्तराखंड के चमोली ज़िले के बद्रीनाथ धाम से तीन किलोमीटर दूर पहाड़ों पर स्थित माणा गांव के लोगों ने भी अन्ना हजारे के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की. चीन की सीमा पर स्थित देश के इस आख़िरी गांव के लोगों का मानना है कि हर हालत में भ्रष्टाचार का सफाया होना चाहिए.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

नवजात शिशु कहलाएंगे अन्ना

कहीं लोग अन्ना के आमरण अनशन के समर्थन में ख़ुद अनशन पर बैठे हैं तो कहीं आधी रात और तेज बरसात में रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अन्ना का जुनून कुछ इस कदर छाया हुआ है कि लोग अपनी भावी पीढ़ी को अन्ना हजारे जैसा बनाना चाहते हैं, इसीलिए नवजात शिशुओं का नाम अन्ना रखा जा रहा है. हर कोई अन्ना बनने को बेताब है. मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले के ज़िला चिकित्सालय में हाल में जन्मे तीन नवजात शिशुओं के अभिभावकों ने उनका नाम अन्ना रख दिया है. भारत सिंह ने अपने बेटे का नाम सिर्फ़ इसलिए अन्ना रखा, क्योंकि उनके परिवार में यह मेहमान तब आया है, जब देश में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा है. वह चाहते हैं कि उनका बेटा भी अन्ना जैसा बने और देश के लिए कुछ करने के साथ-साथ उनका भी नाम रोशन करे. डॉक्टर कहते हैं कि यह पहला अवसर है, जब नवजात शिशुओं के अभिभावकों ने उनके एक जैसे नाम रखे. इसके अलावा भिंड ज़िले के एहतरार गांव में पूरा गांव ही अनशन पर बैठ गया है. इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं. सागर ज़िले के बीना में लोग गीत-संगीत के माध्यम से इस मुहिम को घर-घर तक पहुंचा रहे हैं. प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी खुलकर अन्ना हजारे के समर्थन में आ गई है. अन्ना समर्थकों ने भोपाल में कैलाश जोशी एवं कांतिलाल भूरिया, छिंदवाड़ा में कमलनाथ, होशंगाबाद में राव उदय प्रताप सिंह, बैतूल में ज्योति धुर्वे, उज्जैन में प्रेमचंद गुड्डू का घेराव किया. इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा और सिवनी में भी आंदोलन किया गया. अन्ना के आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

मध्य प्रदेश

यहां भी है अन्ना की धूम

अन्ना हजारे की एक आवाज़ पर बिहार के चप्पे-चप्पे में इन दिनों धरना, प्रदर्शन, उपवास और कैंडल मार्च का नारा आम हो गया है. अलग-थलग पड़े पुराने संगठनों में जान आ गई है, कई नए संगठन भी खड़े हो गए हैं. बापू के भजन और देशभक्ति गीत बच्चों की ज़ुबान पर चढ़ गए हैं और नए-नए नारे गढ़े जा रहे हैं. अन्ना हजारे के अनशन और उसे मिले समर्थन ने उन लोगों को ताक़त दी है, जो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, तभी तो नालंदा ज़िले के परवलपुर में समाजसेवी नवल प्रसाद पिछले एक सप्ताह से अनशन पर हैं. वह आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार, मिड डे मील और जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं. सारण में पुराने आंदोलनकारी उमेश्वर सिंह उर्फ मुनि जी अपने कई साथियों के साथ अनशन पर हैं, पटना के कारगिल चौक पर जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे अरुण दास और टी उपेंद्र अनशन पर बैठे हैं. इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े राहुल राजन कहते हैं कि धरना, प्रदर्शन एवं उपवास के ज़रिए हम अन्ना हजारे को ताक़त दे रहे हैं. अन्ना विचार मंच, अन्ना संघ जैसे कई नए संगठन भी खड़े हो गए हैं. गोपालगंज में सेवानिवृत्त आईजी गिरीश नंदन सिंह ने भगवानपुर कैमूर में अन्ना हजारे की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की है. पूर्णियां में लोगों ने हनुमान मंदिर के सामने उपवास शुरू किया है, यहां भजन भी गाए जा रहे हैं. बापू का प्रिय भजन-रघुपति राघव राजाराम...भी लोगों की ज़ुबान पर है. राजधानी पटना में कोचिंग संस्थानों के छात्र भी अन्ना के समर्थन में उतर आए हैं. भौतिकविद् एच के वर्मा के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं का बड़ा हुजूम पटना की सड़कों पर उतरा. वर्मा कहते हैं कि जन लोकपाल देश के हित में है, इसलिए हम लोग समर्थन में उतरे हैं. वर्मा की राय है कि अक्षर इस देश से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए तो ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो सकता है. उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे अन्ना के आंदोलन को समर्थन दें. गणित विषय के शिक्षक पंकज ने कहा कि अन्ना हजारे सत्य के साथ हैं और जीवन के हर क्षेत्र में वही शख्स कामयाब होता है, जो सच के साथ होता है. दवा व्यापार से जुड़े अमरेंद्र सिंह कहते हैं कि अन्ना हजारे ने पूरे देश को एक रास्ता दिलाया है. उनके आंदोलन से यह साफ हो गया कि भ्रष्टाचार और उसके कारण बढ़ रही महंगाई से पूरा देश त्रस्त है. इसलिए इस समय देशवासियों का फ़र्ज़ है कि वे भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए शुरू हुए इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दें.

-सरोज सिंह

rajeshy@chauthiduniya.com

बिहार

सूचना का अधिकार क़ानून आज़ादी के बाद एक ऐसा क्रांतिकारी क़ानून बनकर उभरा है, जिसे आम नागरिक एक कारगर हथियार के रूप में लगातार इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं.

शेहला मसूद

सूचना का एक और सिपाही शहीद

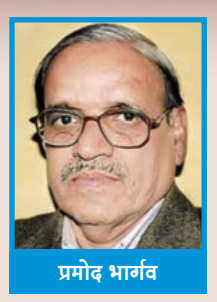

प्रमोद भार्गव

भ्रष्टाचार की भंडाफोड़ कोशिशें जानलेवा साबित हो रही हैं. भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद की हत्या से पूरे देश में सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां लेने का जोख़िम उठा रहे कार्यकर्ता हैरान हैं. इस क़ानून के लागू होने से लेकर अब तक 17 आरटीआई कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है. बीते छह माह में ही छह कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई. मसलन प्रत्येक माह एक कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारा गया. शेहला की हत्या के बाद सामने आईं जानकारियों से पता चला कि उन्होंने क़रीब एक हज़ार आवेदन गड़बड़ियों से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए कर रखे थे. इनमें बाघों के शिकार, वनों की अवैध कटाई और पुलिस की करतूतों से जुड़ी जानकारियों की मांगें महत्वपूर्ण थीं. लिहाज़ा आशंका जताई जा रही है कि इसीलिए उनकी हत्या कराई गई. हालांकि शुरुआत में इस हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन शेहला के परिवार जनों एवं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह द्वारा सीबीआई जांच की मांग सामने आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे तत्काल सीबीआई को सौंप दिया.

सूचना का अधिकार क़ानून आज़ादी के बाद एक ऐसा क्रांतिकारी क़ानून बनकर उभरा है, जिसे आम नागरिक एक कारगर हथियार के रूप में लगातार इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं. यह क़ानून लोकसेवकों और नौकरशाहों की जवाबदेही तय करता है. इसीलिए अब कार्यपालिका के लिए भ्रष्टाचार, गड़बड़ियों और बरती जा रही अनियमितताओं को गोपनीय बनाए रखना मुश्किल हो रहा है. सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां विकास कार्यों, लोक कल्याणकारी योजनाओं और जागरूकता अभियान से जुड़े कार्यों में सामने आ रही हैं. इस क़ानून को वजूद में भी इसी मक़सद से लाया गया था कि सरकारी कार्यों में प्रशासन एवं नागरिकों के बीच पारदर्शिता सामने आए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे. इन्हीं वजहों से नागरिक समाज में जागरूकता बढ़ी और लोक कल्याण के महत्व से जुड़ी जानकारियां एकत्र करने का सिलसिला तेज हो गया. चूंकि ये जानकारियां भरोसे के सूत्रों से मिली जानकारियों के बजाय संबंधित दफ़्तर से ही प्रामाणिक एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज़ों के रूप में सामने आती हैं, इसलिए इनकी सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता. आरटीआई कार्यकर्ता इन दस्तावेज़ी साक्ष्यों को अख़बारनवीसों को उपलब्ध कराकर ख़बरों का हिस्सा भी बना देते हैं. भ्रष्ट कारनामे सामने आने से संबंधित अधिकारी–कर्मचारी ख़ुद को अपमानित महसूस करते हैं. इस कदाचरण पर जांच भी शुरू हो जाती है, जो उनके लिए कई परेशानियों का सबब बनने के साथ–साथ भ्रष्ट आचरण से हासिल धन का बंटवारा करने का कारण भी बनती है. विधानसभा में मामला गूंज जाए तो कई सवालों के आधिकारिक जवाब भी देने पड़ते हैं. लज्जा और जिल्लत के इन दौरों से न गुजरना पड़े, इस नज़रिए से ये लोग भी प्रतिकार का आक्रामक रुख़ अपना लेते हैं. यह मानसिकता जानकारी मांगने वालों के लिए कभी–कभी जानलेवा भी साबित हो जाती है. शेहला मसूद की हत्या इसी मानसिकता का प्रतीक मालूम होती है.

सूचना का अधिकार क़ानून लागू हुआ था, तो यह उम्मीद जगी थी कि भ्रष्टाचार पर किसी हद तक लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भ्रष्टाचार सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता रहा और आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान पर बन आई. नतीजतन देखते–देखते 17 कार्यकर्ताओं के प्राण हर लिए गए. चूंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला जितना संगीन होता है, उससे जुड़े नौकरशाह और ठेकेदारों का गठजोड़ भी उससे कहीं ज़्यादा पहुंच वाला होता है. इसलिए अव्वल तो पारदर्शिता से जुड़ी जानकारियां देने में आनाकानी की जाती है और यदि जानकारी किसी बड़े घोटाले से जुड़ी है तो कार्यकर्ता की जान भी जोख़िम में डाल दी जाती है. इसीलिए अब आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग बढ़ती जा रही है. यह मांग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में इंजीनियर रहे सत्येंद्र दुबे की हत्या के बाद से लगातार उठाई जा रही है. दुबे ने स्वर्णिम चतुर्भज योजना में हुए भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ दस्तावेज़ी साक्ष्यों के साथ किया था, जिसका परिणाम उन्हें अपने प्राण गंवा कर भोगना पड़ा. इस घटना के बाद से ही जानकारी देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मुहैय्या कराने की मांग ने जोर पकड़ रखा है. उनकी पहचान भी गोपनीय रखने की मांग की जा रही है. विधि आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार से इस संदर्भ में क़ानून बनाने के लिए कहा है. इस मांग की पूर्ति के लिए ही व्हिसल ब्लोअर क़ानून के प्रारूप को संसद में पेश किया जाना है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस क़ानून में कई विसंगतियां हैं. इसलिए संशोधित किए बिना मौजूदा मसौदे को विधेयक का रूप देना ग़लत है. फ़िलहाल यह मसौदा संसद की स्थायी समिति के पास है. वह इसे परखने और ज़रूरी हुआ तो कुछ बदलावों के बाद संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत करेगी.

दरअसल इस प्रस्तावित विधेयक और शासकीय गोपनीयता क़ानून के बीच ऐसा तालमेल होना ज़रूरी है, जिससे यह क़ानूनी रूप ले और इसके अमल की भी कारगर व्यवस्था सामने आए. जानकारी मांगने वालों को टालमटोल का सामना न करना पड़े, उन्हें गोपनीयता की ढाल में नाजायज़ कारोबार को अंजाम देने वाले भ्रष्टाचारी धमकाने और उनकी जान से खिलवाड़ करने से बाज आएं.

दरअसल इस प्रस्तावित विधेयक और शासकीय गोपनीयता क़ानून के बीच ऐसा तालमेल होना ज़रूरी है, जिससे यह क़ानूनी रूप ले और इसके अमल की भी कारगर व्यवस्था सामने आए. जानकारी मांगने वालों को टालमटोल का सामना न करना पड़े, उन्हें गोपनीयता की ढाल में नाजायज़ कारोबार को अंजाम देने वाले भ्रष्टाचारी धमकाने और उनकी जान से खिलवाड़ करने से बाज आएं. व्हिसल ब्लोअर और सूचना अधिकार क़ानून के विरोध में खड़ी कार्यपालिका दावा करती है कि आरटीआई का दुरुपयोग हो रहा है, अधिकारियों को नाहक परेशान करने के लिए इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में यदि आरटीआई की छत्रछाया से वजूद में आए इन कार्यकर्ताओं को व्हिसल ब्लोअर क़ानून लाकर सुरक्षा मुहैय्या कराई जाती है तो सरकारी तंत्र की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ लोगों ने आरटीआई को प्रतिष्ठा और आजीविका हासिल करने का साधन बना लिया है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र का यह एक बहाना भर है. आरटीआई क़ानून का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई करने के पुख्ता इंतज़ाम हैं, किंतु भ्रष्टाचारियों में क़ानूनी तरीक़े से लड़ने का माद्दा नहीं होता. इसलिए वे हथकंडों का सहारा तो लेते हैं, लेकिन कामकाज में पारदर्शिता दिखाई दे, ऐसे क़ानून के विरोध में खड़े हो जाते हैं. इस नज़रिए से आरटीआई की मज़बूती बनाए रखना ज़रूरी है, साथ ही कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक ठोस क़ानून वजूद में आना भी बेहद ज़रूरी है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... जन लोकपाल बिल

उत्तराखंड के भीम गोडा बांध से 10 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बिजनौर ज़िले की मालन नदी उफना गई है, वहीं बाकरपुर-यूसुफपुर बांध टूट गया.

बाढ़ का क़हर

पीड़ित भगवान भरोसे

राजेश सिन्हा

लगातार बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार के लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. शहरी इलाक़ों में बाढ़ की स्थिति भयावह नहीं दिख रही है, लेकिन मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर एवं पूर्णियां सहित कई ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं. प्रभावित लोग तटबंधों और अन्य ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा समुचित राहत की कोई व्यवस्था नहीं है. शासन-प्रशासन की बेरुखी के कारण दर्जनों गांव के लोगों के समक्ष रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है. भूखे बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. लोग मवेशियों के लिए चारा जुटाने के लिए कोई भी जोख़िम उठाने से नहीं हिचक रहे हैं. बावजूद इसके प्रशासन कई ज़िलों में बाढ़ की स्थिति सामान्य बता रहा है. प्रभावित ज़िलों में भी कई स्थानों पर राहत सामग्री नहीं पहुंच सकी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है. स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका इस बार संदेह के घेरे में है, क्योंकि कुछ जगहों पर उन्होंने राहत शिविर का बैनर तो लगा दिया है, लेकिन राहत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. मुट्ठी भर राहत देकर स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन ने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाक़ों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बाढ़ की स्थिति सामान्य बताते हुए कहा कि वहां राहत सामग्री के वितरण के साथ-साथ आवागमन के लिए पर्याप्त नौकाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. इस आदेश का अधिकारियों पर कितना असर हुआ और यह कितना कारगर होगा, यह तो वक़्त बताएगा, लेकिन जब चौथी दुनिया द्वारा प्रभावित इलाक़ों का जायज़ा लिया गया तो प्रमाणित हो गया कि लोग शासन-प्रशासन से अधिक भगवान पर भरोसा करने को मजबूर हैं. ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में पर्याप्त नौकाएं उपलब्ध कराने का दावा तो किया गया, लेकिन हक़ीक़त कुछ और है. नौकाएं न होने के कारण लोग जान जोख़िम में डालकर यहां-वहां आने-जाने के लिए मजबूर हैं. अब तक दो दर्जन से अधिक लोग इस चक्कर में डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं. कई इलाक़ों में नावों की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन वे इतनी जर्जर हैं कि लोग उन पर सवारी करने से बच रहे हैं. कोसी, बागमती, काली कोसी एवं करेह सहित कई नदियों के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि न होने से कुछ इलाक़े पूर्ण रूप से और कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, लेकिन गंगा एवं बूढ़ी गंडक की उफनती धार ने कई नए इलाक़ों में कोहराम मचा दिया है. बाढ़ आने के पूर्व एकत्र किए गए खाद्यान्न से ही कई परिवार किसी तरह अपनी भूख मिटा रहे हैं. अब जबकि खाद्यान्न लगभग ख़त्म होने को है, इसलिए बाढ़ का जायज़ा लेने पहुंच रहे प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित लोगों द्वारा खदेड़ा जा रहा है. बेगूसराय ज़िले में गंगा नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण मटिहानी, बलिया, शाम्हो एवं सनहा सहित कई अन्य इलाक़ों के लोग तबाही झेलने को मजबूर हैं. सनहा गोरगामा बांध के कई हिस्सों में दरार पड़ने के कारण कई इलाक़ों में दहशत का माहौल है. गंगा की दहाड़ से सहमे लोगों के साथ-साथ प्रशासन द्वारा लगातार स्थिति पर नज़र रखी जा रही है. दियारा इलाक़े में रहने वाले लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल होता जा रहा है. कई ऐसे प्रभावित गांव हैं, जहां अभी तक राहत वितरण की बात तो दूर, प्रशासनिक अधिकारी जायज़ा लेने भी नहीं पहुंचे हैं. समस्तीपुर ज़िले के मोहिउद्दीनगर एवं मोहनपुर सहित पटोरी प्रखंड की कई पंचायतों में सैलाब ने लोगों की ज़िंदगी पटरी से उतार दी है. घरेलू सामान और मवेशियों के साथ इलाक़े से पलायन कर चुके लोग सिर छिपाने के लिए इधर-इधर भटक रहे हैं. खगड़िया ज़िले के 59 गांवों में बाढ़ का कहर जारी है. गोगरी अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित लोगों में प्रशासन के प्रति खासी नाराज़गी देखी जा रही है. राहत से वंचित लोगों का कहना है कि राहत वितरण के नाम पर जमकर धांधली बरती जा रही है. अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है. कटघरा निवासी विनोद राय, सुमन राय, गौतम राय एवं बिनोद महतो और भूड़िया गांव निवासी अवधेश यादव एवं सूखो यादव आदि ने बताया कि सरकारी स्तर से नाव उपलब्ध न कराए जाने के कारण लोगों को निजी नावों पर सवारी करनी पड़ रही है. अधिक कमाई की चाहत में नाविकों द्वारा क्षमता से अधिक लोगों को नाव पर लादने के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. खगड़िया प्रखंड के रहीमपुर नया टोला, नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 एवं 26 सहित अन्य इलाक़ों में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है. नाव न होने के कारण लोग नाद (मवेशियों का भोजन पात्र) या अन्य साधनों का सहारा लेकर आ-जा रहे हैं.

बिहार

खगड़िया से होकर गुजरने वाले एनएच- 31 एवं रेलवे ब्रिज के पास बूढ़ी गंडक ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है. नतीजतन राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर भी ख़तरा मंडराने लगा है. यह अलग बात है कि कार्यपालक अभियंता का कहना है कि एनएच-31 से पानी पांच फीट नीचे है. कोसी नदी भी बलतारा, बसुआ और कुरसैला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. गोगरी-नगरपाड़ा तटबंध एवं बदला-नगरपाड़ा तटबंध के कई हिस्सों पर बूढ़ी गंडक नदी का दबाव बना हुआ है, जबकि नारायणपुर लिंक बांध पर भी ख़तरा उत्पन्न हो गया है. गोगरी के साथ-साथ परबत्ता प्रखंड में गंगा एवं बूढ़ी गंडक ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. बन्नी, बौरना एवं गोगरी पंचायत सहित कई अन्य इलाक़ों में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है. मधुआ गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी का पानी बाएं तटबंध को भेद चुका है. परबत्ता प्रखंड के सौढ़ उत्तरी एवं सलारपुर पंचायत के लोगों का जीना मुहाल हो गया है. सुपौल, मधेपुरा एवं कटिहार में भी बाढ़ का कहर जारी है. मधेपुरा ज़िले के पास एनएच-107 पर बना बलुआहा डायवर्सन ध्वस्त हो जाने के कारण तीन ज़िलों का पटना मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है. खगड़िया-बेलदौर के बीच बना डुमरी पुल पहले ही ध्वस्त होने के कारण मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल के लोगों को पूर्णियां होकर पटना पहुंचना पड़ता था. मधेपुरा ज़िले के चौसा प्रखंड की आधा दर्जन पंचायतें पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं. सुपौल ज़िले की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है. यहां के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अमहा के समीप नहर टूट जाने से पानी कम होने लगा है. बिहार-बंगाल सीमा के समीप बहने वाली नागर नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कटिहार ज़िले के बारसोई एवं विघोर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. नजराबाड़ी, पीरासन एवं डेंगरापाड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि कई गांवों पर ख़तरा मंडरा रहा है. अररिया, भागलपुर एवं मुंगेर सहित कई अन्य जगहों पर भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना कि स्थिति सामान्य है, निश्चित रूप से जले पर नमक छिड़कने के समान है. शासन-प्रशासन की इस बेरुखी के परिणामस्वरूप अगर बाढ़ प्रभावित लोग उग्र रूप धारण करने को मजबूर हो जाएं तो सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के मुखिया को भी आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

दूध और ब्रेड को तरसे लोग

राजकुमार शर्मा

भारी वर्षा के चलते राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, लेकिन लोग बारिश को नज़रअंदाज़ करके, जान को जोख़िम में डालकर यात्राएं कर रहे हैं. राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन पूरी तरह फिसड्डी साबित हो रहा है, जिसके चलते उत्तरकाशी और रुद्र प्रयाग में आवश्यक सेवाएं चरमरा गई हैं. तेज बारिश के साथ मलबा आने से होने वाले भूस्खलन के चलते गंगोत्री-बद्रीनाथ राजमार्ग पर आवागमन ठप्प हो गया है. भटवाड़ी से लगे पचास गांवों के साथ-साथ अब सेना, आईटीबीपी एवं वीआरओ के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है. उत्तरकाशी और ऋषिकेश को आपस में जोड़ने वाला मार्ग बंद होने के कारण बाज़ार में सब्जी, दूध, ब्रेड और मक्खन की कमी हो गई है. बाज़ार में एक-दो को छोड़कर कोई सब्जी नहीं मिल पा रही है. गंगोत्री मार्ग पर डूंडा के नीचे छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे मार्ग में फंसे लोग अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन इनकी परेशानी कम नहीं हुई. मनेरी के आगे गंगोत्री राजमार्ग, भटका सौड़, भटवाड़ी बाज़ार, चडेती, हेलंगू, थिरांग एवं सुक्की में आए मलबे और भू-धसान के चलते जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. टकनौर क्षेत्र खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है. राज्य सरकार सिर्फ़ विज्ञापनों में सरकार जनता के द्वार का नारा लगा रही है. प्रशासन इन इलाक़ों में फंसे स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है. इन इलाक़ों में केरोसिन एवं रसोई गैस की आपूर्ति न हो पाने के कारण जनता को काफी परेशानी हो रही है. इलाक़े में बंद पड़े 42 संपर्क मार्गों में से अब तक केवल दो मार्ग ही खोले जा सके हैं. बद्रीनाथ मार्ग भी जनता की परेशानी का सबब बन गया है. यहां राजमार्ग सहित कई संपर्क मार्ग बंद होने के कारण लोगों को अपनी जान जोख़िम में डालकर पहाड़ी मार्गों से गुजरना पड़ रहा है. वहीं इन दिनों बीमार लोग उपचार के अभाव में काल के गाल में समा रहे हैं. राज्य के मैदानी इलाक़ों में भी बारिश ने कहर ढा रखा है. हरिद्वार के एक दर्जन गांवों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है. इन गांवों के साथ ही लक्सर बाज़ार में भी तीन से पांच फुट पानी हिलोरें ले रहा है. गंगा और सोलानी की उफनती लहरों ने तटों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके चलते लक्सर तहसील के लगभग दो दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और एक दर्जन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. हरिद्वार में भारी वर्षा के चलते विभिन्न गांवों के क़रीब 1500 कच्चे मकान ध्वस्त हो गए. लक्सर के मोहनवाला, दावतीखेड़ा एवं जोगावाला में पांच से छह फुट तक पानी हिलोरें ले रहा है. प्रशासन ने तटबंध टूटने पर पीएसी के जिन जवानों को बचाव-राहत कार्य के लिए भेजा था, वे वापस जा चुके हैं. जनता की परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है. बरसाती नदी रतमई के किनारे स्थित तटबंध टूटने से औरंगाबाद के ग्रामीण काफी परेशान हैं. इससे फसल तो बर्बाद हुई ही, खेतों में कटाव की समस्या पैदा हो गई. हरिद्वार के शहरी इलाक़ों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को सिल्ट का कहर झेलना पड़ रहा है. नगरपालिका प्रशासन सिल्ट हटने के बाद सफाई कराने की बात कहकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया है. सिल्ट जमा होने से कई इलाक़ों में बीमारियां फैल रही हैं. 19 सर्किलों में कूड़ा उठाने का काम ठप्प है, इससे धर्म नगरी का हाल बेहाल है. देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को कूड़े के ढेरों से गुजरना पड़ रहा है. खास तौर से कनखल एवं ज्वालापुर में स्थिति ज़्यादा ख़राब है. राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक हरिद्वार में ही रहते हैं, फिर भी जनता की परेशानी से उनका कोई लेना-देना नहीं है. केंद्रीय संसदीय राज्यमंत्री एवं हरिद्वार के सांसद हरक सिंह रावत ने लक्सर एवं सुल्तानपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करके जनता का दुःख-दर्द जाना. उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराज़गी व्यक्त की. रावत ने हरिद्वार के ज़िलाधिकारी की भी जमकर क्लास ली. राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि सूबे का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह नाकाम सिद्ध हो रहा है, जिसके चलते पहाड़ी एवं मैदानी, दोनों ही इलाक़ों में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने सरकार का ध्यान चार धाम यात्रा में फंसे यात्रियों की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि इसका नकारात्मक संदेश पूरे देश में जा रहा है, जिसका राज्य के पर्यटन उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या का मानना है कि मुख्यमंत्री को दैवीय आपदा से परेशान जनता को राहत प्रदान करने का काम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए.

उत्तराखंड

feedback@chauthiduniya.com

हर तरफ़ पानी ही पानी

बाढ़ और पानी से शहरी जनता हलकान है, वहीं किसान परेशान. किसी के खेत पानी में डूब गए हैं तो किसी का घर-मकान और राशन-पानी बाढ़ लील गई. क़रीब 24 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं. लोग छतों पर तिरपाल लगाकर, स्कूलों के बरामदों में, कुछ नहीं तो खुले में ही जीवनयापन कर रहे हैं. बाढ़ के कहर ने सूखे से बेहाल हुए किसानों की कमर तोड़कर रख दी है. शारदा एवं घाघरा आदि नदियों में बनबसा एवं शारदा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, फ़ैज़ाबाद एवं अंबेडकर नगर आदि ज़िलों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है. गंगा, यमुना, रामगंगा एवं कोसी आदि नदियों में उफान के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक गंगा, यमुना, चौका एवं गोबरहिया आदि नदियों के किनारे बसे शहरों और गांवों की हालत ख़राब है. बाढ़ से निपटने और राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय आपदा राहत बल की टुकड़ियां भेजने का आग्रह किया था, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया. बिजनौर में बाकरपुर-यूसुफपुर बांध टूटने के कारण लगभग सौ गांवों में पानी भर गया, वहीं बिजनौर, हरिद्वार एवं रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर पानी बह रहा है. इससे लखनऊ-दिल्ली राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ. बनबसा बैराज से अचानक चार लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गोंडा एवं बाराबंकी ज़िले के क़रीब 200 गांव प्रभावित हुए. बहराइच में घाघरा के तटबंध के पास बसे कायमपुर में तेज बहाव के चलते दो लोगों की मौत हो गई. घाघरा का जलस्तर ख़तरे के निशान से 65 सेमी ऊपर पहुंच गया है. सरयू और घाघरा ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. गोंडा ज़िले के कर्नलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्रों के क़रीब 104 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. ज़िला प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कहा है. अकेले गोंडा ज़िले में दो लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. घाघरा के कटान से कई घर नदी में समा चुके हैं. बहराइच में बाढ़ के कारण कैसरगंज के कई गांव पानी से घिरे हैं, जिनकी कुल आबादी 85,373 है. इसके अलावा खासेपुर, अहाता, ढपाली पुरवा एवं गोड़हिया के दो दर्जन गांवों में भी पानी भर गया. राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और राहत आयुक्त के के सिन्हा ने बताया कि मुरादाबाद और गोंडा की हालत ज़्यादा ख़राब है. केंद्र से एनडीआरएफ की टुकड़ियां भेजने का आग्रह किया गया है, जिन्हें अभी फ़िलहाल गोंडा और मुरादाबाद में छह-छह नावों के साथ तैनात किया जाएगा. बहराइच और गोरखपुर में पीएसी के जवान बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तैनात हैं. उत्तराखंड के भीम गोडा बांध से 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बिजनौर ज़िले की मालन नदी उफना गई है, वहीं बाकरपुर-यूसुफपुर बांध टूट गया. बिजनौर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी आ गया, जिसके चलते उसे बंद करना पड़ा. कालागढ़ बांध से छोड़े गए पानी के चलते रामगंगा का जलस्तर ख़तरे के निशान से ऊपर चला गया, जिससे बिजनौर एवं मुरादाबाद ज़िले के लगभग सौ गांव प्रभावित हुए. रामपुर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से क़रीब 22 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. हरिद्वार से गंगा में दो लाख 90 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद मुज़फ़्फ़रनगर की जानसठ तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए. हरियाणा के ताजवाला बैराज से यमुना में क़रीब सवा छह लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से भी ज़िले के तटवर्ती गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई. बदायूं में भी बाढ़ का ख़तरा बढ़ गया है. प्रशासन ने सभी 13 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है. लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का तांडव चल रहा है. पीलीभीत-बस्ती मार्ग अवरुद्ध हो गया है. पहाड़ों पर लगातार बारिश और डैमों से पानी छोड़े जाने से शाहजहांपुर की सभी नदियां उफना गई हैं. रामगंगा एवं गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से निचले ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है. गांवों में भी नदियों का पानी घुसना शुरू हो गया. भारी वर्षा एवं किच्छा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते बरेली की मीरगंज तहसील के एक सौ से अधिक गांव जलमग्न हो गए और सुल्तानपुर गांव तो पूरी तरह नदी में समा गया. प्रशासन ने 38 गांवों के जलमग्न होने की पुष्टि की है. सीतापुर में गांजरी क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग घर छोड़कर पलायन कर गए हैं. लखीमपुर खीरी में मूसलाधार बारिश के चलते उफनाई नदियां अपनी जगह छोड़कर बस्ती में घुसने लगी हैं. बाढ़ की विकरालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह मुद्दा राज्यसभा तक पहुंच गया. भाजपा के कलराज मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार को बाढ़ राहत कार्यों में फ़ौरन अपना योगदान करना चाहिए. भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राज्य के 24 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं. मुख्यमंत्री मायावती ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव कार्यों में तेजी लाने और पीड़ितों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं मुहैय्या कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं शहरी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी क़दम उठाने को कहा गया है.

उत्तर प्रदेश

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com

समाचारपत्रों की विकृति

महावीर प्रसाद आर मोरारका

आज के युग में स्कूलों के सिवाय मानव मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है समाचारपत्रों का. आपने ग़ौर किया होगा कि भारत में जितने भी समाचारपत्र पढ़े जाते हैं, शहरों में, देहातों में या गांवों में, उनमें से 80–90 फ़ीसदी वे समाचारपत्र हैं, जिनके मालिक करोड़पति हैं. पत्रकारिता का सारा व्यवसाय आज इन्हीं करोड़पतियों के हाथ में है. भला ये कैसे धनिकों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं? जब सरकार द्वारा किया हुआ कोई ग़ैर क़ानूनी काम सामने आता है तो ये हाहाकार मचा देते हैं, आकाश–पाताल एक कर देते हैं, सरकार को चैन नहीं लेने देते. पर जब धनिक समाज का एक अंग, चाहे वे कपड़े की मिलों के उद्योगपति हों, चाहे वे चीनी की मिलों के मालिक हों, चाहे वे जूट की मिलों के मालिक हों या रासायनिक व्यवसाय के लोग हों, कोई ग़ैर क़ानूनी कार्यवाही करने लगते हैं, प्रजा उनकी करतूतों से संत्रस्त हो जाती है, तब इन समाचारपत्रों के संपादकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती. जब कहीं रेलवे दुर्घटना हो गई, उसमें कुछ व्यक्ति मर गए तो प्रजा की ओर से एक बुलंद आवाज़ उठेगी. समाचारपत्र लिखेंगे कि दुर्घटना होना बहुत बुरी बात है, लंबे–लंबे शब्दों या संदेशों में सहानुभूति प्रगट करेंगे. पर जब इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाकर सरकार यह घोषणा करे कि रेलवे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना होगा, उनके काम करने के समय की अवधि में कमी करनी होगी और घाटे की पूर्ति करने के लिए भाड़ा, महसूल या टिकट की दरें बढ़ाई जाएंगी तो फिर यही समाचारपत्र वाले हल्ला मचाएंगे कि यह बड़ा अनुचित हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इत्यादि.

मानव मस्तिष्क पर स्कूल की शिक्षा का या समाचारपत्र निरंतर पढ़ते रहने का जो प्रभाव पड़ता है, वह प्रतिकूल ही है. उसको आप ठीक रास्ते पर ला नहीं सकते. कारण–स्कूल, शिक्षा विभाग और समाचारपत्र, ये सब धनिक समाज द्वारा नियंत्रित हैं, उन्हीं द्वारा संचालित हैं या उन्हीं के दिए हुए विज्ञापनों पर जीवित हैं. अतएव उनका पक्षपात होना स्वाभाविक ही है. गांवों–देहातों में तीसरी चीज जो मानव दिमाग़ पर असर करती है, वह है मंदिर में जाना, भगवद्चर्चा या धर्मगोष्ठी. गांव के लोग रात को या शाम को चौपाल पर या मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे होकर आपस में बातचीत करते हैं, उनमें अधिकतर इन्हीं धनिकों के गुणगान का बखान होता है या भारत के प्राचीन इतिहास में राजाओं ने प्रजा का पालन किस तरह किया, उसका विशद वर्णन. रामराज्य की कल्पना बहुत ही अच्छी कल्पना मान ली जाती है, जो विशुद्ध बुर्जुआ सामंतवाद था. भारत हमेशा से ही वीर पूजक रहा है. मानव के व्यक्तिगत गुणों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए यहां का नागरिक उसी व्यक्ति की पूजा करने लगता है. राम, कृष्ण, बुद्ध, राणा प्रताप, शिवाजी, लोकमान्य तिलक, गांधी जी, पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल इत्यादि अनेक महापुरुष हुए हैं, जिनके निजी गुणों से मुग्ध होकर भारत की प्रजा उन्हें चिरकाल के लिए पूज्य मान रही है.

मतलब यह नहीं कि वे महापुरुष किसी भी मायने में पूजा के या प्रशंसा के पात्र नहीं, मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूं कि सर्वसाधारण मानव की आर्थिक स्थिति के संबंध में इनमें से किन–किन महानुभावों ने क्या–क्या किया. वर्ग विभाजन को, चाहे वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो, चाहे ज्ञान शिला पर आधारित हो, चाहे संग्रह मूलक हो, क़रीब–क़रीब सबने ही प्रोत्साहन दिया. गांव की चौपाल में बैठकर आज भी शाम को रामायण की कथा होती है, सब ही श्रोता आनंद विभोर होकर राम का यशोगान और रामराज्य की प्रशंसा करते हैं. उनमें से किसी के मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि आख़िर ऐसी कौन सी वस्तु थी, जिसे इतना ऊंचा आदर्श माना जाए? उसी रामराज्य में एक ब्राह्मण बालक की असामयिक मृत्यु हो जाने पर जब उसके पिता ने आकर राम के दरबार में दुहाई दी तो राजा राम ने अपना धनुष–बाण उठाकर जंगल में तपस्या कर रहे शूद्र शंबूक का वध कर डाला और तब सब ही एक मत से उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा करने में लग गए. मान भी लिया जाए कि शंबूक का तपस्या करना तत्कालीन क़ानून के अनुसार अवैध था, तो भी क्या यह कथा यह ज़ाहिर नहीं करती कि मानव–मानव में कितना भारी फ़र्क़ था. रामराज्य कैसा आदर्श था, यह अगर शंबूक के माता–पिता या परिवार वालों से पूछा जाए तो पता चले? कहने का तात्पर्य है कि स्कूल, समाचारपत्र या धर्म चर्चा ये तीन प्रधान साधन, जो जनता की राय क़ायम करने में सहायक होते हैं, तीनों पर धनिकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हुआ है. समान अर्थ वितरण का प्रश्न इन कारणों से सामने खड़ा ही नहीं हो पाता.

भारत में सबसे बड़ी समस्या जो शताब्दियों से चल रही है, वह है जातिवाद या वर्ण व्यवस्था. इन जातियों के हिसाब से आदमी अपने आप अपने को छोटा या बड़ा मानने लग गया है और यह भावना अपने रक्त में इस तरह समा गई है कि हम आज के प्रगतिशील युग में भी मन से इसको निकाल नहीं पा रहे हैं. आज भी सबसे ज़्यादा ताक़तवर नारा जाति का ही है. चुनावों में भी खुलेआम इसका प्रयोग होता है. हालांकि भारतीय संविधान के अनुसार देश धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हो चुका है. तो भी बनिए–बनिए आपस में वोट देंगे, जाट–जाट आपस में मेल रखेंगे. दक्षिण भारत में ब्राह्मण चूंकि अल्पसंख्यक हैं, अब्राह्मणों का वोट न मिलने से वे चुने नहीं जा सकते. इसी तरह की बीमारी सारे राष्ट्र में आज भी फैली हुई है. जहां नेताओं का यह उपदेश है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करना ही होगा, जाति–पांत का भेदभाव मिटाना ही होगा, वहां वे ही हर राज्य सरकार में, हर कमेटी में, हर नौकरी में यह खयाल रखते हैं कि अमुक जाति का प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं. मिनिस्ट्री में राजपूत 1 ही क्यों है? जाट 3 क्यों हैं, ब्राह्मण 1 ही है, हरिजन 2 हैं. इस जातिवाद का प्रतिनिधित्व अनुपात से हो, यह फिक्र बनी रहती है. तो बताइए श्रेणी विभाजन की यह मानसिक भावनाएं बदलें तो कैसे बदलें? मान लीजिए, अगर सबके पास समान वित्त हो तो क्या स्कूल के अध्यापक इस तरह कायर हो सकते थे? क्या समाचारपत्र इस तरह से ईमानदारी को अलग ताक पर रख सकते थे? क्या इन मंदिरों, मस्जिदों, धर्म गोष्ठियों या गांवों की चौपाल गोष्ठियों में राजा का, महाराजाओं या सेठों का यशोगान हो सकता था? कदापि नहीं, ये सब उसी हीन भावना के प्रतीक हैं, जो आप में, हम में, सब में समा गई है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

आने वाले दिन संकट वाले हैं

देश अगले कुछ दिनों तक संकट में अभी और रहेगा. संकट में इसलिए रहेगा, क्योंकि हमारी महान सरकार संकट सुलझाना कम जानती है, संकट पैदा करना ज़्यादा जानती है. नियम नए सिरे से लिखने की कोशिश हो रही है. जब नियम नए सिरे से लिखे जाएं और पहले से बने उन नियमों की अनदेखी की जाए, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया है, तब लगता है कि संकट जानबूझ कर प्रकट किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के कम से कम सात फ़ैसले ऐसे हैं, जो यह बताते हैं कि जब भी कभी जन्मतिथि का संकट हो या उस पर बहस हो या कन्फ्यूजन हो कि किसी आदमी की जन्मतिथि क्या हो. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला साफ़–साफ़ कहता है कि ऐसी स्थिति में हाईस्कूल का प्रमाणपत्र आख़िरी सबूत, आखिरी प्रमाण माना जाए. जो जन्मतिथि हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में लिखी गई है, वही उस व्यक्ति की जन्मतिथि मानी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को अब भारत की सरकार बदल रही है. भारत की सरकार यह फ़ैसला कर रही है कि किसी भी फॉर्म में, जैसे यूपीएससी के फॉर्म में अपने हाथ से किसी ने अपनी जो जन्मतिथि लिख दी, किसी क्लर्क ने जो जन्मतिथि लिख दी या किसी ने ग़लती से जो जन्मतिथि लिख दी, वही जन्मतिथि सही है, लेकिन उन्हीं दिनों आए हुए हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में जो जन्मतिथि लिखी है, वह सही नहीं है. ऐसा सरकार किसी और के साथ नहीं कर रही, बल्कि भारत के थल सेनाध्यक्ष के साथ कर रही है. सरकार सांसदों की बात, मीडिया की बात या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से निकले हुए संकेत को मानना ही नहीं चाहती. सरकार ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वह किसी भी स्थिति में जनरल वी के सिंह, जो भारत के थल सेनाध्यक्ष हैं, की जन्मतिथि वही मानेगी जो यूपीएससी के फॉर्म में लिखी हुई है, न कि वह, जो उनके हाईस्कूल प्रमाणपत्र में लिखी हुई है.

यह सारी कहानी 2006 में शुरू हुई, जब जनरल जे जे सिंह भारत के थल सेनाध्यक्ष थे. जनरल जे जे सिंह आज राज्यपाल हैं. उन्होंने उस समय अंदाज़ा लगाया कि चाहे जन्मतिथि 1950 हो या 1951, जनरल वी के सिंह भारत के थल सेनाध्यक्ष बनेंगे ही. अगर वी के सिंह थल सेनाध्यक्ष बनते हैं और जन्मतिथि 1951 रहती है तो एक वह शख्स, जो जनरल जे जे सिंह के समाज का है, सिख समाज का, भारत का थल सेनाध्यक्ष नहीं बन पाएगा. इसीलिए उन्होंने काग़ज़ खंगाले और उन काग़ज़ों में हाथ से लिखे हुए यूपीएससी के फॉर्म को निकाला, जिसे बाद में ख़ुद यूपीएससी ने बदल दिया. उन्होंने अपने यहां यह नोट लिखा कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 1950 मानी जाए, न कि 1951. सेना का सिपाही जो सीमा पर है या सेना का वह सिपाही जो बैरक में है, वह हतप्रभ है और उसके मन में एक संदेह पैदा हो रहा है कि क्या उसका जनरल अपनी जन्मतिथि को लेकर झूठ बोल रहा है? क्या उसका जनरल जिसके ऊपर अभी तक कोई दाग़ नहीं है, उसने सिर्फ़ 10 महीने का एक्सटेंशन पाने के लिए झूठ बोला या झूठे दावे कर रहा है? यह संदेह भारतीय सेना के एक गौरवशाली सिपाही, जो भारत का थल सेनाध्यक्ष बना, के ऊपर एक दाग़ है, धब्बा है. इस धब्बे को साफ़ करने की ज़िम्मेदारी मुख्यत: सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का दायित्व है कि वह अपने उन लोगों के हितों की रक्षा करे, जो सरकार नाम की संस्था की नींव होते हैं.

भारत का थल सेनाध्यक्ष या तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष ऐसे ही खंभे हैं, जिनके ऊपर सरकार टिकी होती है, लेकिन सरकार ख़ुद अपने ही खंभे या अपने ही आधार की बेइज़्ज़ती करने या उसकी शान को धुंधलाने में लग गई है. क्या रास्ता है? एक रास्ता है कि जनरल वी के सिंह इस दाग़ को लिए हुए चुपचाप सेना से रिटायर हो जाएं. दूसरा रास्ता यह है कि जनरल अपने इस दाग़ को धोने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाएं. जहां तक हमें पता है, भारत के थल सेनाध्यक्ष सबके पास अपना रिप्रेजेंटेशन भेज चुके हैं. सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में मनमोहन सिंह की सरकार ने यह फ़ैसला लिया है कि जनरल की किसी भी बात को न सुना जाए और उन्हें ज़बरन अगले साल 31 मई को रिटायर कर दिया जाए तथा उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को भारत का थल सेनाध्यक्ष बनाया जाए. जनरल बिक्रम सिंह कैसे भी जनरल हों या उन पर जो भी आरोप लग रहे हों, सांसद उनके ख़िलाफ़ चिट्ठी लिख रहे हों, उससे हमारा यहां कोई मतलब नहीं है. हमारा मतलब सिर्फ़ इतना है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में होना चाहिए या नहीं और 2006 तक इस मसले को क्यों नहीं उठाया गया? 2006 में ही इस मसले को क्यों उठाया जनरल जे जे सिंह ने? जनरल दीपक कपूर ने इस मसले का हल क्यों नहीं निकाला? दोनों किस इंटरेस्ट की वजह से इस मसले को टालते रहे, क्योंकि उनकी यह हिम्मत तो नहीं थी कि वे आख़िरी फ़ैसला कर सकें. उन्होंने इस फ़ैसले को टाल दिया.

लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के ऊपर एक आरोप यह भी है कि उनकी बहू पाकिस्तानी मूल की है और इन दिनों शायद वह अमेरिका की नागरिक हो गई है. अमेरिका का नागरिक तो फाई भी था. वही फाई, जिसके सेमिनार में हमारे देश के बड़े-बड़े पत्रकार जाने लगे थे. अभी एक महीना नहीं बीता है, जब अमेरिका ने फाई को गिरफ्तार किया और इस आरोप में कि वह आईएसआई से पैसा लेकर हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर के सवाल पर बोलने के लिए उकसाता था और हमारे बुद्धिजीवी हिंदुस्तान के हितों के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलते थे.

भारत की थलसेना गौरवशाली सेना है. भारत की थलसेना देश की सीमाओं की रखवाली करती है. भारत की थलसेना किसी भी आपदा में देश के लोगों की मदद करती है. वह इस देश का गौरव है. उस सेना के एक जनरल की जन्मतिथि का विवाद ख़ुद पैदा करना, उसके बाद उसे हवा देना और ख़बरें लीक करना, कुछ ऐसा है, मानों हम अपने आप अपनी आंख फोड़ रहे हैं या अपनी नाक काट रहे हैं. हम नहीं जानते, भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है. वे कौन सी ताक़तें हैं, जो 40 हज़ार करोड़ के होने वाले सौदे के ऊपर नज़रें लगाए हुए हैं? भारत की सेना को इस सामान को ख़रीदना है. मौजूदा जनरल इसमें शायद पड़ना नहीं चाहते. अगर जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 1950 रहती है तो जनरल बिक्रम सिंह नए सेनाध्यक्ष होंगे और इस सामान को ख़रीदेंगे और यदि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि 1951 रहती है तो लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक नए सेनाध्यक्ष होंगे और तब वह इस सामान को ख़रीदेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनायक जनरल वी के सिंह की तरह निहायत ईमानदार और साफ़–शफ़्फ़ाफ़ इंसान हैं. हिंदुस्तान की सेना में इन दोनों जनरलों को लोग सैल्यूट करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हथियार माफ़िया के लिए शायद यह सबसे बड़ी डिसक्वालीफिकेशन है. इसलिए उसका इंटरेस्ट है कि जनरल वी के सिंह या तो अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दें या जल्दी से जल्दी इस्तीफ़ा देकर रिटायर हो जाएं, ताकि लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह को इस पद पर आने का मौक़ा मिल सके.

हम लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमें इतनी चिंता ज़रूर है कि हिंदुस्तान की सेना में अब ऐसा कोई आदमी चीफ नहीं बनना चाहिए, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हों. संसद के एक सदस्य ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के ऊपर आरोप लगाए हैं. इन आरोपों का कोई जवाब अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है. लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह के ऊपर एक आरोप यह भी है कि उनकी बहू पाकिस्तानी मूल की है और इन दिनों शायद वह अमेरिका की नागरिक हो गई है. अमेरिका का नागरिक तो फाई भी था. वही फाई, जिसके सेमिनार में हमारे देश के बड़े–बड़े पत्रकार जाने लगे थे. अभी एक महीना नहीं बीता है, जब अमेरिका ने फाई को गिरफ्तार किया और इस आरोप में कि वह आईएसआई से पैसा लेकर हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर के सवाल पर बोलने के लिए उकसाता था और हमारे बुद्धिजीवी हिंदुस्तान के हितों के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलते थे. प्रधानमंत्री क्यों इन आरोपों के जवाब नहीं दे रहे, यह तो वही जानें, लेकिन देश नज़र गड़ाए हुए है कि अगर प्रधानमंत्री एक ऐसे जनरल को सेना का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर दाग़ है और जिसकी सफ़ाई ख़ुद प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं तो हमें लगता है कि इस देश में आने वाले दिन थोड़ी ज़्यादा परेशानी के होने वाले हैं.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

हाथी, चूहा और कांग्रेस

मेघनाद देसाई

हाथी जंगल का राजा था. उसका वजन एक टन और लंबाई 15 फीट थी. जंगल के अन्य जानवरों को उसकी बात माननी पड़ती थी. वह जंगल में उपद्रव करता और जो दिखाई पड़ता, उसे नष्ट कर देता था. वह एक चूहे के सामने आया. एक दांत और सुंदर पूंछ वाला यह चूहा मुश्किल से 4 इंच का था. हाथी ने कहा कि यह चूहा जंगल के लिए ख़तरनाक है. इसकी पूंछ ख़तरनाक हो सकती है. इसे जंगल से बाहर किया जाना चाहिए. जंगल के अन्य जानवर यह नहीं समझ सके कि हाथी इस चूहे से इतना डरा हुआ क्यों है. हाथी ने कहा कि उसने दस साल पहले इस चूहे को सड़ा पनीर खाते हुए देखा था, अत: यह चूहा भी अब सड़ गया है. उधर चूहे ने जंगल छोड़ने से इंकार कर दिया. वह वहीं रुका रहा. हाथी जितना अधिक गरजता, चूहे की पूंछ उतनी ही बढ़ती जाती. अंत में हाथी चूहे की लंबी पूंछ में उलझ गया और उसे चूहे से ख़ुद को छोड़ने के लिए कहना पड़ा. चूहा समझौता करने को तैयार नहीं था. उसने कहा कि हाथी अगर छूटना चाहता है तो उसे जंगल में उपद्रव करना और अन्य जानवरों को धमकाना बंद करना पड़ेगा.

पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि ताक़तवर सरकार नागरिक समाज के दबाव के आगे झुक गई. लोकपाल को लेकर जो हालात बने हैं, उनमें किसी अन्य लोकतंत्र में कम से कम एक कैबिनेट मंत्री अब तक अपना इस्तीफ़ा दे चुका होता. अप्रैल में यूपीए के साथ अन्ना हजारे का समझौता हुआ. यह लगभग उसी तरह था, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्वकप जीता था. अगस्त में भारतीय क्रिकेट टीम की तरह कांग्रेस ने लीपापोती कर दी. इस बीच क्या परिवर्तन हो गया? मेरा अपना मानना है कि सोनिया गांधी को इलाज के लिए अमेरिका क्या जाना पड़ा, कांग्रेस निस्सहाय हो गई. दरअसल, कांग्रेस 10 जनपथ से सलाह लेने की आदी हो गई है. पिछले कुछ वर्षों के दौरान कांग्रेस ने किसी भी स्वतंत्र सोच या निर्णय को सिर्फ़ हतोत्साहित ही किया है और अब यह स्थिति नियंत्रण के बाहर होने की वजह से कांग्रेस दिशाहीन हो गई है. चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में मिली वैधता के कारण अन्ना के मुक़ाबले सरकार के पास एक बेहतर मौक़ा था. कई वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ताओं द्वारा इसी समय अन्ना को बदनाम करने की कोशिश भयावह और दयनीय थी. यह तो ज़ाहिर था कि कांग्रेस किसी भी तरह के विरोध को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो. अन्ना पर 2.2 लाख रुपये के दुरुपयोग का आरोप लगाने का विचार हास्यास्पद था.

इस मोड़ से ही कांग्रेस की हार की शुरुआत हो गई. कांग्रेस का यह कहना कि कोई बिल जब संसद में हो, तब उसका विरोध करना ठीक नहीं है, एक अर्थहीन बात है. किसी भी लोकतंत्र में जनता किसी बिल के संसद में होने या उसके पारित होने से पूर्व या बाद में भी उसका विरोध कर सकती है. मैं ख़ुद फोक्स हंटिंग बिल के विरोध में पार्लियामेंट स्क्वायर पर भारी प्रदर्शन का गवाह रहा हूं. कांग्रेस ने भी लोक लेखा समिति और उसकी रिपोर्ट के मुद्दे पर संसद की उपेक्षा की और संयुक्त संसदीय समिति को भी पूरी तरह काम नहीं करने दिया गया. राहुल गांधी कांग्रेस को उबारने आए. सारे क़ानूनी दांव–पेंच और तकनीकी बातें धरी की धरी रह गईं. अन्ना को एक ऐसे सामान्य सांसद के आदेश पर रिहा कर दिया गया, जिसकी स्थिति कांग्रेस के महासचिव से ऊपर नहीं है. सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में चार लोगों के दल के आगे संसद की संप्रभुता का क्या अर्थ रह गया? क्या आप अन्ना का समर्थन कर रही भीड़ पर नेताओं पर विश्वास न करने का आरोप लगा सकते हैं?

पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि ताकतवर सरकार नागरिक समाज के दबाव के आगे झुक गई. लोकपाल को लेकर जो हालात बने हैं, उनमें किसी अन्य लोकतंत्र में कम से कम एक कैबिनेट मंत्री अब तक अपना इस्तीफ़ा दे चुका होता. अप्रैल में यूपीए के साथ अन्ना हजारे का समझौता हुआ. यह लगभग उसी तरह था, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्वकप जीता था.

feedback@chauthiduniya.com

नव उदारवाद और भ्रष्टाचार विरोध की राजनीति

प्रेम सिंह

हम यह नहीं कहते कि पूर्व प्रचलित पदों, अवधारणाओं एवं तरीक़ों का मौजूदा संदर्भों में नया अर्थ और प्रयोग नहीं हो सकता, बल्कि वह होना चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थवश या अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालने के लिए इनका रूप बिगाड़ देना इनके आविष्कारकों को लांछित करने के साथ–साथ संघर्ष की परंपरा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति द्रोह है. नव उदारवाद के हमाम में जो हालत धर्मनिरपेक्षता की हो चुकी है, वही गांधी और सत्याग्रह की होने जा रही है. दुनिया को स्वास्थ्य और शक्ति के नुस्खे बांटने वाले रामदेव चार दिनों के अनशन में बेहाल हो गए. नुस्खे वह आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के भी बांटते हैं, लेकिन भोगियों के इस योगी में न आध्यात्मिक शक्ति का लेश निकला, न शारीरिक शक्ति का. आपको याद होगा, कुछ साल पहले इनके कारखाने में बनने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता और काम करने वाले मज़दूरों के शोषण पर सवाल उठे थे. बाबा हल्की पेंदी के तवे की तरह गरम हो गए थे और अनर्गल प्रलाप करने लगे थे. नव उदारवाद की प्रयोगशाला में ऐसे ही योगी ढलते हैं.

अपने आर्थिक साम्राज्य को संभालने में लगे रामदेव का बयान आया है कि वह फिर आंदोलन करेंगे. कारण, उनके एक प्रमुख कारकुन बालकृष्ण को सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है. हजारे ने अपने सत्याग्रह का रामदेव जैसा हश्र न होने देने के लिए पहले से अदालत की शरण लेने की घोषणा की. सत्याग्रही अपनी मृत्यु का ख़ुद निर्णायक और ज़िम्मेदार होता है. उसे जान बचाकर भागने या कोर्ट–कचहरी की शरण लेने की ज़रूरत नहीं होती. रामदेव पर थोड़ी चर्चा और की जा सकती है. उन्होंने सरकार के साथ हुए समझौते की सूचना समर्थकों को न देकर भले ही दगाबाज़ी न की हो, अनशन स्थल से भागकर ज़रूर समर्थकों के साथ धोखा किया. दरअसल अकूत दौलत, ज़ाहिर है जो कुछ सालों में सदाचार की कमाई या सदाचार की कमाई के दान से नहीं जुट सकती और शोहरत पाकर बाबा को औंघाई लगी है. यह सच्चाई मीडिया ने खुलकर नहीं बताई कि अनशन स्थल छोड़कर भागे बाबा के प्रति अनेक लोगों की भावना ठगे जाने जैसी थी. दिग्विजय सिंह द्वारा बाबा को ठग बताने पर राम जेठमलानी पूरी कैबिनेट को ठगों का अड्डा बताते हैं. इस ठग विमर्श पर क्या कहा जाए? ठग ही जाने ठग की भाषा!

कांग्रेस का आरोप है कि बाबा रामदेव आरएसएस के एजेंट हैं, लेकिन बाबा के हौसले देखिए, वह आरएसएस को अपनी जेब में धरा हुआ मानते हैं. बाबा सयाने हैं और आरएसएस की फितरत को जानते हैं कि वह किसी की भी जेब में जाने को तत्पर रहता है, जेपी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अमेरिका तक. सेकुलर नागरिक समाज बाबा को आरएसएस के चंगुल से निकालने की रणनीति बनाना चाहता है, ताकि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई को सांप्रदायिकता से बचाया जा सके. हमें भी इस बाबत दो–चार साथियों के फोन आते हैं. नागरिक समाज को अभी भी शायद स्पष्ट नहीं हुआ है कि संकीर्णता और सांप्रदायिकता में बाबा आरएसएस के भी बाप हैं. हमने संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी नागरिकों और संगठनों की तरह रामलीला मैदान में यूपीए सरकार द्वारा आधी रात के समय की गई दमनकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा की. रामदेव तो भाग निकले और उन्हें सवारी के लिए सरकारी हवाई जहाज मिल गया, लेकिन दूरदराज से आईं हज़ारों स्त्रियों, बच्चों एवं पुरुषों पर दिल्ली पुलिस का जो कहर बरपा, उसे शर्मनाक के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता. अगर वे सब नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भी आए होते तो भी हम पुलिस दमन का वैसा ही विरोध करते. हालांकि निर्दोषों पर हुए पुलिस दमन से नाराज़ नागरिकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के कई भागों में पुलिस और सुरक्षाबलों का ही राज चलता है. भले ही केंद्र और राज्यों में सरकार किसी की हो. पीयूसीएल, पीयूडीआर जैसे नागरिक संगठनों की रपटें और ख़ुद सरकार के आंकड़े देखे जा सकते हैं कि बहुत से निर्दोष नागरिक राज्य सत्ता ने जेलों में ठूंस रखे हैं. आशा करनी चाहिए कि राजधानी में आपातकाल जैसा दृश्य देखने के बाद संवेदनशील और सचेत नागरिक देश की इस प्रताड़ित जनता के संवैधानिक और जीवनाधिकारों के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे.

कांग्रेस ने अन्ना हजारे और रामदेव को आरएसएस का मुखौटा कहा है, लेकिन समस्या यह है कि वह ख़ुद इन्हें अपना मुखौटा बनाने की हर कवायद करती है और सफल न होने पर आरएसएस के पाले में धकेलती है. मंशा साफ है कि आरएसएस की बढ़ती मज़बूती देखकर पहले की तरह मुसलमान कांग्रेसी छत्रछाया में आ जाएं. दलितों की घर वापसी का काम राहुल गांधी दलितों के घरों में जाकर करने लगे हैं. इतिहासकार रामचंद्र गुहा से लेकर साहित्यकार गिरिराज किशोर तक बता रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति का नया पाठ गढ़ रहे हैं. गिरिराज किशोर ने तो राहुल गांधी द्वारा दलितों के घरों में जाकर रहने को गांधी की अहिंसक छापामारी से जोड़कर दिखाया है. के एम पणिक्कर और रोमिला थापर ने दि हिंदू में साझा लेख लिखा है कि नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी के नए निदेशक महेश रंगराजन नेहरू के सपनों को साकार करने के लिए बनी इस संस्था के स्तर को गिरने से बचाएंगे, जो इनके मुताबिक़ पिछले दस वर्षों से लगातार गिरता गया है. शायद इन दोनों विद्वानों ने महेश रंगराजन द्वारा राहुल गांधी की प्रशंसा में कसे कसीदे नहीं पढ़े हैं. बुद्धिजीवियों की यही खासियत होती है कि जो कौड़ी राहुल गांधी के मैनेजरों के हाथ नहीं आई, वह उन्होंने खोज निकाली. कांग्रेस ने सेकुलर बुद्धिजीवियों पर शुरू से ही बड़ा भरोसा किया है. ये बुद्धिजीवी भी कांग्रेस के साथ कभी विश्वासघात नहीं करते. ऊपर से अमेरिका है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, चुनाव जीत लिया जाएगा. तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि रामलीला मैदान की कार्रवाई अनिवार्य थी.

दरअसल, कांगेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी को जूता दिखाने वाले शख्स ने गलत सवाल पूछा कि कांग्रेस विपक्ष नहीं चाहती है. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस केवल संघ–भाजपा को विपक्ष के रूप में रखना चाहती है. इससे उसके अनेक कारज सधते हैं. संघ–भाजपा के रहते सोनिया गांधी के सेवक और सेकुलर सिपाही कांग्रेस के साथ रहते हैं. इससे भाजपा को सत्ता में न आने देने में भरपूर सहायता मिलती है और अगर कुछ समय के लिए वह आ भी जाए तो उसकी नाक में दम किया जा सकता है. इस छोटे कारज से बड़ा कारज सधता है कि नव उदारवाद के विरोध की राजनीति नहीं पनप पाती. 1857 से लेकर 1942 तक, क्रांतिकारियों से लेकर गांधीवादियों तक देश की आज़ादी और गौरव के लिए लड़ने वालों में जो भी चूकें रही हों, कायरता नहीं थी, उन्होंने लालच के रोग से भी छुटकारा पा लिया था, बल्कि कायरता और लालच के जातीय रोग को काटकर ही वे सत्याग्रही अथवा क्रांतिकारी बनते थे. जो कायरता और लालच के रोग को पूरी तरह नहीं काट पाते थे, रास्ते में टूट जाते थे. गांधी की अहिंसा और क्रांतिकारियों की हिंसा भारत के कायरता और लालच के जातीय रोग को नहीं काट पाई. आज़ादी के संघर्ष के चलते वह अधूरा–छूटा काम आज़ादी के बाद पूरा होना था, लेकिन आज़ादी के बाद न गांधी की चली, न क्रांतिकारियों की. हालांकि दोनों की विरासत के दावेदारों की कभी कमी नहीं रही. कारण जो भी रहे हों, फ़िलहाल वतन कायरों और लालचियों के हवाले है. हम अपने क्षेत्र की सच्चाई जानते हैं. भारत के उच्च शिक्षण संस्थान कायर और लालची बनाने के कारखाने बनते जा रहे हैं.

लोहिया ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वोट, फावड़ा और जेल का सूत्र दिया था. अन्याय के प्रतिरोध में बार–बार जेल जाना समाजवादियों की पहचान बन गई थी. यही कारण था कि आपातकाल में अकेले समाजवादियों ने जेल की परवाह नहीं की. आजकल के समाजवादी जेल जाने की बात छोड़िए, थाने तक जाने की बात आते ही पीछे खिसकने लगते हैं. डरा हुआ व्यक्ति सत्याग्रही नहीं हो सकता. भ्रष्टाचार या किसी भी मुद्दे अथवा समस्या पर आंदोलन करने वाले लोग अगर किसी विचारक, नेता अथवा कार्यप्रणाली का नाम लेते हैं तो कुछ न कुछ मर्यादा का पालन उन्हें करना चाहिए. बेहतर तो यह होगा कि वे अपने काम और तरीक़े की ज़िम्मेदारी ख़ुद ही लें. इससे कम से कम नई पीढ़ियों में भ्रम नहीं फैलेगा. अंत में कह सकते हैं कि उपनिवेशवादी दौर से प्रशासन और नीतियों की जड़ों में पैठा भ्रष्टाचार नव उदारवादी दौर में आसमान छू चुका है. अगर गांधी होते तो कहते, हम भ्रष्टाचार करना छोड़ दें तो वह अपने आप मिट जाएगा. यानी भ्रष्टाचार पैदा करने वाली व्यवस्था से अपना समर्थन वापस ले लें, लेकिन भ्रष्टाचार को परवान चढ़ाने वाली नव उदारवादी व्यवस्था और उसकी नीतियों को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता. भारत में नव उदारवादी व्यवस्था के भगीरथ मनमोहन सिंह टीम हजारे और रामदेव दोनों के हीरो हैं. फ़िलहाल तो एक ही सूरत बचती नज़र आती है. नव उदारवादी नीतियों से बदहाल देश की अधिकांश जनता जनांदोलनकारियों और नागरिक समाज एक्टिविस्टों से अलग खउुद विचार और संघर्ष करे.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं समाजवादी चिंतक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

भ्रष्टाचार और भारत

देश में भ्रष्टाचार चरम पर है. सरकार जनहित के बजाय पूंजीपतियों के हित साधने में लगी है. सत्ताधीशों को अपनी कुर्सी संभालने से ही फ़ुर्सत नहीं है, ऐसे में वे जनता के बारे में क्या सोचेंगे? जनता की भलाई के नाम पर अनेक योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन आम आदमी को उसका कोई लाभ नहीं मिलता. इन योजनाओं के लिए जारी किए गए अरबों रुपये राजनेताओं और नौकरशाहों की जेब में चले जाते हैं. हर बार नई योजना, नई बंदरबांट. विकास के नाम पर यही सब चलता रहता है. देश में क़ानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है. उद्योगपतियों, राजनेताओं, नौकरशाहों और माफ़ियाओं का राज है, आम जनता बेबस है.

–राम गुल्हाने, अमरावती, *महाराष्ट्र.*

ऐतिहासिक इमारतों की बदहाली

देश की ऐतिहासिक इमारतों की हालत दयनीय है. जिन ऐतिहासिक इमारतों से सरकार को आमदनी होती है, उनके रखरखाव पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन छोटे–बड़े क़स्बों में स्थित इमारतों को तवज्जो नहीं दी जाती. देखभाल न होने के कारण अनेक ऐतिहासिक स्थल लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं. इन इमारतों पर क़ब्ज़े कर लिए गए हैं. लोग इन इमारतों को तोड़कर अपने मकान बना रहे हैं.

–सरफ़राज़ ख़ान, *हिसार, हरियाणा.*

दुर्लभ पांडुलिपियां

तिब्बत में भारतीय पांडुलिपियों के 50 हज़ार से ज़्यादा पेज संरक्षित हैं. इनमें से कुछ बहुमूल्य एवं दुर्लभ पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी हैं. इन पांडुलिपियों को छांटने, फोटो कॉपी करने और पंजीकरण का काम 2006 में शुरू किया गया था, जो अब पूरा हो चुका है. ये पांडुलिपियां तिब्बती और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं में लिखी हैं. इनमें से कुछ ताड़ के पत्तों पर लिखी दुर्लभ एवं बहुमूल्य पांडुलिपियां हैं. ताड़पत्र पांडुलिपियों का संबंध भारत से है. इन पर संस्कृत भाषा में बुद्ध ग्रंथ, प्राचीन भारतीय साहित्य और कोड लिखे हुए हैं. तिब्बत अब दुनिया की उन जगहों में शामिल हो गया है, जहां सबसे ज़्यादा संस्कृत ताड़पत्र पांडुलिपियां पंजीकृत हैं.

–असलम ख़ान, *दिल्ली.*

पंचायतों में भ्रष्टाचार

बिहार में पंचायतों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है. सरकारी योजनाओं में लूटखसोट चल रही है. पंचायतों में शुद्धिकरण की आवश्यकता है. बिना शुद्धिकरण के पंचायती राज का सपना पूरा नहीं किया जा सकता. प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए शराब और नक़दी के माध्यम से मतदाताओं को लुभाते हैं. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं पर धन ख़र्च करने पर सख्ती से रोक लगाने की ज़रूरत है.

–प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार.*

दोषी अफ़सरों के नाम उजागर हों

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख–षड्यंत्र के साये में इंडियन आर्मी, प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, पढ़ा. यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला है. देश की सुरक्षा में कहीं सेंध तो नहीं लग गई? काफ़ी साल बीत चुके हैं, जब कुछ सैन्य अफ़सर कांगो में एक सेक्स स्कैंडल में उलझ गए थे, उन अफ़सरों के नामों का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि उनकी ग़लती से देश का नाम ख़राब हुआ था.

–डॉ. कर्नल राजेंद्र चौहान, *ईमेल से.*

यूआईडी की उपयोगिता

यूआईडी कार्ड बनाने का कार्य केंद्र सरकार का गोरखधंधा है. यह कार्ड जनता के किसी काम का नहीं है. भारत से ज़्यादा विकसित देशों में सर्वे हो चुके हैं, लेकिन इसके फ़ायदे कम और नुक़सान ज़्यादा हैं, इसलिए वहां इस योजना को बंद कर दिया गया. सरकार जनता के पैसे ऐसे फ़ालतू निर्णय लागू करके उड़ाना चाहती है, जिससे उसके मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने के अवसर मिल सकें.

–दुर्गा शंकर, *ईमेल से.*

देश में बसते थे इंसान

कभी भारत देश में बसते थे इंसान,
करते थे देश और देशवासियों का सम्मान.
देश में हो चैन–ओ–अमन, जिनका था अरमान,
आज़ादी के लिए कर दी थी अपनी जां क़ुर्बान.
अब बस्ते हैं यहां इंसानों जैसे दिखने वाले शैतान,
करते हैं सिर्फ़ अपनी और अपनी ज़रूरतों का सम्मान.
दिल में दर्द तो इतना है कि नहीं कर सकता बयान,
लेकिन हम कल भी थे महान और आज भी हैं महान.
हमारा भारत महान, हमारा भारत महान...

–सन्नी वर्मा, *कानपुर, उत्तर प्रदेश.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

सटीक काम करने वाले रोबोट सर्जरी में क्रांति का कारण बन सकते हैं, लेकिन सबको उन पर विश्वास नहीं है.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 05 सितंबर–11 सितंबर 2011

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई का दुश्मन कौन है

इस अंक में हम उन कारणों की चर्चा कर रहे हैं, जिनकी वजह से जनता के लोकतांत्रिक हथियार सूचना के अधिकार क़ानून को कमज़ोर बनाने की साजिश रची जाती है. आज ऐसे कारणों और उनके समाधान के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है.

जुर्माना नहीं लगता

केंद्र और राज्यों के लगभग तमाम सूचना आयुक्त सूचना न देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने से बचते रहे हैं. यहां तक कि जनता की मांग पर आयुक्त बनाए गए शैलेष गांधी भी अपनी श्रेष्ठता एक दिन में अधिक से अधिक मामले निपटा कर दिखाने में लगे हैं, जबकि यह साफ हो चुका है कि यदि जुर्माने का प्रावधान न होता तो सूचना अधिकार क़ानून के तहत सूचना कभी मिलती ही नहीं.

दुरुपयोग बताना ग़लत

भ्रष्ट अफसरों और नेताओं के साथ-साथ देश के लगभग सभी सूचना आयुक्त यह कहते मिल जाएंगे कि सूचना अधिकार क़ानून का इस्तेमाल अच्छे लोग नहीं कर रहे हैं, ग़लत लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं. क्या एक आदमी जो रिश्वत नहीं देता, उसे यह जानने का हक़ नहीं है कि उसके पासपोर्ट आवेदन का क्या हुआ? क्या किसी ग़रीब को यह जानने का हक़ नहीं है कि उसके हिस्से का राशन कहां जा रहा है?

लंबित मामलों की संख्या

सूचना आयोगों की सुस्ती का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग ने सात सूचना आयुक्त होने के बावजूद 2008 में मात्र 880 मामलों की सुनवाई की. महाराष्ट्र सूचना आयोग का ऑडिट करने पर पता चला कि आयोग के छह सूचना आयुक्त प्रतिदिन औसतन 5 अपीलों या सुनवाइयों को निस्तारित करते हैं. कर्नाटक सूचना आयोग की स्थिति यह है कि मार्च 2009 के अंत तक वहां लंबित मामलों की संख्या 5200 थी. पश्चिम बंगाल सूचना आयोग ने तीन सालों में मात्र 116 मामलों की सुनवाई की.

जेल का डर

सूचना आयुक्त आवेदकों या कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने से लेकर उन्हें जेल भिजवाने में भी नहीं हिचकते. महाराष्ट्र सूचना आयोग के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश जोशी के आदेश पर मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णराज राव और उनके 11 साथियों के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था.

सूचना के बदले पैसों की मांग

गाज़ियाबाद के कुलदीप सक्सेना ने बिजली विभाग से अपने इलाक़े के बिजलीघर की क्षमता और तीन महीने की सप्लाई के बारे में जानकारी मांगी तो विभाग ने उनसे कहा कि यह सूचना देने के लिए उसे एक कर्मचारी लगाना पड़ेगा, जिस पर 5000 रुपये का ख़र्च आएगा. इसी तरह भोजपुर ज़िले के गुप्तेश्वर सिंह ने राशन विभाग से अनाज और मिट्टी के तेल के बारे में सूचना मांगी तो उनसे 78 लाख रुपये की मांग की गई. यह हथकंडा देश के सैकड़ों लोक सूचना अधिकारी आज़मा रहे हैं.

कैसे-कैसे बहाने

सूचना क़ानून के तहत सूचना न देने के लिए लोक सूचना अधिकारी ऐसे अजीबोग़रीब तर्क देते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता. उत्तर प्रदेश सूचना आयोग किसी संस्था के लेटरहेड पर सूचना मांगने पर आवेदन निरस्त कर देता है. जम्मू-कश्मीर निर्वाचन आयोग की तरफ़ से एक आवेदक को पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि आवेदन हिंदी के बजाय अंग्रेजी में भेजें और कहीं-कहीं उर्दू में दिया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता.

आवेदन शुल्क का पेंच

आवेदन के संदर्भ में शुल्क का पेंच इस तरह फंसा है कि उसने एक सामान्य से क़ानून का इस्तेमाल भी पेचीदा बना दिया है. एक तरफ़ हरियाणा जैसे राज्यों में सूचना अधिकार क़ानून के तहत आवेदन करने के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं, वहीं अरुणाचल में यह शुल्क 10 रुपये से 500 रुपये तक है. उच्च न्यायालयों में तो यह शुल्क 500 रुपये कर ही दिया गया है. जहां 10 रुपये शुल्क है, वहां भी हाल बेहाल है. नकद की रसीद नहीं, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर किस नाम से बनेगा, यह भी कोई बताने को तैयार नहीं.

पीआईओ या बदमाश

जागरूक आदमी जेल में सड़ते हैं या किसी गली में मरे पड़े मिलते हैं. यह बात उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने लखनऊ के सलीम बेग से कही थी. बेग ने सूचना अधिकार क़ानून के तहत कांस्टेबल पद के लिए चयनित उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी मांगी थी. बीएसएनएल आजमगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी आरटीआई आवेदनों से इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने सूचना मांगने वाले स्थानीय निवासी रवि कुमार मौर्य की कार्यालय में ही पिटाई कर दी, साथ ही झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया.

धारा 8 का दुरुपयोग

तमिलनाडु के सी. रमेश ने जब आरटीआई के तहत फरवरी 2002 से मार्च 2002 के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी तो सूचना क़ानून की धारा 8 (1)(ए) का हवाला देते हुए उन्हें सूचना देने से मना कर दिया गया. कहा गया कि इसे सार्वजनिक किए जाने से देश की एकता और अखंडता पर विपरीत असर पड़ सकता है. दिल्ली के प्रमोद सरीन ने दिल्ली कॉलेज और इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होकर आरटीआई के तहत प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट की छाया प्रति मांगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया कि प्रश्नपत्र और उनके जवाब विश्वविद्यालय की बौद्धिक संपदा हैं, इसलिए उन्हें क़ानून की धारा 8 (1)(डी) के तहत नहीं दिया जा सकता.

सरकारी कर्मचारियों को धमकी

मध्य प्रदेश के देवास में केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी शिक्षक मांगीलाल कजोडिया ने अपने ही विद्यालय से सूचनाएं मांगीं तो पहले उन्हें कारगिल भेज दिया गया और बाद में नौकरी से ही निकाल दिया गया. रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में चालक पद पर कार्यरत ओंकार गुप्ता के साथ भी यही हुआ, जब उन्होंने अपने विभाग की तानाशाही को आरटीआई के माध्यम से उजागर किया. सूचना के बदले मिले जवाब में ओंकार की तनख्वाह ही कम कर दी गई. इसी तरह साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में कार्यरत मुजीबुर्रहमान ने जब अपनी ही कंपनी से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा किए गए धन की जानकारी मांगी तो उन्हें कंपनी के निदेशक की तरफ़ से धमकियां मिलनी शुरू हो गईं और उनके ख़िलाफ़ तमाम तरह की जांच बैठा दी गई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
साहित्यिक गतिविधियों का उदय होगा और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे. किसी दोस्त के समर्थन से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी. जल्दबाज़ी और लापरवाही से बचें. सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है. ऑफिस में सोच- समझ कर लिए गए फ़ैसले फ़ायदेमंद साबित होंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
पुरुषार्थ से ही साधन और संपन्नता बढ़ेगी. सबका हित सोचना आपकी फितरत है. आप ऑफिस के मामले में किसी बहुत बड़े काम को तो अंजाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपना भविष्य सुरक्षित बनाने की दिशा में ज़रूर कामयाब होंगे. खानपान के मामले में कंट्रोल रखने से आप एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
अच्छा मौसम और समझदारी का खुशगवार दौर हमेशा नहीं बना रहता. कोई नया दोस्त बनाने में कामयाब होंगे. घरेलू मामलों में पुराने समय से चला आ रहा तनाव ख़त्म हो जाएगा. बिजनेस के मामले में कोई शख्स आश्वासन देगा, जो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है. कोई ख़ुशख़बरी मिल सकती है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह विशेष परिश्रम के बावजूद मायूसी बनी रहेगी. नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कोई चर्चा होगी. काम के सिलसिले और प्यार के मामले में आपको दौड़भाग करनी होगी. थकान से बचने के लिए संगीत की शरण लें. मेहनत और लगन का अच्छा रिजल्ट आने के लिए कोई नया प्लान बनाना होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह कर्म करने के उपरांत ही सफलता मिलेगी. कुछ महत्वपूर्ण कामों में आ रही रुकावट दूर होगी. मनचाहे शख्स के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. किसी दोस्त अथवा सहकर्मी की समस्या को सुलझाने के लिए आपको आगे आना पड़ सकता है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आगंतुकों और भद्रजनों का आगत-स्वागत विशेष यश वृद्धि करेगा. किसी समस्या का हल निकल आएगा. आसपास की यात्रा का कार्यक्रम बनेगा, लेकिन उसे टाल देना फ़ायदेमंद होगा. ज़्यादा दौड़भाग न करें तो अच्छा होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
गाड़ी हमेशा रफ्तार से नहीं दौड़ती. तेज दौड़ना कभी-कभी नुक़सानदायक होता है. नए प्रोजेक्ट को लेकर दौड़भाग करने से फ़ायदा हो सकता है. टेंशन से बचें. कई मौक़े आपके रास्ते में आएंगे, उन्हें पहचान कर उनका फ़ायदा उठाना होगा. आपके आसपास दिलचस्प लोगों का जमघट लगेगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
किसी व्यक्ति से निराशा बढ़ने पर यदि लड़ाई करनी है तो फिर उस प्रवृत्ति से लड़ें, जिससे उसका भी हित हो और आपका भी. मंगल-बुध तक आपके सामने आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते होंगे. सोच-समझ कर एक रास्ता चुनना होगा. छोटे-मोटे झगड़े पैदा होंगे, पर जल्द ख़त्म हो जाएंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
जो लोगों को अच्छा लगता है, शायद आपको अच्छा न लगे. कोई भी फ़ैसला धीरज के साथ करें, जल्दबाज़ी से नुक़सान होने का डर है. अजनबी पर विश्वास न करें. कुछ लोग नए आइडियाज लेकर आएंगे, उन्हें ध्यान से सुनें, क्या पता कोई आइडिया क्लिक कर जाए. किसी अनुभवी शख्स से सलाह लें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह परिवार की ख़ुशी के लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा, तभी सफलता मिल सकती है. धन लाभ हो सकता है. हालांकि ऑफिस में सीनियर्स आप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूझबूझ के ज़रिए आप उन्हें अपना कायल बना लेंगे. खानपान का खास ध्यान रखें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह भक्ति और पूजा-अर्चना करने की मनोवृत्ति रहेगी. अत: किसी प्रकार का द्वेष ठीक नहीं है. परिवार की उम्मीदें और ज़रूरतें बढ़ सकती हैं. ऑफिस का मामला हो या बिजनेस का, विरोधियों और दुश्मनों से सावधान रहें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह कोई आपसे बहुत आशा लगाए बैठा है. अब यह आपके हाथ में है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं. प्यार के नए मामले में ख़ुद को न उलझाएं, पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह जान लें. प्रॉपर्टी के मामलों को पुख्ता बनाने के लिए ज़रूरी क़दम उठाने होंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

कौन बनेगा रोडपति

के बीसी से बहुत लोग करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन हांगकांग में इन दिनों एक रियलिटी शो की धूम है, जिसमें अमीर लोग हिस्सा ले रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें कम से कम पैसे मिल रहे हैं. हांगकांग के व्यापारियों के बीच इरवीन हुआंग एक जाना-माना नाम है, लेकिन जब कूड़ा जमा करने की बारी आई तो हुआंग ज़्यादा नंबर नहीं बटोर पाए. 46 वर्षीय हुआंग एक ऐसे टीवी रियलिटी शो में भाग ले रहे हैं, जिसमें बड़े-बड़े बिजनेसमैन और करोड़पति कुछ दिनों के लिए ऐसा काम करेंगे, जिसमें उन्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे. इस शो की रेटिंग रातोंरात बढ़ती जा रही है. मास्क लगाए, एप्रन और हाथों में रबर के दस्ताने पहन कर सड़े हुए कचरे को डंप करने के बाद हुआंग कचरे के ढेर से निकले. लेकिन कचरे की बदबू से वह इतना परेशान हो गए कि उन्होंने शो छोड़ने तक की धमकी दे डाली. हुआंग अपने सुपरवाइज़र से शिकायत करते हैं, यह बहुत बदबूदार है. मुझे ताजी हवा चाहिए. मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता. हुआंग को क़रीब 6 डॉलर प्रतिदिन मिलते हैं. हुआंग अपने सुपरवाइज़र से कहते हैं, मेरे हाथों को देखो, ये फूल गए हैं. गंदे पानी की वजह से ऐसा हुआ है, यह बहुत कठिन काम है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे थोड़ा आराम करना है. द बैटल ऑफ द पुअर रिच नामक इस रियलिटी शो में हुआंग का भी एपिसोड दिखाया गया. हांगकांग के टीवी चैनलों पर यह शो 2009 से दिखाया जाना शुरू हुआ.

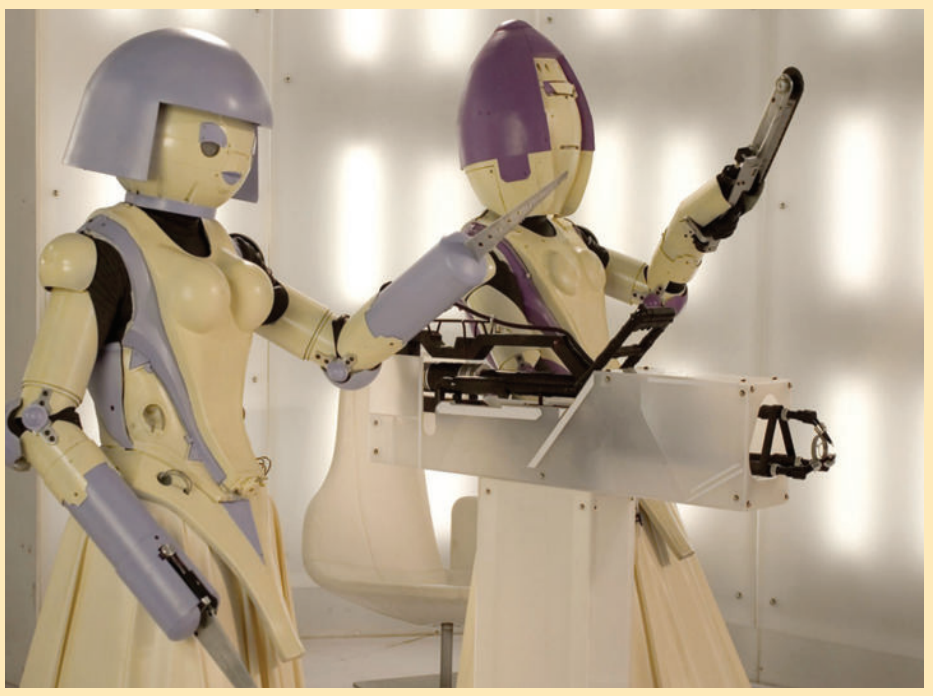

कमाल का डॉक्टर

आयरलैंड में 2007 में कॉर्क यूनिवर्सिटी के मैटरनिटी अस्पताल में पहली बार गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में रोबोट का इस्तेमाल किया गया था. उसके नतीजों को देखकर अस्पताल ने ऑपरेशन में रोबोट का इस्तेमाल बढ़ा दिया है. आयरलैंड का एक अस्पताल यूरोप का पहला ऐसा अस्पताल है, जहां ऑपरेशन के लिए रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है. सटीक काम करने वाले रोबोट सर्जरी में क्रांति का कारण बन सकते हैं, लेकिन सबको उन पर विश्वास नहीं है. जून से यह यूरोप का इकलौता अस्पताल बन गया है, जहां अति आधुनिक रोबोट को कैंसर या सामान्य, लेकिन जटिल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही यह अस्पताल यूरोप के डॉक्टरों के लिए वह जगह बन गया है, जहां वे इस नए चिकित्सा उपकरण को देख और समझ सकते हैं. अमेरिका की इंट्यूटिव सर्जिकल कंपनी दा विंची सर्जिकल रोबोट्स बनाती है. इनमें बहुत छोटे-छोटे उपकरण और कैमरे लगे होते हैं, जो डॉक्टर नियंत्रित करते हैं. दा विंची रोबोट इस्तेमाल करने वाले डॉ. मैट हेविट कहते हैं, पारंपरिक की होल सर्जरी की तुलना में रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा यह है कि डॉक्टर को थ्री डाइमेंशनल व्यू दिखाई देता है और इसलिए इसमें एक गहराई भी दिखाई देती है, जो की होल सर्जरी में नहीं दिखाई देती. रोबोट की मदद से किए जाने वाले ऑपरेशन सामान्य लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन की तरह होते हैं, जिनमें शरीर में एक छोटा सा छेद करके ऑपरेशन किया जाता है. इस छेद से ही शरीर में कैमरा या उपकरण डाले जाते हैं. मशीन के हाथ जैसे हिस्से रोबोट ही होते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे किसी कार फैक्ट्री में देखे जाते हैं. दा विंची नामक रोबोट के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले तीन हाथ हैं, जो 360 डिग्री पर घूम सकते हैं. इससे डॉक्टर अपने हाथ की तुलना में ज्यादा सूक्ष्मता से ऑपरेशन कर सकते हैं. रोबोट में एक चौथा हाथ भी होता है, जिसमें 3-डी हाई डेफिनेशन कैमरा लगा होता है. ऑपरेशन करते समय डॉक्टर थ्री डी कैमरे से पूरी तस्वीर देख सकता है, जो ऑपरेशन को और सटीक बनाता है. है न कमाल का डॉक्टर!

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अगर गद्दाफ़ी का पतन होता है, जो लगभग तय माना जा रहा है तो अमेरिका जैसे देश वहां की नई सरकार पर अपनी नीति थोपने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र वहां के तेल और गैस के भंडारों पर है.

गद्दाफी और लीबिया का भविष्य

राजीव कुमार

अफ्रीका में परिवर्तन की बयार बह रही है. सूडान में गृह युद्ध का अंत उसके विभाजन के साथ हुआ. मिस्र और ट्यूनीशिया में सत्ता के विरुद्ध आंदोलन हुए और सफल भी हुए. इसके साथ ही फरवरी 2011 के मध्य में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ़्तारी के बाद लीबिया में सरकार का विरोध शुरू हुआ, जो देखते-देखते सत्ता को चुनौती देने लगा और उसने कभी लीबिया के नायक रहे कर्नल मुअम्मर गद्दाफ़ी को खलनायक बना दिया. पिछले सात महीने से चल रहे इस संघर्ष का अंत कभी भी हो सकता है. विद्रोहियों ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली स्थित ग्रीन स्क्वॉयर पर भी क़ब्ज़ा कर लिया. विद्रोही गद्दाफ़ी परिसर के नाम से मशहूर बाब-अल अजीजिया में भी घुस गए, उन्होंने परिसर स्थित ग़द्दाफ़ी की मूर्ति को तोड़ दिया. आंदोलनकारियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए कर्नल गद्दाफ़ी की टूटी मूर्ति को अपने पैरों से रौंद डाला. इन लोगों ने परिसर में मौजूद उस प्रतीक को भी तोड़ दिया, जिसमें एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मुट्ठी में पकड़े हुए दिखाया गया था. अस्सी के दशक में कर्नल गद्दाफ़ी के परिसर में हुए अमेरिकी हवाई हमले की याद में इसे बनाया गया था और गद्दाफ़ी अपने लोगों को अक्सर यहीं से संदेश दिया करते थे.

विद्रोहियों ने पहले यह घोषणा की कि मुअम्मर गद्दाफ़ी के दोनों बेटों को पकड़ लिया गया है और कर्नल का कोई पता अभी तक नहीं लगा है, लेकिन दो दिनों बाद ही अल अरबिया टेलीविजन पर कर्नल गद्दाफ़ी के बेटे सैफ अल-इस्लाम को दिखाया गया, जब वह त्रिपोली पर सरकारी बलों के नियंत्रण की बात पत्रकारों से कह रहा था. इस तरह विद्रोहियों के दावे खोखले साबित हुए. इस बात पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता कि गद्दाफ़ी देश छोड़कर भाग गए हैं. अमेरिका, ब्रिटेन एवं जर्मनी सहित कई देशों के प्रमुखों ने गद्दाफ़ी को आत्म समर्पण करने को कहा है, ताकि और अधिक ख़ूनख़राबे से बचा जा सके, लेकिन गद्दाफ़ी मानने को तैयार नहीं हैं. उन्हें अभी भी अपनी जीत की उम्मीद है अथवा वह समर्पण का दंश झेलने के बजाय शहीद होना पसंद कर रहे हैं. गद्दाफ़ी ने कहा कि उन्हें और उनके लड़ाकों को नाटो के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में या तो जीत मिलेगी या शहादत. उन्होंने रेडियो पर भाषण देते हुए कहा कि हालांकि वह गद्दाफ़ी परिसर स्थित अपने ठिकाने से निकल गए हैं, लेकिन यह उनकी रणनीति है, हार नहीं. माना जा रहा है कि गद्दाफ़ी त्रिपोली छोड़कर अपने पैतृक शहर सिर्ते चले गए हैं. गद्दाफ़ी चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन उनका पतन लगभग तय है. राजधानी का 80 फ़ीसदी हिस्सा विद्रोहियों के क़ब्ज़े में है और ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के भीतर अन्य क्षेत्रों पर भी उनका क़ब्ज़ा हो जाएगा. दिसंबर 2010 में जब ट्यूनीशिया में बदलाव के लिए विद्रोह की शुरुआत हुई तो उस समय जिन देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए विद्रोह होने की प्रबल उम्मीद बन रही थी, उनमें लीबिया का नाम नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि कर्नल गद्दाफ़ी पश्चिमी देशों के पिट्ठू नहीं थे, जो कि मध्य पूर्व राष्ट्रों की जनता की नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण माना जाता था. कर्नल गद्दाफ़ी ने भी उस समय कहा था कि वह लोगों के साथ हैं और उनके पास किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं है, यहां तो लोकतंत्र है, लेकिन विश्लेषकों का अनुमान ग़लत निकला और ट्यूनीशिया एवं मिस्र के साथ लीबिया में भी सत्ता के ख़िलाफ़ संघर्ष शुरू हो गया. फरवरी के मध्य में एक महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता की गिरफ़्तारी ने ही गद्दाफ़ी सरकार के विरुद्ध हुए इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की. इस कार्रवाई के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसे सरकार ने दबाना शुरू कर दिया. सबसे ज़्यादा विरोध बेनगाजी शहर में हुआ और बाद में यही शहर सरकार के ख़िलाफ़ हुए हिंसक विद्रोह का केंद्र भी बना. विद्रोहियों ने पश्चिमी शहर अजदाबिया और तोबरुक पर भी हमले किए. सरकारी फौज ने भी जवाबी हवाई हमले किए.

सरकार को शुरू में सफलता मिली और विद्रोहियों को बिन जावेद, रास लनूफ और ब्रेगा जैसे शहरों से तटीय इलाक़ों में खदेड़ दिया गया. सेना के हवाई हमलों से आम नागरिक भी प्रभावित हुए, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप भी होने लगा. संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के तहत लीबिया पर हमले की योजना भी बनाई गई, लेकिन गद्दाफ़ी सरकार ने घबरा कर युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा का पालन करने के बजाय सरकार ने हमले जारी रखे, जिससे नाराज़ अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने लीबिया पर हवाई हमले शुरू कर दिए. सबसे पहला हमला फ्रांस की तरफ़ से किया गया. इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन भी हवाई हमलों में शामिल हो गए, नतीजतन लीबियाई सेना की हवाई क्षमता लगभग नष्ट हो गई, लेकिन कर्नल गद्दाफ़ी ने एक लंबी लड़ाई की घोषणा कर दी. उधर नाटो की सहायता मिलने से विद्रोहियों की ताक़त बढ़ती गई और वे विजय के काफी क़रीब दिखने लगे. उन्होंने अपने आंदोलन के लिए न केवल सामरिक तैयारी की, बल्कि प्रशासनिक तैयारी भी की. फरवरी में आंदोलन शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद पूर्वी लीबिया के शहरों के निवासियों ने एक अंतरिम प्रशासन का गठन किया, जिसे नेशनल ट्रांजिशन काउंसिल (एनटीसी) नाम दिया गया. इस संस्था का उद्देश्य लीबिया को राजनीतिक और सामरिक नेतृत्व प्रदान करना, लोगों को आवश्यक सेवाएं मुहैया कराना और विदेश में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करना है. संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समेत विभिन्न विभागों की देखरेख और विभिन्न क्षेत्रों एवं शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 33 सदस्य हैं. एनटीसी की एक कार्यकारिणी भी है, जो कैबिनेट की तरह कार्य करती है. इसने 14 पृष्ठों का एक संवैधानिक मसौदा भी तैयार किया है, जो देश में विद्रोह की सफलता के पश्चात सरकार के गठन तक काम आएगा. मुस्तफा मोहम्मद अब्दुल जलील को संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है. गद्दाफ़ी सरकार में न्याय मंत्री रहे अब्दुल जलील ने निहत्थे विद्रोहियों के ख़िलाफ़ हथियार के इस्तेमाल के विरोध में अपना इस्तीफ़ा दे दिया था.अब्दुल हफीज घोगा को उपाध्यक्ष बनाया गया है. वह मानवाधिकार मामलों के वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उमर अल हरीरी को सैन्य, अली इसावी एवं महमूद जिब्रील को विदेशी मामलों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. अहमद अल जुबैर अहमद अल सनुसी, फाति मोहम्मद बजा, फातिही तिरबिल सरवा और सलवा अल दिघाली को भी एनटीसी में शामिल किया गया है. कुछ लोगों के नाम सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखे गए हैं. एनटीसी ने एक तरह से विद्रोह की सफलता के बाद सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है. उसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन भी हासिल है. गद्दाफ़ी सरकार के विरुद्ध 52 देशों ने एनटीसी को मान्यता देना स्वीकार कर लिया. सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गद्दाफ़ी शासन की समाप्ति के बाद क्या लीबिया में शांति बहाली हो जाएगी? कर्नल मुअम्मर गद्दाफ़ी ने भी सैनिक विद्रोह के माध्यम से सत्ता पर अधिकार किया था. अपने 42 सालों के शासन में उन्होंने लीबिया को संपन्न और शक्तिशाली बनाया, साथ ही अपने निजी खजाने में भी अपार धन जमा किया. इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों की फौज भी खड़ा कर ली. वह जिस कबीले के हैं, उस कबीले के लोग गद्दाफ़ी का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सेना यदि विद्रोहियों का मुक़ाबला नहीं पाएगी तो वे हथियार उठा लेंगे. इससे तो लगता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी लीबिया में शांति बहाली में समय लगेगा. हो सकता है, गद्दाफ़ी के लीबिया छोड़ने के बाद वहां वही स्थिति हो जाए, जैसी सद्दाम हुसैन की पराजय के पश्चात इराक और तालिबान शासन की समाप्ति के बाद अफ़ग़ानिस्तान में हुई. विद्रोह के सूत्रधारों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, वरना लीबिया में शासन चलाना काफी मुश्किल होगा. एनटीसी के अंदर भी आपसी मतभेद हैं. उसकी पहली बैठक ही खासी अव्यवस्थित रही. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मध्य पूर्व राजनीति के प्रोफेसर फवाज गेरजेस का मानना है कि विद्रोहियों ने अपना घर दुरुस्त नहीं किया है. वे अभी तक अपने वैचारिक, राजनीतिक एवं कबायली मतभेदों को ख़त्म नहीं कर पाए हैं. एनटीसी को लीबिया के सभी क्षेत्रों का समर्थन हासिल नहीं है. मिरासता लीबिया का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन वह यह नहीं मानता कि एनटीसी ही लीबिया का अकेला प्रतिनिधि है. एनटीसी के अंदर के मतभेद अगर गद्दाफ़ी के शासन की समाप्ति के पहले ख़त्म नहीं हुए तो इसके परिणाम अच्छा नहीं होंगे. अभी तो उनके पास एक सामान्य उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार गद्दाफ़ी को सत्ता से हटाया जाए, लेकिन गद्दाफ़ी के बाद सत्ता की जंग शुरू होगी, जिसके लिए एनटीसी के सदस्यों के बीच मौजूद वैचारिक मतभेदों का दूर होना ज़रूरी है. इसके अलावा विद्रोह की सफलता के बाद इसमें शामिल लोगों का क्या होगा, यह भी एक गंभीर प्रश्न है. यह कोई अहिंसात्मक आंदोलन तो है नहीं, जिसमें शामिल लोग सफलता के बाद अपने-अपने घर लौट जाएंगे. विद्रोहियों ने हथियार थामे हैं और वे पिछले सात महीनों से युद्ध कर रहे हैं. नई सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है. इस बात की भी आशंका है कि संघर्ष में तकलीफ उठा चुके विद्रोही गद्दाफ़ी समर्थकों को परेशान करें और अगर ऐसा हुआ तो फिर लीबिया में छद्म युद्ध प्रारंभ हो जाएगा. नई सरकार को इस विषय पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, ताकि लीबिया को बचाया जा सके. विद्रोह की सफलता के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आम लोगों को प्रभावित करने वाली है, वह है पश्चिमी राष्ट्रों का लीबिया पर प्रभाव. चूंकि विद्रोहियों को उनका साथ मिला है तो सामान्य बात है कि विद्रोह की सफलता के बाद बनी सरकार में शामिल लोगों पर उनका खासा प्रभाव होगा और वे अपने हितों के लिए इस सरकार का उपयोग करना चाहेंगे. लीबिया में तेल का भंडार है, वहां जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा इसी व्यवसाय से प्राप्त होता है. अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन आदि देशों ने जिस तरह विद्रोहियों का साथ दिया है, उससे उनकी नीयत पर संदेह होना लाज़िमी है. ध्यान रहे कि कर्नल गद्दाफ़ी पर उनका प्रभाव नहीं था. अमेरिका ने तो गद्दाफ़ी पर हवाई हमला भी किया था. अगर गद्दाफ़ी का पतन होता है, जो लगभग तय माना जा रहा है तो अमेरिका जैसे देश वहां की नई सरकार पर अपनी नीति थोपने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र वहां के तेल और गैस के भंडारों पर है. नई सरकार अगर इस जाल में फंसती है तो फिर से लीबिया में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मध्य पूर्व के देशों की जनता में पश्चिमी राष्ट्रों के गद्दाफ़ी काफी आक्रोश है. इसलिए कर्नल गद्दाफ़ी की पराजय लीबिया में शांति बहाली की गारंटी नही है. नई सरकार को एक साथ कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसकी कोई भी भूल लीबिया को एक लंबे गृह युद्ध की ओर ले जा सकती है. एनटीसी की वास्तविक परीक्षा तो अभी बाक़ी है, जिसकी शुरुआत गद्दाफ़ी शासन के अंत के बाद होगी.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उन्होंने कहा, मैंने अनेक साधु-संतों के दर्शन किए हैं.

आस्था है तो सब कुछ है

वह स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबई से शिरडी आए. उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडिल पहन रखे थे. उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडिल इस कार्य में बाधक बन गए. उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए? तब उन्होंने अपने सैंडिल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए.

काका साहेब दीक्षित के भ्राताश्री भाई जी नागपुर में रहते थे. जब वह 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया. दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए. पांच वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर आए और भाई जी के यहां ठहरे. वहां श्री साई बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उनके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई. मनमाड और कोपरगांव निकल जाने पर वह एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े. शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर दो ध्वज लहराते देखे. सामान्यत: देखने में आता है कि भिन्न-भिन्न संतों का बर्ताव, रहन-सहन और बाह्य सामग्रियों में प्राय: भिन्नता पाई

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार बार नमस्कार.

जाती है, परंतु केवल इन वस्तुओं से ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है. सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे. उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वह सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं, क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है. अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूं. तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने उदिग्न हो उठे हो तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे, तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उन्होंने कहा, मैंने अनेक साधु-संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई बिरला ही है, जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है. ऐसे साधु का दर्शन न करना ही उत्तम है, ऐसा कहकर वह वापस लौटने लगे.

तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो. मस्जिद में जो साधु है, वह इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच-विचार नहीं करते. यह सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उन्हें भेंट करते हैं. अंत में वह शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए. मस्जिद के मंडप में पहुंच कर तो वह द्रवित हो गए. उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रुंध गया. उनके सारे दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहां अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए, उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना. वह बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु वह उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर-जोर से चिल्ला कर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ. ख़बरदार, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो! ऐसे संत का दर्शन क्यों करना चाहि, जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाकर रखे, क्या यह संतपन के लक्षण हैं? एक क्षण भी यहां न रुको. अब उन्हें अनुभव हो गया कि बाबा ने उसके हृदय की बात जान ली और वह कितने सर्वज्ञ हैं. उन्हें अपनी योग्यता पर हंसी आने लगी और यह भी पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं. उन्होंने देखा कि वह किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेमदृष्टि से निहारते हैं. किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण उनके आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर उन्हें अपना आचरण सुधारना चाहिए. बाबा का क्रोध तो उनके लिए वरदान स्वरूप है. अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वह बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए.

इसी तरह बंबई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साई बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थीं, परंतु उन्हें विश्वास ही नहीं होता था, क्योंकि वह संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे. अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था. वह स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबई से शिरडी आए. उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडिल पहन रखे थे. उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडिल इस कार्य में बाधक बन गए. उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए? तब उन्होंने अपने सैंडिल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए. उनका ध्यान सैंडिलों पर ही लगा रहा. उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद एवं उदी प्राप्त कर लौट आए. पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडिल तो ग़ायब हो चुके हैं. पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ गई और अंत में निराश होकर वह अपने स्थान पर वापस आ गए. स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वह भोजन करने को बैठे, परंतु वह पूरे समय तक उन सैंडिलों के चिंतन में ही मग्न रहे. भोजन के बाद मुंह-हाथ धोकर जब वह बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर नए सैंडिलों का एक जोड़ा लटका हुआ था. उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा, बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम-घूमकर हरि का बेटा, जरी का फेंटा की पुकार लगाने को कहा है और जो कोई कहे कि सैंडिल हमारे हैं, उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का नाम क (अर्थात कानोबा) है. साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना. बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद एवं आश्चर्य हुआ. उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडिल हैं, मेरा ही नाम हरि और मैं ही कानोबा का पुत्र हूं. यह मेरा जरी का साफा देखो. बालक संतुष्ट हो गया और सैंडिल उन्हें दे दिए. उन्होंने भी सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी. हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु शिरडी यात्रा का यह मेरा प्रथम अवसर है, फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोबा. वह तो केवल बाबा के परीक्षार्थ वहां आए थे. उन्हें इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई. उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं.

स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

पूजा के हर रंग, काशी विश्वनाथ के संग आलेख में तीन लोक से न्यारी काशी (बनारस) के अनोखे पूजा विधान की चर्चा के साथ-साथ भगवान विश्वनाथ के स्नान, शृंगार, पूजन, आरती, भोग और दर्शन की क्रमवार प्रक्रिया का लेखक ने सजीव वर्णन किया है.

अनंत विजय

सपाट बयानी का संग्रह

बहुत ही दिलचस्प वाकया है. राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तकों की सूची उसकी वेबसाइट पर जाकर देख रहा था. कई किताबें पसंद आईं. यह सोचकर नाम लिखता गया कि उन पुस्तकों को मंगवा कर पढ़ूंगा और अगर मन बना तो उन पर अपने स्तंभ में या अन्यत्र कुछ लिखूंगा भी. सूची बनाते-बनाते एक किताब दिखाई दी-मरजानी, लेखिका वर्तिका नंदा. मैंने अशोक माहेश्वरी जी को किताबों की जो सूची भेजी, उसमें मरजानी का नाम भी भेज दिया. मेरे पत्र के कुछ दिनों बाद ही झा जी घर पर आकर किताबें दे गए. मैंने किताबें देखनी शुरू की. पलटते-पलटते मरजानी की बारी आई. जैसे ही मैंने किताब खोली तो हैरान रह गया. मरजानी वर्तिका नंदा का नया कविता संग्रह निकला. अपनी अज्ञानता में मैंने उसे उपन्यास समझ कर मंगवा लिया था. मेरी ज़्यादातर रुचि उपन्यास या फिर कहानी संग्रह में ही रहती है. ख़ैर हाल के दिनों में जिस तरह से वर्तिका नंदा ने अपने ताबड़तोड़ लेखन से हिंदी में सारा आकाश छेकने की कोशिश की है, उसके बाद से ही उनके लेखन को लेकर पाठकों के मन में दिलचस्पी बढ़ी है. मेरे मन में भी. अख़बारों में लगातार लेखन करके भी वर्तिका ने पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. दो हज़ार दस में राजकमल प्रकाशन से ही नंदा की किताब टेलीविज़न और क्राइम रिपोर्टिंग को मैं उलट-पुलट कर देख चुका था, लिखना चाह रहा था, लेकिन काहिली की वजह से लिख नहीं पाया. गद्य में मेरी रुचि है, लेकिन पद्य में मेरी रुचि जरा कम या यूं कहें कि बेहद कम है. मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे पुराने कवियों जैसे दिनकर, अज्ञेय, निराला एवं नागार्जुन आदि को पढ़ने में आनंद आता है. आनंद इस वजह से आता है कि वे कविताएं मेरी समझ में आती हैं. मुक्तिबोध को कोर्स में होने की वजह से पढ़ा. पहले अंधेरे में बहुत ही दुरुह कविता लगी थी, लेकिन बाद में जब उस कविता पर कई आलोचकों की राय पढ़ी तो बात समझ में आई. लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, उन्हें मेरी अल्पबुद्धि जरा कम ही समझ पाती है. समझने की बहुत कोशिश की, कई कवियों की कविताओं को पढ़ा भी, लेकिन समझ न पाने की वजह से उन पर लिख नहीं पाया.

वर्तिका की इस किताब को पलटते हुए मैंने सोचा कि एक पत्रकार और अब पत्रकारिता के शिक्षक की कविताएं पढ़ लेनी चाहिए. संग्रह को दो बार पढ़ा. कवयित्री ने अपने भूमिकानुमा लेख-कविता से पहले लिखा है. वैसे कविताएं निजी दस्तावेज़ की तरह होती हैं. आम तौर पर वे तकिए के नीचे छिपी रहती हैं या अकेलेपन की साथी बनती हैं और जब हवाओं का रुख़ आसमान की तरफ़ ले जा रहा होता है, तब भी ये घास की तरह ज़मीन पर रहकर मज़बूत बनी रहती हैं. कवयित्री ने कविता को भावुकता की ज़मीन दे दी है, मन के क़रीब रहने वाली, साथ-साथ चलने वाली, ओढ़नी बनी और तकिया भी. कविता को ओढ़नी बताने का उनका निहितार्थ क्या है, इसके साफ संकेत कहीं नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन प्रचलित अर्थ में ओढ़नी लड़कियां

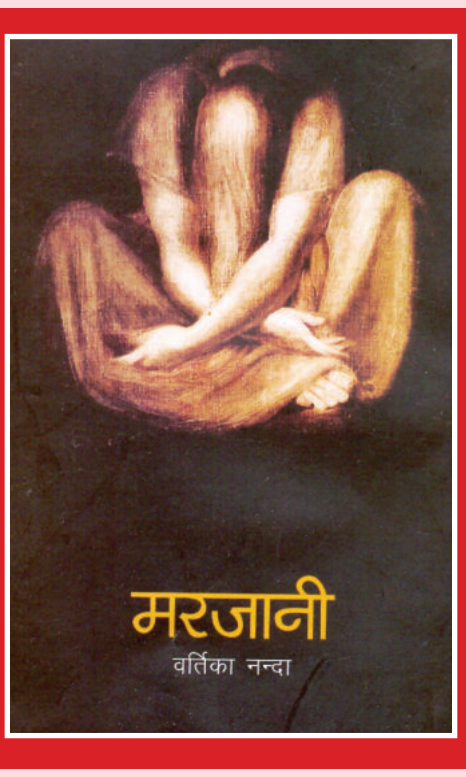

समीक्ष्य संग्रह-मरजानी
लेखिका-वर्तिका नंदा
प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य-200 रुपये

और औरतें अपने को ढकने के लिए इस्तेमाल करती हैं. मुझे यह समझ नहीं आया कि कविता ओढ़नी कैसे बन सकती है और किस लाज को ढकने के काम आ सकती है. कविता में शब्दों का चयन उसे चमका देता है, लेकिन अगर वही शब्द अगर ज़बरदस्ती ठूंसे जाते हैं तो स्पीड ब्रेकर की तरह झटके भी देते हैं. अपनी कविता को लेकर इमोशनल कवयित्री इतने पर ही नहीं रुकती हैं, पाठकों से भी आग्रह करती हैं कि इन्हें मैंने नज़ाकत से रखा था, आप भी इन्हें नज़ाकत से ही पढ़िएगा.

कवयित्री का यह आग्रह उनकी कविताओं में एक ज़बरदस्त मोह के रूप में सामने आता है. ख्याल ही तो है, में वह कहती हैं, क्या वो कविता ही थी/जो उस दिन कपड़े धोते-धोते/साबुन के साथ घुलकर बह निकली थी/एक ख्याल की तरह आई/ख्याल की ही तरह/धूप की आंच के सामने बिछ गई/पर बनी रही नर्म ही. यहां भी वर्तिका के लिए कविता नर्म और नाज़ुक है. एक कवयित्री का अपनी कविताओं को लेकर मोह तो जायज़ है, लेकिन पाठक तो कविता को कविता की कसौटी पर कसेंगे ही. वर्तिका नंदा की कविताओं को पढ़ते हुए एक बार फिर से मेरे मन में पुराना सवाल कौंधा, कविता क्या है? जवाब में फिर से कविता के नए प्रतिमान में नामवर सिंह का लिखा याद आया, किसी काव्य कृति का कविता होने के साथ ही नया होना अभीष्ट है. वह नई हो और कविता न हो, यह स्थिति साहित्य में कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती. वर्तिका की कविताएं पढ़ते हुए मुझे कुछ भी नया नहीं लगा, न तो कविता की भाव भूमि और न कथन और न बिंब. उनकी कविताओं में अक्सर घूम-फिर कर घर, परिवार और उनका पेशा और परिवेश आता रहता है और कवयित्री, लगता है, उसके ही चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं. वर्तिका की कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लगा कि अपनी कविताओं में वह कई बार बेहद सपाट हो जाती हैं और कविता और नारों के बीच का फ़र्क़ भी भूल जाती हैं. उदाहरण के तौर पर अगर हम उनकी कविता क्यों भेजूं स्कूल को देखें-नहीं भेजनी अपनी बेटी मुझे स्कूल/नहीं बनाना उसे पत्रकार/क्या करेगी वह पत्रकार बनकर/अगर नाम कमा लेगी तो नहीं बन पाएगी पूरी औरत.

यह एक कवि का अपने पेशे से मोहभंग की अभिव्यक्ति है, जो उसकी कविताओं में नारे की शक्ल में उपस्थित होती है. नारे भीड़ में जोश तो भर सकते हैं, लेकिन जब वे कविता की ज़मीन पर पहुंचते हैं तो औंधे मुंह गिर जाते हैं. समीक्ष्य संग्रह में यह कई बार घटता है. इसके अलावा मरजानी की अन्य कविताओं में भी जो बिंब उठाए गए हैं, वे भी पहली नज़र में वास्तविकता को मूर्त करते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर उन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो वास्तविकता का अनावश्यक भार उठाते हुए कविताएं हांफती नज़र आती हैं, चाहे वह टीवी एंकर और तुम हो या फिर कसाईगिरी. निष्कर्ष यह कि बिंब के बोझ तले कविता इतनी दब गई है कि वह उठ ही नहीं पाई. वर्तिका नंदा की छोटी-बड़ी कविताओं को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इन कविताओं में जो भावुकता है या जो वैयक्तिकता है, वह संरचना में शिथिलता और काव्यानुभूति की कमज़ोरी का परिणाम है. इस संग्रह में जिस तरह से तात्कालिक परिवेश की ज़मीन पर कवयित्री ने सपाट बयानी की है, उससे भी उनकी कविताओं की दुर्बलता सामने आती है. घटनाओं को यथार्थपरकता की चाशनी में डुबो कर कविता गढ़ने की जो एक प्रवृत्ति हाल के दिनों में सामने आई है, वर्तिका की कविताएं उसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं. वर्तिका नंदा का यह कविता संग्रह एक कमज़ोर और सपाट कविताओं का संग्रह है, जो हिंदी साहित्य जगत में अगर अननोटिस्ड रह जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा. अंत में एक और चौंकाने वाली बात, राजकमल प्रकाशन ने अब अपनी किताबों का मूल्य डॉलर में भी देना शुरू कर दिया है. इस संग्रह का दाम है आठ डॉलर.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

बनारस को जानिए-समझिए

आत्म प्रचार और विज्ञापन के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो किसी प्रतिदान की अपेक्षा के बग़ैर चुपचाप निष्ठापूर्वक अपना काम किए जा रहे हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं लेखक-पत्रकार कमल नयन. कमल जी के आलेख काफ़ी पहले साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग में प्रमुखता से प्रकाशित होते रहे. कमल नयन ने धर्मयुग के संपादक डॉ. धर्मवीर भारती के वैचारिक विमर्श के अनुसार अपनी अभिनव कृति बनारस तेरे रंग हज़ार शीर्षक से प्रस्तुत की है. आज हिंदी में लेखकों के जीवन और कृतित्व पर तो ढेर सारी पुस्तकें मिल जाती हैं, लेकिन संस्कृति और दिग्दर्शन कराने वाली पुस्तकें बाज़ार से नदारद हैं. यह पुस्तक कुछ हद तक इसकी रपाई कर सकती है. बनारस तेरे रंग हज़ार के आलेखों में बनारस और उससे जुड़े लोगों और बनारसी संस्कृति को सुदृढ़ करने में उनके योगदान को बख़ूबी उभारा गया है. भारतीय संस्कृति में बनारसीपन सदैव से ही चर्चा का विषय रहा है. पूजा के हर रंग, काशी विश्वनाथ के संग आलेख में तीन लोक से न्यारी काशी (बनारस) के अनोखे पूजा विधान की चर्चा के साथ-साथ भगवान विश्वनाथ के स्नान, शृंगार, पूजन, आरती, भोग और दर्शन की क्रमवार प्रक्रिया का लेखक ने सजीव वर्णन किया है. इसके साथ ही मंदिर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और प्रबंध व्यवस्था पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है. काशी (बनारस) की मूल आत्मा को जानने के लिए सावन के रंग में भंग की तरंग, ये राजसी रईस, बनारस की मिठाई संस्कृति-काशी

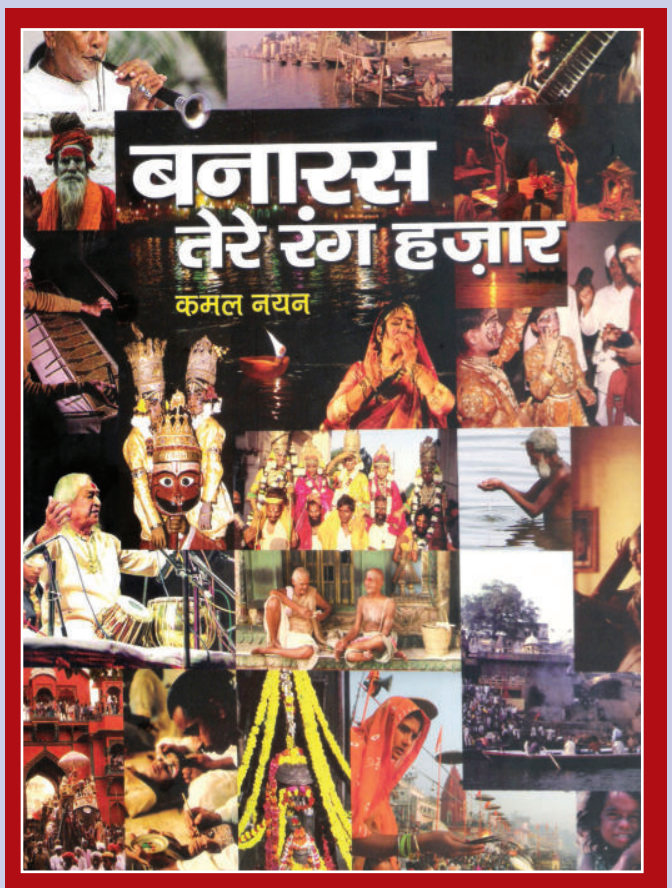

समीक्ष्य कृति-बनारस तेरे रंग हजार
लेखक-कमल नयन
प्रकाशक-भारत बुक सेंटर, लखनऊ
मूल्य-750 रुपये

की मिठाइयां राष्ट्रीयता पगी, किस्से शहर बनारस के, नाद ब्रह्म से साक्षात्कार आदि आलेख पर्याप्त हैं. बनारस तेरे रंग हज़ार संस्मरण, जीवनी, शोध, आलोचना, रेखाचित्र और काशी (बनारस) के सांस्कृतिक आख्यान का बेहतर परिपाक है. इस कृति का विमोचन सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. काशीनाथ सिंह ने किया. पराड़कर स्मृति भवन में बीते 15 अगस्त को आयोजित एक समारोह में इस पुस्तक का विमोचन करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि जो बनारस को नहीं जानता है और जानना चाहता है, उसके लिए बनारस के रंग हज़ार मील का पत्थर साबित हो सकती है. मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता संस्थान के संकायाध्यक्ष प्रो. राम मोहन पाठक ने कहा कि लेखन की सार्थकता पहचानना संपादक का ही काम होता है. तकनीक चाहे जितनी उन्नत हो जाए, संपादक का कोई विकल्प नहीं है. समारोह की अध्यक्षता प्रख्यात कार्टूनिस्ट जगत शर्मा ने की. स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कमल नयन समारोह में उपस्थित नहीं हो सके. उनका लिखित स्वागत भाषण उनके पुत्र प्रमोद कमल ने पढ़ा. संचालन धर्मशील चतुर्वेदी ने किया.

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
सुनो दीपशालिनी
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीत

अनुवाद
प्रयाग शुक्ल

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
150 रुपये

इस किताब में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बांग्ला से अनुवादित हिंदी कविताएं शामिल हैं.

सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

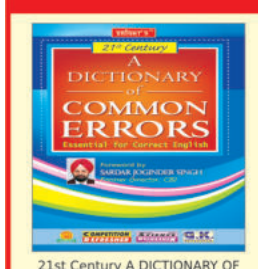

21st Century A DICTIONARY OF COMMON ERRORS
₹ 99

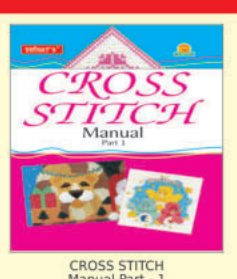

CROSS STITCH Manual Part - 1
₹ 60

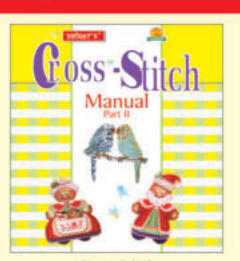

Cross-Stitch Manual Part - II
₹ 70

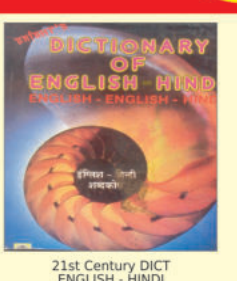

21st Century DICT ENGLISH - HINDI
₹ 75

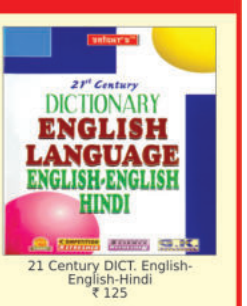

21 Century DICT. English-English-Hindi
₹ 125

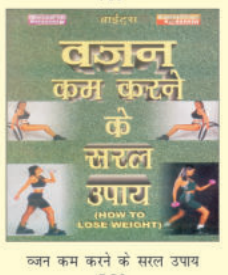

वजन कम करने के सरल उपाय
₹ 50

इंगलिश सीखिए और बोलिए
₹ 199

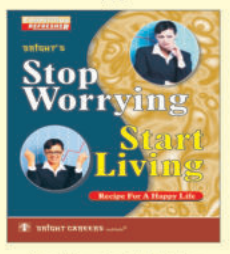

Stop Worrying Start Living
₹ 50

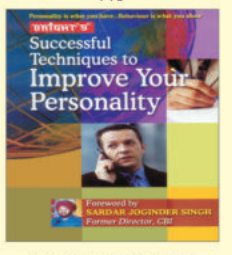

Successful Techniques to Improve Your Personality
₹ 99

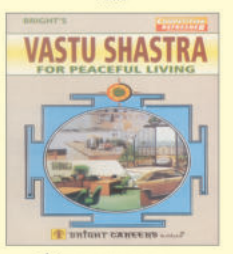

★ VASTU SHASTRA
₹ 70

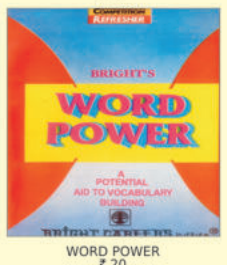

WORD POWER
₹ 20

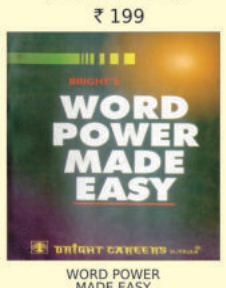

WORD POWER MADE EASY
₹ 80

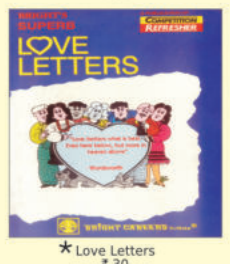

★ Love Letters
₹ 30

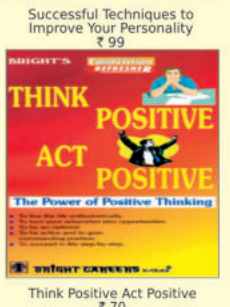

Think Positive Act Positive
₹ 70

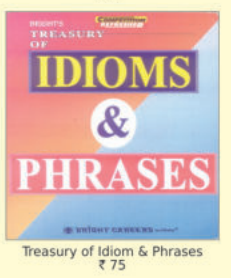

Treasury of Idiom & Phrases
₹ 75

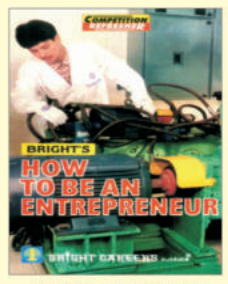

How to be an Entrepreneur
₹ 50

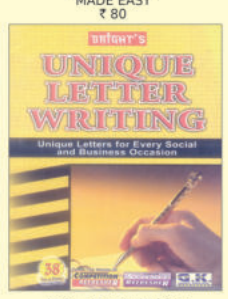

Unique Letter Writing
₹ 45

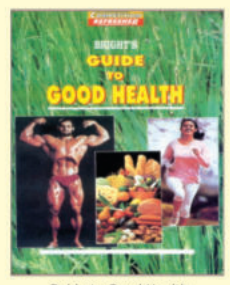

Guide to Good Health
₹ 40

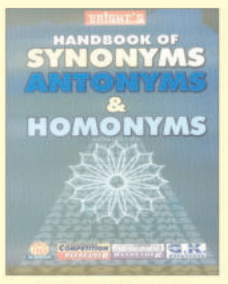

Handbook of Synonyms, Antonyms & Homonyms
₹ 75

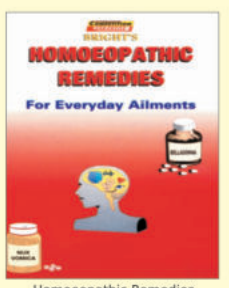

Homoeopathic Remedies
₹ 40

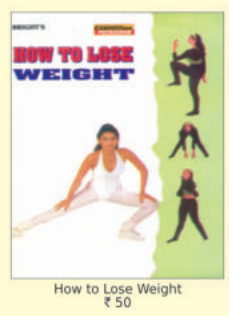

How to Lose Weight
₹ 50

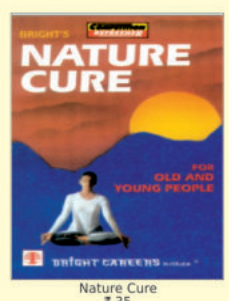

Nature Cure
₹ 35

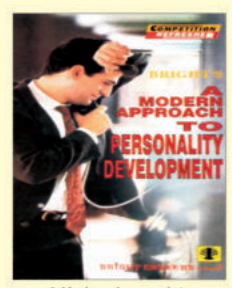

A Modern Approach to Personality Development
₹ 45

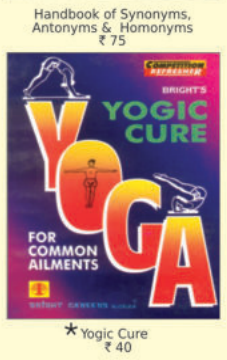

★ Yogic Cure
₹ 40

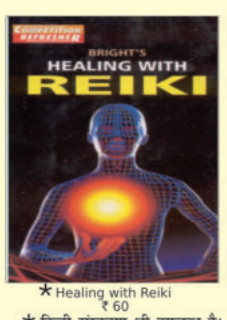

★ Healing with Reiki
₹ 60
★ हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है।

ब्राईट पब्लिकेशंस
भारत में सर्वाधिक बिकने वाली प्रतियोगिता पुस्तकों के प्रकाशक
2767, कूचा चैलान, दरियागंज, दिल्ली-110002 (भारत) (स्थापित : 1968)
फोन : 011-64632226, 23282226, 23283226 — फैक्स : 011-23269227
ई-मेल: sales@brightpublications.com | वैब साइट: http://www.brightpublications.com

विनकॉन टेलीकॉम के सह संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक अरविंद वोहरा ने कहा, आज निजी एवं पेशागत स्तर पर लोगों से जुड़े रहना युवाओं के लिए एक ज़रूरत बन गया है.

ड्यूल सिम वाला आई फोन

इसमें ब्लूटूथ, जीपीआरएस, जावा, वेप और गूगल मैप सपोर्ट सिस्टम है. साथ ही इसमें हाई रेज्यूलेशन ड्यूल कैमरा भी है, जो फ्लैश लाइट के साथ है. यह फोन एमपी-3, एमपी-4, एवीआई और थ्रीजीपी मल्टी मीडिया फीचर्स से लैस है.

मोबाइल फोन और स्मार्ट फोन के बाद लोगों के बीच आई फोन का क्रेज़ बढ़ गया है. महंगे आई फोन को देखकर बाजार में मौजूद दूसरी कंपनियां मोबाइल फोन का स्वरूप थोड़ा बदल कर आई फोन को आम लोगों की जेब तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. इसी क्रम में आईकॉन कंपनी ने अपना पहला क़दम उठाया है. अभी तक बाज़ार में केवल सिंगल सिम आई फोन था, जबकि उसकी तरह दिखने वाले और भी कई मोबाइल बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो काफी सस्ती क़ीमत पर उपलब्ध हैं. अब आईकॉन ने सिर्फ़ 6,490 रुपये की क़ीमत पर अपना मोबाइल बाज़ार में उतारा है, जो दिखने में बिल्कुल आई फोन जैसा है, लेकिन यह ड्यूल सिम वाला है.

दूसरे स्मार्ट फोन की तरह इसमें सभी सुविधाएं हैं. इसमें ब्लूटूथ, जीपीआरएस, जावा, वेप और गूगल मैप सपोर्ट सिस्टम है. साथ ही इसमें हाई रेज्यूलेशन ड्यूल कैमरा भी है, जो फ्लैश लाइट के साथ है. यह फोन एमपी-3, एमपी-4, एवीआई और थ्रीजीपी मल्टी मीडिया फीचर्स से लैस है. अगर आप इसमें टीवी देखना चाहते हैं तो यह सुविधा भी इस फोन में है, जिसके लिए इसमें अलग से एक एंटीना दिया गया है. इस फोन की इनबिल्ट मेमोरी 1 जीबी है, जिसे 8 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा इसमें मोबाइल ट्रेकर, ईमेल क्लाइंट, कॉल रिकॉर्डिंग, ग्रुप एसएमएस ऑप्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं.

एडवांस होम एप्लायंसेज

होम एप्लायंसेज कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपने प्रमुख उत्पादों को और मज़बूत बनाते हुए दुनिया के पहले चारकोल लाइटिंग हीटर माइक्रोवेव ओवन और 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव वॉशिंग मशीन की नई रेंज लांच की. इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव से जुड़ी नई 6 मोशन तकनीक एलजी की वॉशिंग मशीनों को 6 अलग-अलग वॉशिंग मोशन के साथ अपनी तकनीकी महारथ प्रदर्शित करने का मौक़ा देती है. फैब्रिक और गंदगी के हिसाब से कपड़े फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीनों में मानक टंबलिंग, रॉलिंग, फिल्ट्रेशन, स्क्रब, स्विंग और स्टेपिंग आदि 6 मोशन से गुजरते हैं और टॉप लोडर वॉशिंग मशीनों में वेव फोर्स, एजिटेशन, रोटेटिंग, रबिंग, कंप्रेशन और स्विंग से होकर गुजरते हैं. एलजी की भाप तकनीक (स्टीम टेक्नोलॉजी) एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों, धूल के कणों और डिटर्जेंट पाउडर के अवशेषों को हटाने में भी मदद करती है, जो श्वांस संबंधी बीमारियों की वजह बनते हैं. एलजी 16 किलोग्राम की क्षमता वाली वॉशिंग मशीन है और 30 फ़ीसदी तक बिजली की बचत करने में मदद करती है. पूरी तरह ऑटोमेटिक 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव वॉशिंग मशीनों की नई रेंज की क़ीमत 24,290 रुपये से लेकर 70,990 रुपये तक है. वाशिंग मशीन के अलावा चारकोल लाइटिंग हीटर माइक्रोवेव ओवन 32 लीटर की क्षमता में उपलब्ध है. इसकी क़ीमत 18,490 रुपये से लेकर 21,290 रुपये तक है. उन्नत टेक्नोलॉजी से सुसज्जित नए माइक्रोवेव ओवन में स्वादिष्ट खाना तैयार किया जा सकता है. चारकोल लाइटिंग हीटर इसकी ऊष्मा को बढ़ाता है. एलजी के इस नए माइक्रोवेव ओवन रेंज के साथ 201 ऑटो कुक मेन्यू भी आ रहा है, जो एक बटन के क्लिक मात्र पर उपलब्ध हो जाएगा. इसमें इंडियन ब्रेड बास्केट और हेल्दी फ्राई जैसे नए विकल्प शामिल हैं, जो परांठे, उपमा और नान जैसे विभिन्न भारतीय व्यंजन बनाना सिखाते हैं और स्वास्थ्य और कैलोरी के प्रति चिंतित रहने वाले लोगों के लिए कम तेल के साथ स्नैक्स बनाना भी. इसके टॉप दो मॉडलों में आकर्षक वीएफडी डिस्प्ले और स्टाइलिश डोर लगा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मोबाइल की दुनिया में नया धमाका

मोबाइल फोन की दुनिया में लगभग प्रतिदिन नए प्रयोग हो रहे हैं और नए-नए प्रकार के मोबाइल फोन बाज़ार में आ रहे हैं. ग्राहकों के दिलों पर राज करने के लिए एक और कंपनी विनकॉन ने मोबाइल फोन की नई रेंज लांच की है. ओ-77 कनेक्ट और ओ-78 टच अत्याधुनिक ड्यूल सिम फोन हैं, जो अग्रणी ऑपरेटर के अनूठे प्लान के साथ उपलब्ध हैं. प्लान के तहत कई सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं. मसलन, मुफ्त इंटरनेट डाउनलोड, मुफ्त पुश ईमेल और इंस्टैंट मैसेजिंग सर्विस, मुफ्त टॉक टाइम और एसएमएस आदि. उक्त नए विनकॉन ओगों फोन सिंक्रोनिका ब्रिटिश सम्मान प्राप्त मोबाइल मैसेजिंग सेवा से लैस हैं. ये हैंडसेट्स अनूठे एवं अत्याधुनिक फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग (फेसबुक, लिंक्ड इन, ट्विटर), ख़बरों, खेल और मनोरंजन से जुड़े हज़ारों भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय फीड्स. विनकॉन टेलीकॉम के सह संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक अरविंद वोहरा ने कहा, आज निजी एवं पेशागत स्तर पर लोगों से जुड़े रहना युवाओं के लिए एक ज़रूरत बन गया है. यह डिवाइस खास तौर पर इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. हर चीज पुश पर उपलब्ध हो, इस लिहाज से डिज़ाइन की गई है. इतना ही नहीं, हमने इस डिवाइस को किफायती भी बनाया है. न केवल ख़रीदने के लिहाज़ से, बल्कि एक साल तक इस्तेमाल के लिहाज़ से भी, क्योंकि इंटरनेट डाउनलोड, पुश मेल और इंस्टैंट मैसेजिंग वास्तव में मुफ्त हैं. ओ-77 और ओ-78 भारत भर में चुनिंदा स्टोर्स पर क्रमश: 4,499 और 4,999 रुपये में उपलब्ध हैं.

होंडा की नई कार जैज

जापानी कंपनी होंडा सीएल भारत में अपनी कारों को फिर से स्थापित करने में जुट गई है. कंपनी ने अपनी छोटी कार होंडा जैज फिर से लांच की है. जैज का नया संस्करण पेश किया गया है, जिसकी खासियत है उसकी क़ीमत और माइलेज. जैज एस की क़ीमत 5.50 लाख रुपये, जैज सेलेक्ट की क़ीमत 5.75 लाख रुपये और जैज एक्स की क़ीमत 6.06 लाख रुपये है. मालूम हो कि जैज 2009 में लांच की गई थी और उस वक़्त इसकी क़ीमत 7.12 लाख से 7.56 लाख रुपये के बीच थी. लांच किए जाने के समय जैज देश की सबसे महंगी हैचबैक थी और शायद इसी कारण यह लोकप्रिय नहीं हो पाई. कंपनी ने कार बाज़ार की स्पर्धा को देखते हुए जैज की क़ीमत 5.50 लाख रुपये से लेकर 6.06 लाख रुपये तक रखी है. इस क़ीमत में कंपनी इस सेगमेंट की कारों को ज़बरदस्त टक्कर देगी. जैज के 2009 वाले मॉडल की क़ीमत 7.12 लाख रुपये से शुरू होती थीं. होंडा सील कार इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर सेकी इनाबा ने कहा कि होंडा की नई जैज की आकर्षक क़ीमतों से ग्राहक ज़रूर इसकी ओर आकर्षित होंगे. उन्होंने कहा कि हमने आरएंडडी के काफी पार्ट्स देश में बनाने में सफलता हासिल कर ली है. इससे हमारी क़ीमतें घट गई हैं. जैज का यह नया मॉडल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है और एक लीटर में 16.7 किलोमीटर की दूरी तय करता है. इसके ग्रिल, फ्रंट बंपर और हेडलाइटें सभी नई हैं. इसके व्हील एलाय के हैं और पीछे का बंपर नए तरह का है. कंपनी के अनुसार, नई जैज पहले वाली कार से 1.6 लाख रुपये सस्ती है. कंपनी को उम्मीद है कि क़ीमत में भारी कटौती के बाद इसकी बिक्री में तेज़ी आएगी. जैज का नया वैरियंट पहले के मुक़ाबले अधिक आकर्षक और स्पोर्टी है. तकनीकी रूप से नई जैज में कुछ खास नया नहीं है. नई जैज को बाज़ार में पहले से मौजूद हुंडई की आई-10, मारुति की रिट्ज़ एवं नई स्विफ्ट, फोक्स वैगन की पोलो और स्कोडा की फाबिया जैसी कारों से कड़ा मुक़ाबला करना होगा.

कंपनी ने कार बाज़ार की स्पर्धा को देखते हुए जैज की क़ीमत 5.50 लाख रुपये से लेकर 6.06 लाख रुपये तक रखी है. इस क़ीमत में कंपनी इस सेगमेंट की कारों को ज़बरदस्त टक्कर देगी.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

अपने दावों को इंग्लैंड ने सही साबित किया और टीम इंडिया की आख़िरी हार एक पारी और आठ रनों से हुई. इसके साथ ही भारत इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज 0-4 से हार गया.

टीम इंडिया चारों खाने चित्त

अभी कुछ ही दिनों पहले भारत के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड की तरफ़ से दो ऐसे अप्रत्याशित वाकए सामने आए, जो भारतीय मीडिया और कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को नागवार गुजरे. पहली बार जब इंग्लैंड टीम ने एक प्रेस कांफ्रेंस में यह दावा किया था कि हम पूरी सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर देंगे. दूसरी घटना, जब लंदन के मीडिया ने भारतीय टीम पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि भारतीय टीम उस कुत्ते की तरह है, जिससे अगर डरा न जाए तो वह ख़ुद ही डर कर भाग जाता है. दोनों ही मामलों में भारत के पास जवाब देने के लिए दो टेस्ट बाक़ी थे. जैसा कि कहते हैं कि इस जेंटलमैन गेम में हर बात का मुंह तोड़ जवाब अपने प्रदर्शन से दिया जाता है, टीम इंडिया भी बचे हुए दोनों टेस्टों में इंग्लैंड को धूल चटाकर यह साबित कर सकती थी कि लंबे समय बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जीत के बाद वहां का मीडिया पगला और बौखला गया है और फिर इंग्लैंड की गीदड़ भभकी दुनिया के सामने जगज़ाहिर हो जाती.

लेकिन हुआ क्या? आख़िरकार वही, जिसके आसार बहुत पहले से दिख रहे थे. भारत पूरी सीरीज में हर क्षेत्र में चारों खाने चित्त दिखा. अपने दावों को इंग्लैंड ने सही साबित किया और टीम इंडिया की आख़िरी हार एक पारी और आठ रनों से हुई. इसके साथ ही भारत इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज 0-4 से हार गया. इस हार के बाद भारतीय टीम आईसीसी की टेस्ट टीमों के वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. नंबर वन पर इंग्लैंड और दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया है. कल तक टीम इंडिया के लिए मिस्टर लकी के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी का लक कब बैडलक में बदल गया, किसी को भी पता नहीं चला. अभी तक धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया हारी नहीं थी और अब हारी है तो ऐसी कि किसी को मुंह दिखाते नहीं बन रहा है. धोनी की कप्तानी में यह पहला मौक़ा है, जब भारत कोई टेस्ट सीरीज हारा है. आपको बता दें कि पिछले चालीस सालों में भारत की यह सबसे बड़ी और शर्मनाक हार है. धोनी कहते हैं कि इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे खिलाड़ी चोटिल रहे और हम अपनी क्षमता के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. धोनी ने इसके लिए अपर्याप्त अभ्यास को भी दोषी ठहराया. लेकिन जब टीम इंडिया जीत रही थी, तब धोनी ने यह मसला क्यों नहीं उठाया. इस हार के बाद टीम इंडिया की चारों ओर आलोचना हो रही है. मैच के पांचवें दिन फॉलोऑन खेलते हुए केवल वह 283 रन ही बना पाई. ग़ौरतलब है कि भारत ने पहली पारी में इंग्लैंड के छह विकेट पर 591 रनों के जवाब में 300 रन बनाए थे. हालांकि सचिन तेंदुलकर और अमित मिश्रा ने आख़िरी दिन कुछ अच्छा खेल दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारत के हाथ से सफलता बहुत दूर निकल चुकी थी. भारत इस सीरीज में एक ओर शर्मनाक तरीक़े से हारा ही, ऊपर से जिन लोगों ने ओवल में सचिन के शतक की आस लगा रखी थी, वे भी नर्वस नाइंटी के शिकार होकर लौट गए यानी हार तो हार भारत को सचिन का सौंवा शतक देखने का भी मौक़ा नहीं मिला. सचिन 91 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए. लॉर्ड्स में हुए पहले टेस्ट से लेकर ओवल में हुए आख़िरी टेस्ट तक भारत की कमान एक थके हुए खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के पास थी. उनके चयन पर भी अब सवाल उठाए जा सकते हैं. खिलाड़ियों के अलावा मैदान में फील्डिंग सजाने से लेकर सही समय पर सही गेंदबाज़ों को मोर्चे पर न लगाने में भी उनकी असफलता साफ दिखाई दी. धोनी को इन सब खामियों के जवाब खोजने होंगे, लेकिन भारतीय टीम का नुक़सान सिर्फ़ इस सीरीज तक सीमित नहीं है, टीम को इस सीरीज से ऐसे जख्म मिले हैं, जो उसे आने वाले महत्वपूर्ण मैचों में भी दिखाई देंगे. सीरीज में जहां भारत ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ा है, वहीं टीम के कई खिलाड़ियों की हड्डी भी टूटी है. जी हां, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. आधी टीम इंडिया चोटिल होकर बाहर बैठी है. चोटिल खिलाड़ियों की सूची में विस्फोटक सलामी बल्लेबाज़ वीरेंद्र सहवाग और तेज गेंदबाज़ ईशांत शर्मा का नाम जुड़ गया है. इसके अलावा इस सूची में ज़हीर ख़ान, युवराज सिंह एवं हरभजन सिंह पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके थे. टीम इंडिया इस दौरे पर चोटों से ही जूझती रही है. लॉर्ड्स के पहले टेस्ट मैच में ही ज़हीर ख़ान चोटिल होकर बाहर हो गए. उसी मैच में गौतम गंभीर भी चोटिल होकर बाहर हो गए. उनकी ग़ैर मौजूदगी में राहुल द्रविड़ को सलामी बल्लेबाज़ की भूमिका निभानी पड़ी.

इसके बाद भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों की चोटों का सिलसिला थमा नहीं. काफी लंबे समय बाद टीम में वापसी करने वाले युवराज सिंह और फिरकी गेंदबाज़ हरभजन सिंह भी इस मैच में चोटिल होकर बाहर हो गए. टीम इंडिया सीरीज में चोटों की वजह से 2-0 से पिछड़ गई थी. इसके बाद अपनी पुरानी चोट से उभरे वीरेंद्र सहवाग ने सीरीज में वापसी की. इसके अलावा गौतम गंभीर और ज़हीर ख़ान भी इस मैच में वापस आए. ज़हीर ख़ान मैच की पहली पारी के दौरान ही चोटिल होकर पूरी सीरीज से बाहर हो गए. इसके अलावा प्रवीण कुमार भी दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी के दौरान अपना अंगूठा चोटिल करा बैठे थे. गंभीर और सहवाग भी पूरी तरह से फिट नहीं थे. सहवाग इस वजह से दोनों पारियों में खाता तक नहीं खोल पाए. लिहाज़ा नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया यह मैच भी बुरी तरह चौथे दिन ही हार गई. चौथे टेस्ट तक आते-आते गौतम गंभीर और सहवाग दोनों चोटिल हो गए थे. गंभीर इस मैच में भी पारी की शुरुआत करने नहीं उतर पाए थे. सहवाग भी दूसरी पारी में चोटिल हो गए. इससे पहले ईशांत शर्मा भी गेंदबाज़ी के दौरान अपने बाएं हाथ की उंगली में चोट खा बैठे थे. सहवाग की जगह मुंबई के सलामी बल्लेबाज़ अजंकया रेहाणे और ईशांत की जगह तेज गेंदबाज़ वरुण अरोड़ा को मौक़ा दिया गया. लेकिन क्या ऐसा संभव है कि अचानक टीम के इतने सारे खिलाड़ी एक साथ चोटिल हो जाएं. असल में पिछले साल से लगातार मुनाफ़ा और क्रिकेट मैच में मिलने वाली कमाई के लोभ में फंसे खिलाड़ी अपनी चोटें छिपाते हैं. गौतम गंभीर का वाकया तो सबको याद होगा. इसके अलावा आईपीएल के दौरान ही सहवाग भी घायल हुए थे, लेकिन उस वक़्त शायद सहवाग ने अपना इलाज कराना ज़रूरी नहीं समझा और इसी का खामियाजा इंग्लैंड में मिली शर्मनाक हार के रूप में भुगतना पड़ा.

अब इस पर जल्दी विश्वास नहीं होता कि यह वही टीम इंडिया है, जिसने विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोका था, टी-20, आईपीएल और वर्ल्डकप की हैट्रिक लगाई थी. आम तौर पर ऐसा होता है कि जो टीम सिलसिलेवार जीतती जाती है, उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं. क्रिकेट प्रेमियों की हर अपेक्षा पर खरा उतरना आसान भी नहीं है, लेकिन जिस तरीक़े से इस सीरीज में टीम इंडिया चारों खाने चित्त रही, यह उम्मीद तो हम किसी नई नवेली टीम से ही कर सकते हैं. अब वक़्त है धोनी और उन सभी खिलाड़ियों के लिए कि वे इस हार पर गहन चिंतन-मनन ज़रूर करें.

राजेश एस. कुमार
rajeshy@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 05 सितंबर-11 सितंबर 2011

रेडी की सफलता में बड़ा योगदान सिंगल स्क्रीन का रहा. जहां इसे 100 प्रतिशत की ओपनिंग मिली. रेडी की कामयाबी ने साबित कर दिया कि सलमान ख़ान निर्विवाद रुप से सिंगल स्क्रीन केनंबर वन स्टार हैं.

हिंदी फिल्मोद्योग का मॉनसून

फिल्मों पर पैसों की झमाझम बरसात

सुषमा गुप्ता

देश में मॉनसून कुछ देरी से आया, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यह जून से ही आ गया. हिट का ऐसा शानदार मॉनसून हिंदी फिल्मोद्योग ने कई सालों से नहीं देखा था. हर हफ्ते एक हिट आ रही है और पैसों की झमाझम बारिश करा रही है. जून और जुलाई में कई हिट, तो कई सुपर हिट आ चुकी हैं. यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि कई बड़ी फिल्में इस साल रिलीज़ हो रही हैं. पिछले दो महीने में अमूमन हर हफ्ते एक हिट आ रही है. हिट का यह सिलसिला शुरू हुआ अनीज बज़्मी के निर्देशन में बनी सलमान ख़ान स्टारर फिल्म रेडी के साथ. फिल्म ने ज़बरदस्त ओपनिंग ली और कुछ ही दिनों में यह दर्शकों के दिलोदिमाग़ पर छा गई. यह फिल्म साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है और कमाई के मामले में इसने कई रिकार्ड तोड़ दिए. पहले ही हफ्ते में इसने 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली. अभी तक यह क़रीब 120 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसकी कुल कमाई पौने दो सौ करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी. रेडी की सफलता में काफी बड़ा योगदान सिंगल स्क्रीन का रहा, जहां इसे 100 प्रतिशत की ओपनिंग मिली. रेडी की कामयाबी ने साबित कर दिया कि सलमान ख़ान निर्विवाद रूप से सिंगल स्क्रीन के नंबर वन स्टार हैं. इसके बाद रिलीज़ हुई शैतान, भेजा फ्राई टू और भिंडी बाज़ार को भी दर्शकों की सराहना मिली. हालांकि इन फिल्मों को रेडी की कामयाबी का खामियाजा भी उठाना पड़ा और सराहना के बाद भी ये फिल्में बहुत अच्छा कारोबार नहीं कर सकीं. रेडी के बाद अगली हिट फिल्म बनी डबल धमाल. इंद्र कुमार की इस फिल्म ने अच्छी ओपनिंग और अच्छा बिजनेस किया. फिल्म हिट साबित हुई, लेकिन बॉलीवुड में कमाई की मूसलाधार बारिश आई जुलाई के साथ. पहले हफ्ते दो फिल्में आमने-सामने थीं. अमिताभ बच्चन की बुड्ढा होगा तेरा बाप और आमिर ख़ान प्रोडक्शन की डेली बेली. बुड्ढा होगा तेरा बाप ने रिलीज़ से पहले ही सेटेलाइट अधिकार बेचकर अपनी लागत वसूल ली, जबकि डेली बेली रिलीज़ से पहले अपने एडल्ट कटेंट के चलते सुर्ख़ियों में आ गई. फिल्म की वजह से आमिर की जमकर फ़ज़ीहत हुई, लेकिन आमिर इस बात से ख़ुश हैं कि गालियों और फ़ज़ीहत के बाद भी फिल्म ने पचास करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली. बुड्ढा होगा तेरा बाप में बूढ़े अमिताभ को एक्शन करता देख दर्शकों को अच्छा लगा. यह फिल्म भी हिट साबित हुई. बुड्ढा होगा तेरा बाप ने 21 करोड़ रुपये का मोटा मुनाफ़ा कमाया.

इसके बाद 8 जुलाई को भट्ट कैंप की मर्डर-2 रिलीज़ हुई. इस फिल्म ने भी ख़ूब कमाई की. इसकी लागत और कमाई का अनुपात इस साल सबसे बेहतर साबित हुआ है. इस मामले में यह फिल्म ब्लॉक बस्टर साबित हुई है. हालांकि फिल्म की कहानी में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन शानदार संगीत, सेक्स और कम बजट ने फिल्म को सुपर हिट करा दिया. इसी दिन रिलीज हुई फिल्म चिल्लर पार्टी ने भी हिट का तमगा हासिल कर लिया. इसके अगले दो हफ्ते दो बड़ी हिट हिंदी फिल्मोद्योग का इंतज़ार कर रही थीं और फिर आई जोया अख्तर के निर्देशन में बनी ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा. फिल्म ने ज़बरदस्त सराहना और कामयाबी हासिल की. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भी फिल्म ने ख़ूब कमाई की. फिल्म ने यूके टॉप टेन और यूएसए टॉप ट्वेंटी में जगह बनाई. कमाई के मामले में फिल्म 85 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है और कुछ दिनों में यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा. यह साल की सबसे बड़ी ओवरसीज़ हिट साबित हो रही है. सिंघम के ज़रिए हिंदी सिनेमा ने सुपर हिट की हैट्रिक पूरी की. फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ रुपये पार कर चुका है और यह साल की दूसरी सबसे हिट साबित हो रही है. सिंघम ने यह कामयाबी अपने शानदार एक्शन दृश्यों और अजय-रोहित शेट्टी की सुपर हिट जोड़ी के चलते हासिल की. इस हिट के बाद दोनों की जोड़ी हिंदी फिल्मोद्योग में नंबर एक जोड़ी बन चुकी है. इससे पहले दोनों ने लगातार हिट फिल्में दी हैं. इसी साल दोनों की गोलमाल-3 आई थी और उसने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कारोबार किया. एक साल में दो फिल्मों के 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बिजनेस हासिल करने का खिताब अब तक किसी और को नहीं मिला था. इस लिहाज़ से अजय देवगन और रोहित शेट्टी दोनों के करियर के लिए यह साल बेहद अहम और शानदार साबित हुआ है. अब रोहित शेट्टी को नंबर वन डायरेक्टर के खिताब से नवाज़ा जा रहा है. हालांकि वह इस बात से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते और उनकी नज़र में राजू हिरानी ही नंबर वन डायरेक्टर हैं. बहरहाल, जुलाई के रूप में ऐसा शानदार महीना बॉलीवुड में काफी समय बाद आया. इस महीने आठ फिल्में आईं और उनमें से चार को सुपर हिट का खिताब मिल चुका है. बीते तीन सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब अलग-अलग टेस्ट की फिल्में आईं और सभी हिट हुई हों.

शानदार जुलाई के बाद अगस्त की शुरुआत भी धमाकेदार होने की उम्मीद थी. आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हुआ और इसने जितनी सुर्ख़ियां बटोरीं, उससे लगा कि फिल्म सुपर हिट होगी, हालांकि ऐसा हो नहीं सका. आरक्षण को लेकर विवाद पैदा हुआ तो लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर बढ़ी कि आख़िर आरक्षण को लेकर प्रकाश झा ने क्या दिखाया है. आरक्षण मसले को उठाने और उसे बीच में यूं ही छोड़कर दूसरे ट्रैक पर स्टोरी बढ़ाने की वजह से रिलीज़ के बाद यह फिल्म समीक्षकों के निशाने पर आ गई और फिल्म को कम रेटिंग मिली. कम रेटिंग और तीन राज्यों में प्रतिबंध के साथ रिलीज़ का असर ओपनिंग पर पड़ा और फिल्म को उम्मीद के मुताबिक़ ओपनिंग नहीं मिली. बाद में उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाक़ी राज्यों में फिल्म रिलीज़ कर दी गई और वीकेंड पर बढ़े कलेक्शन की वजह से पहले हफ्ते में इसने 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कारोबार कर लिया. दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन अच्छा रहा और 42 करोड़ रुपये की फिल्म ने अपनी लागत वसूल ली. यह फिल्म अब तक क़रीब 58.5 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है. हालांकि इसके बाद कोई हिट नहीं आई. नॉट ए लव स्टोरी कम बजट की वजह से फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दर्शकों की दिलचस्पी आरक्षण के बाद रिलीज़ फिल्मों में कम ही दिखी. इसकी एक वजह अन्ना हजारे का आंदोलन भी रहा. आंदोलन की वजह से न तो मीडिया में ये फिल्में सुर्ख़ियां बटोर सकीं, न ही दर्शकों का ख़ास रुझान दिखा. मानसून में पैसों की बरसात सिर्फ़ हिंदी फिल्मों पर नहीं हुई, बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों ने भी ख़ूब कमाई की. मसलन हैरी पॉटर, डेथली हैलोज पार्ट-2, ट्रांसफॉर्मर-3 और डार्क ऑफ दी मून आदि ने भी टिकट खिड़की पर अच्छा कारोबार किया. हैरी पॉटर और ट्रांसफॉर्मर-3 ने अब तक क्रमशः अपनी झोली में 15 करोड़ और 19 करोड़ रुपये हासिल किए. इन दोनों फिल्मों के 600 प्रिंट 2-डी और 3-डी फॉर्मेट में रिलीज किए गए थे. साथ ही ये फिल्में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज की गई थीं. आख़िर बॉलीवुड में हिट और पैसों की बरसात कैसे हुई, क्या यह इत्तेफ़ाक़ था या फिर कोई और वजह? इसकी कई वजहें थीं. बड़ा कारण अच्छी फिल्मों का होना था. पिछले दो महीनों में जो भी फिल्म हिट हुई, उसकी कहानी नई थी. निर्देशन भी काफी अच्छा था. इसके अलावा मार्केटिंग के नए तरीक़ों के इस्तेमाल ने भी फिल्मों को हिट कराने में अपना योगदान दिया. इनका प्रोमो, आउटडोर विज्ञापन और गाने यानी सभी कुछ दर्शकों को लुभाने वाला था. दिल्ली बेली को निगेटिव पब्लिसिटी का फ़ायदा मिला तो बुड्ढा होगा तेरा बाप के लिए अमिताभ बच्चन ने 5 भाषाओं में प्रोमो रिकॉर्ड कराया. ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा के सितारों एवं निर्माताओं ने दिल्ली तक का रोड ट्रिप शुरू किया और कई जगहों पर रुककर दर्शकों को लुभाने की कोशिश की. इसके अलावा जिस तरीक़े से मॉनसून दक्षिण से आता है, सुपर हिट भी दक्षिण से आईं. साल की दोनों बड़ी फिल्में रेडी और सिंघम दक्षिण फिल्मों की रीमेक थीं. दरअसल इसके साथ ही बॉलीवुड उस दौर में लौट रहा है, जहां पर सिर्फ़ मल्टीप्लैक्स नहीं, बल्कि सिंगल स्क्रीन के आम दर्शकों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती रही हैं. दबंग हो या फिर रेडी या फिर वांटेड या फिर थ्री इडियट्स, इन सबकी सफलता ने दिखा दिया है कि सिंगल स्क्रीन और छोटे शहरों की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि फिल्में बड़ी हिट तभी होंगी, जब वे हर जगह अच्छा कारोबार करेंगी. हालांकि हिट का मॉनसून थमा हुआ है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में इसके फिर से शुरू होने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में कई फिल्मों पर नज़र है. इनमें सलमान-करीना की बॉडीगार्ड, यशराज बैनर की इमरान खान-कैटरीना स्टारर मेरे ब्रदर की दुल्हन, पंकज कपूर के निर्देशन में बनी शाहिद कपूर-सोनम कपूर की मौसम, संजय दत्त-अजय देवगन स्टारर रॉस्कल, शाहरुख-करीना की मेगा बजट रा-वन, शाहरुख-प्रियंका की डॉन-2, सैफ-करीना की एजेंट विनोद, अक्षय कुमार-जॉन अब्राहम की देसी ब्वॉयज और डायरेक्टर प्रियदर्शन की अनिल कपूर-अजय देवगन स्टारर तेज वग़ैरह ऐसी फिल्में हैं, जिनमें बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कराने का दम माना जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

छोटे पर्दे पर सोनाली

आग, सरफरोश, हम साथ-साथ हैं, डुप्लीकेट, मेजर साहब और जिस देश में गंगा रहता है जैसी कई फिल्में करके सोनाली बेंद्रे ने एक एक्ट्रेस के रूप में ख़ुद को इंडस्ट्री में स्थापित किया है. 2002 में निर्माता-निर्देशक गोल्डी बहल से शादी करने के बाद सोनाली ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, मगर उनके प्रशंसक अब तक उन्हें भुला नहीं पाए. यह देखकर सोनाली का ख़ुश होना लाज़िमी है. इस बात का पता सोनाली को चला कैसे? दरअसल पिछले दिनों एक मैग्जीन के लिए फोटो शूट करते वक्त फोटोग्राफर ने उन्हें अपने निजी एक्सक्लूसिव कलेक्शन से कुछ फोटोग्राफ सोनाली को गिफ्ट किए. यह फोटोग्राफर सोनाली से नौ साल पहले मिला था और उनका फोटो शूट करने की तमन्ना रखता था, क्योंकि वह मानता है कि सोनाली इंडस्ट्री के ख़ास फोटोजेनिक फेसेस में से एक हैं. इस फोटो शूट के वक़्त मिलने पर सोनाली को उसने अपने निजी कलेक्शन से मोमेंटो के तौर पर कुछ फोटोग्राफ्स दिए. ये ख़ास फोटोग्राफ्स अब तक मीडिया में नहीं आए हैं और न किसी और ने देखे. यह देखकर सोनाली काफी ख़ुश हुईं. इतनी बढ़िया फैन फोलोविंग होने के बावजूद सोनाली फिल्मों में आने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वह टीवी शो में लगातार नज़र आ रही हैं. सिर्फ इसलिए कि उन्हें टीवी पर काम करना अच्छा लगता है. वह कहती हैं, मैं पहले भी फिल्मों के साथ टीवी कर रही थी, लेकिन अब फिल्मों में काम नहीं करूंगी. मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार और मेरा बेटा है, बाक़ी सब कुछ उनके इर्द-गिर्द घूमता है. मेरा फंडा बिल्कुल साफ है. अपने होम प्रोडक्शन की फिल्मों में पति गोल्डी के साथ जितना संभव हो पाता है, उतना ही जुड़ पाती हूं. इन दिनों गोल्डी दो फिल्में कर रहे हैं. इनमें से एक है आई मी एंड फैमिली, जिसमें जॉन अब्राहम हैं. इस फिल्म की 80 प्रतिशत शूटिंग हो चुकी है. गोल्डी एक और फिल्म जल्द ही शुरू करेंगे. सोनाली कहती हैं, सच बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ ख़ुद को मेंटेन करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है. जब मैं 20-25 साल की थी तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, सब कुछ नेचुरल था. अब मैं योगा करती हूं और खाने-पीने का भी ख्याल रखती हूं. सोनाली ने सबसे पहले स्टार प्लस का शो-क्या मस्ती क्या धूम होस्ट किया और उसके बाद वह इंडियन आइडल-4 की जज बनीं. इसके अलावा इंडियाज गॉट टैलेंट की भी वह लगातार जज बन रही हैं. कलर्स के इंडियाज गॉट टैलेंट के तीन सीजन आ चुके हैं और चौथे सीजन में भी सोनाली लगातार इस शो की जज बनी हैं.

फिल्म प्रीव्यू

मेरे ब्रदर की दुल्हन

यशराज फिल्म्स अपने बैनर तले नए निर्देशकों को लगातार अवसर दे रहा है. अली अब्बास जफर को भी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन निर्देशित करने का मौक़ा मिला. निर्देशन की कमान संभालने से पहले अली ने बारीकी से अपना काम सीखा. वह झूम बराबर झूम, टशन, न्यूयॉर्क एवं बदमाश कंपनी जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं. कुश अग्निहोत्री (इमरान खान) की उम्र 28 वर्ष है. वह मुंबई में रहता है और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता है. हालांकि इस समय वह अपने बड़े भाई लव अग्निहोत्री (अली जफर) के लिए दुल्हन ढूंढने का काम कर रहा है. लव की उम्र 30 वर्ष है और वह इंवेस्टमेंट बैंकर है और हमेशा कन्फ्यूज रहता है. वह बड़े ठाठ-बाट से रहता है. ख़ूबसूरत चेहरे उसकी कमज़ोरी हैं. अचानक एक दिन उसे एहसास होता है कि उसकी लाइफ पार्टनर देसी गर्ल होनी चाहिए. देसी गर्ल तलाशने की ज़िम्मेदारी वह अपने छोटे भाई को सौंप देता है. कुश कई परिवारों एवं लड़कियों से मिलता है. उसे बड़े मजेदार अनुभव होते हैं. आख़िरकार उसे डिंपल दीक्षित (कैटरीना कैफ) में वे सारी बातें नज़र आती हैं, जो उसका भाई अपनी पत्नी में चाहता है. 27 वर्षीय डिंपल बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ. लंदन में उसका जन्म हुआ है, लेकिन दिल से एकदम देसी है. उसे सीमाओं में बंधकर जीना पसंद नहीं है. अब वह सैटल होना चाहती है. लव और डिंपल के परिवार आपस में मिलते हैं, औपचारिकताएं पूरी होती हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है. इसी बीच हीरो कुश को डिंपल से प्यार हो जाता है यानी अपने भाई की होने वाली दुल्हन से. इसके बाद कई मजेदार घटनाएं घटती हैं. डिंपल अंत में किसकी दुल्हन बनती है, यही जानने के लिए आपको देखनी है यह फिल्म.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 05 सितंबर–11 सितंबर 2011

www.chauthiduniya.com

क्या राहुल के दौरे से

बदलेंगे हालात

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

प्रवीण महाजन

गोलीकांड से कराह रहे मावल व उसके आसपास के गांवों के हालात क्या राहुल के एकमात्र दौरे से बदल जाएंगे? कांग्रेस के महासचिव व देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की यात्रा के मद्देनज़र लोगों के मन में यह सवाल उठना लाज़िमी है, क्योंकि किसानों के आंदोलन के बाद वह भट्टा–परसौल गए और उनके दौरे के तत्काल बाद नया भूमि अधिग्रहण विधेयक बनकर तैयार हो गया. नए विधेयक के आने के बाद यह आस जगी कि अब भूमि अधिग्रहण में अपनी ज़मीन खोने वालों को भविष्य में राहत मिलेगी. इसलिए राहुल के मावल पहुंचने पर पीड़ित किसान परिवारों के मन में जो न्याय मिलने की आस जगी है वह पूरी हो पाएगी? ऐसे विचार आमजन के मन में उठने लगे हैं. आमजन की भावना राजनीति से ओत–प्रोत नहीं होती है. वे निश्छल मन से शासन–प्रशासन में बैठे लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उनके प्रति न्याय करें और उनके अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन सत्ता में बैठे मंत्री–संतरी उनकी इस अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता है. राहुल का यह दौरा कितना राजनीतिक था और कितना पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने वाला था, यह तो समय ही बताएगा.

राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान न ज़्यादा आश्वासन दिए, न किसी तरह की बात कही. सिर्फ़ इतना कहा कि मावल में जो गोलीबारी हुई वह ग़लत थी. इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पवना बांध और पवना पाइप लाइन के विषय में पूरी जानकारी ली. वह मृतकों के परिजनों से मिले और उनकी पूरी बात सुनी. वह घायलों से मिलने तलेगांव अस्पताल नहीं गए. पत्रकारों से बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा. लगता है राहुल अपने इस दौरे को राजनीतिक दुष्प्रचार का विषय नहीं बनाना चाहते थे. इसीलिए उनके दौरे की पूर्व सूचना न पुलिस को दी गई और न ही पुणे के कांगेस पदाधिकारियों को. लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का महासचिव और जिसे देश का भावी प्रधानमंत्री माना जाता हो, भला उसकी यात्रा कैसे दुष्प्रचार से दूर रह सकती है? कैसे व्यक्तिगत कही जा सकती है? वह भी उस स्थान का दौरा जहां कुछ ही दिनों पहले गोलीबारी हुई हो. राज्य के सत्ताधीशों में जिसे लेकर राजनीति की जा रही हो. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री सहित राज्य के सभी ज़िम्मेदार अफ़सर अपनी मोटी खाल बचाने की क़वायद कर रहे हों. राज्य का संपूर्ण विपक्ष जिस मामले की व्यापक आलोचना कर रहा हो. जिस मामले को लेकर पूरा विपक्ष राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से राज्य सरकार को बर्ख़ास्त करने की मांग कर रहा हो. इसलिए राहुल की यात्रा पर राजनीतिक दुष्प्रचार होने के साथ ही राजनीतिक गूढ़ार्थ लगाए जा रहे हैं. इन सबके बीच फिर भी मावल व उसके आसपास के पीड़ितों को न्याय मिलने की बात बाक़ी रह जाती है.

एक बात स्पष्ट है कि मृतक मोरेश्वर साठे की बेटी हो या कांताबाई का बेटा नितिन ठाकरे या श्यामराव तुपे के परिजन हों, उनको जो क्षति पुलिस की बर्बर कार्रवाई से हुई है उसकी भरपाई न राहुल गांधी कर सकते हैं, न उनकी सरकार और न ही विपक्षी नेता. जिसने अपना पिता खोया है, मां खोई है, जिस परिवार ने अपने घर का मुखिया खोया है और उनके साथ जो भी पीड़ित लोग हैं, उन्हें भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना कभी न करना पड़े, इसका उपाय किया जा सकता है. किया भी जाना चाहिए. इसीलिए लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि राहुल के दौरे के बाद पीड़ितों के हालात में क्या बदलाव आएंगे? राहुल दिल्ली लौट गए हैं. संभावना है कि मावल के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से कोई सिफ़ारिश करें, परंतु शंका है कि केंद्र सरकार इस मामले में तत्काल कुछ कर पाएगी, इसके आसार कम ही लगते हैं, क्योंकि वह अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निपटने में उलझी हुई है. राज्य सरकार को तो राहुल गांधी ने ही यह कहकर कठघरे में खड़ा कर दिया है कि गोलीबारी में क़ानूनी प्रावधानों की अनदेखी की गई है. इसी के साथ गोलीबारी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक दांवपेंच चले जाने लगे हैं. अब यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह राजनीति करती है या अपनी ग़लती सुधारते हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाने के उपाय करती है. घटना के दिन से लेकर अभी तक राज्य सरकार ने एक भी ऐसा क़दम नहीं उठाया है, जिससे लगे कि पीड़ितों को राहत मिल सकती है. इतना ज़रूर है कि राजनीतिक द्वंद्व की आशंकाएं बढ़ गई हैं. सत्ताधीशों को यह समझना होगा कि कहीं न कहीं उनकी सिंचाई योजनाओं के नियोजन में भारी ख़ामियों के कारण शहर से लेकर गांव तक पानी के लिए संघर्ष तेज़ हो रहा है. यह भविष्य के लिए चेतावनी है. किसानों को हम अन्नदाता–भूमिपुत्र कहकर उनका मान बढ़ाते हैं, लेकिन जब वे अपने खेतों में अन्न पैदा करने के लिए पानी मांगते हैं तो उन्हें गोली मारने में ज़रा भी देर नहीं लगाते हैं. किसान किसी भी योजना के लिए यह सोचकर ज़मीन देता है कि उस योजना के पूरा होने पर उसके खेतों को भरपूर पानी मिलेगा और वह भरपूर अन्न पैदा कर सकेगा. मावल व आसपास के गांवों के किसानों ने भी 35 वर्ष पहले यही सोचकर अपने खेतों की ज़मीन पवना बांध के लिए दी थी. तब सरकार ने उनसे जो वादे किए थे, वे अब तक पूरे नहीं किए गए. इसके बावजूद उन्होंने कभी किसी तरह का उग्र आंदोलन नहीं किया. मगर तीन साल पहले अचानक सरकार को सूझी कि नहर से जाने वाला पानी दूषित होता है, इसलिए उसने पवना पाइप लाइन योजना बना डाली. इससे किसानों को पानी पर डाका पड़ने का अहसास हुआ. तभी से उन्होंने अपनी समस्या सरकार के सामने रखनी चाही, पर सरकार तो सरकार ठहरी, उसके पास दीन–दुर्बलों की समस्या व बात सुनने का समय कहां है? वह तो राज्य के औद्योगिकीकरण की चिंता में डूबी है. पहले उद्योगपतियों की समस्या का हल करना उसकी प्राथमिकता है. उनसे राज्य के ख़ज़ाने को करोड़ों का राजस्व मिलता है. पार्टी के लिए फंड मिलता है. सरकार की यह नीति लोगों के आक्रोश की आग में घी डालने का काम कर रही है. राहुल गांधी यदि मावल यात्रा के दरम्यान पीड़ितों के दर्द के मर्म को समझ सकें हों, उससे कुछ सबक़ लिया हो तो केंद्र व राज्य में बैठी सरकार को कृषि व जल नीति को बदलने के लिए कह सकें तो इस दौरे की सार्थकता सिद्ध होगी. मावल के हालात में बदलाव आने की संभावना जगेगी, या पूरी होगी. यदि ऐसा नहीं होता है तो यह साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी की यात्रा मात्र राजनीतिक थी. विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना के चलते आनन–फानन में राहुल मावल पहुंचे और सांत्वना देने की रस्म अदायगी करके चले गए. अब ज़रा पवना में उपलब्ध पानी की स्थिति पर ग़ौर करें. पवना बांध की पानी संग्रहित करने की क्षमता 305 दस लाख घनमीटर है. इसमें से 31 दस लाख घनमीटर पानी मृतप्राय

शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

राहुल गोसीखुर्द को मावल बनने से रोकें

विदर्भ का गोसीखुर्द भी मावल बनने की राह पर है. गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना के पहले चरण में विस्थापित परिवारों की कुल संख्या 2041 है. इसमें नागपुर ज़िले के 1699 व भंडारा ज़िले के 342 कुटुंब विस्थापित हुए हैं. दूसरे चरण में 7403 कुटुंब विस्थापित हुए, जिनमें नागपुर ज़िले के 4256 व भंडारा के 3147 परिवार शामिल हैं. तीसरे चरण में 5246 परिवार विस्थापित हुए, जिनमें नागपुर ज़िले के 2377 व भंडारा के 2869 परिवार शामिल हैं. इन विस्थापित परिवारों के लोग अपनी मांगें मनवाने के लिए अलग-अलग आंदोलन करते रहते हैं. पिछले 25 सालों से निर्माणाधीन इस परियोजना के कारण उजड़े परिवारों का अब तक पूरी तरह से पुनर्वास करने में सरकार नाकाम ही साबित हुई है. पीड़ित परिवारों की शिकायतों और समस्याओं को प्रशासन ने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है. विदर्भ की स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है. राज्य सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं हैं. गोसीखुर्द प्रकल्प के राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित होने के बाद विस्थपितों ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार करने की मांग की है, लेकिन उनकी मांग पर शासन-प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है.

राज्य सरकार पर आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र जल संपत्ति नियमन प्राधिकरण अधिनियम में 11 जनवरी 2011 को जो संशोधन किया गया है, उसमें सरकार ने राज्य के 38 बांधों में संग्रहित होने वाले पानी में से 15 लाख घनमीटर पानी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवंटित कर 2.6 लाख हेक्टेयर खेतों को सिंचाई जल से वंचित कर दिया है. विदर्भ में तो स्थिति और बुरी है. विदर्भ में 55,070 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 85 बिजली परियोजनाओं को राज्य सरकार ने मंज़ूरी दी है. इन 85 में से मात्र 55 बिजली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन के लिए ही 1526.57 लाख घनमीटर पानी सरकार द्वारा आवंटित किया गया है. इसके अलावा विदर्भ के विविध ज़िलों में 21 स्टील, 11 कपड़ा मिलें, 8 सीमेंट, 9 एसईजेड, 4 पेपर कारख़ानों सहित 62 औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिया है. इनके लिए क़रीब 350 लाख घनमीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी पूर्ति विदर्भ के बांधों में उपलब्ध पानी से की जाएगी. अमरावती के किसान कई माह से आंदोलनरत हैं. उनको डर है कि उनके खेतों का पानी सोफिया प्लांट को दिया जाएगा. इन सब तथ्यों को देखते हुए विदर्भ में कहीं भी मावल जैसी स्थिति बन सकती है. इसलिए राहुल गांधी का यहां के किसान आह्वान करते हैं कि यदि वह किसानों के लिए चिंतित हैं तो विदर्भ को मावल बनने से रोकें. साथ ही अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अधर में लटकी महत्वाकांक्षी योजना को पूरा कराकर किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराएं.

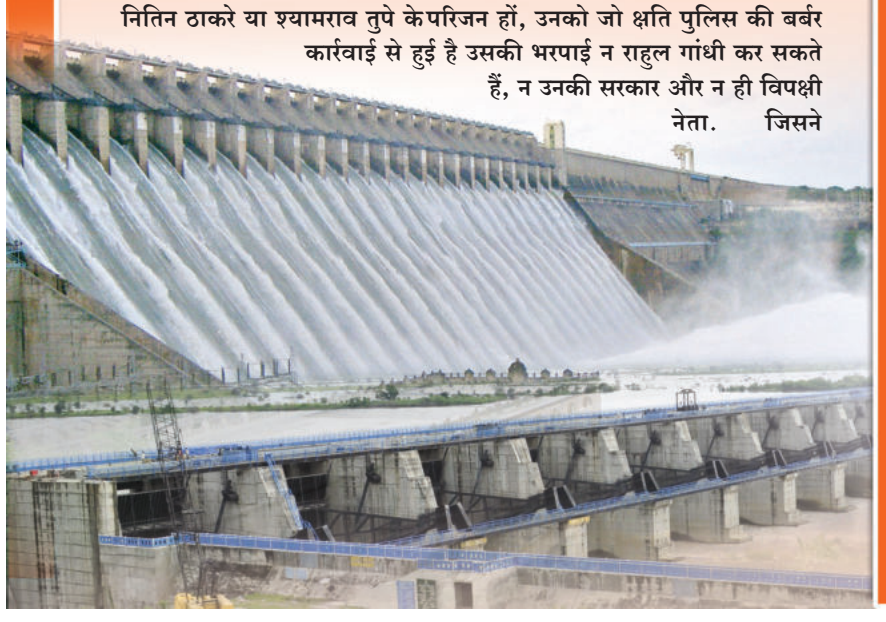

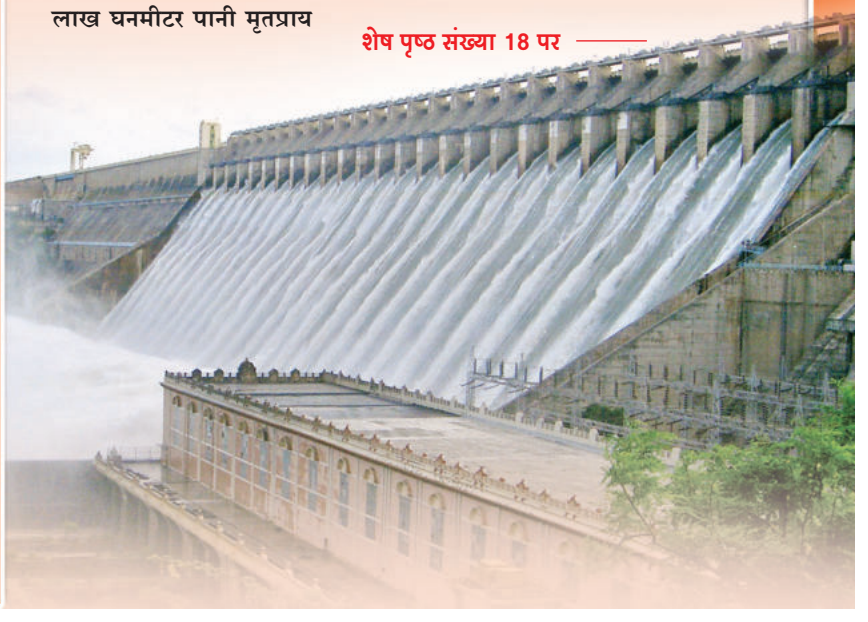

मावल के किसानों को भूमिहीन कर उनके हिस्से का पानी औद्योगिक इकाइयों को दिया जाने वाला है. लिहाज़ा भूमिहीन होने पर किसानों को रोज़ी-रोटी के लिए भटकना होगा.

राज्य के हर शहर में रालेगांव सिद्धी के संत अन्ना हज़ारे के समर्थक रैलियों के रूप में प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं. उनका नारा है-अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं.

महाराष्ट्र हलचल

आला रे आला गणपति आला! गणेशोत्सव पर मुंबई के फोर्ट बाज़ार गेट गणेशोत्सव मंडल के लोग विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की मूर्ति ले जाते हुए.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सद्भावना दिवस पर मुंबई स्थित मंत्रालय में मंत्रियों, सचिवों व कर्मचारियों को सद्भावना प्रतिज्ञा दिलाते हुए. साथ में हैं उपमुख्यमंत्री अजीत पवार व अन्य मंत्रीगण शपथ लेते हुए.

पुणे महानगर पालिका द्वारा शहर में स्थापित भारत के पहले राजीव गांधी एकेडमी फॉर ई-लर्निंग स्कूल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और उनके साथ नज़र आ रहे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, महापौर मोहनसिंह राजपाल, मनपा विपक्षी दल के नेता आबा बागुल व अन्य.

विश्व फोटोग्राफी दिवस की पूर्व संध्या पर मंत्रालय में वृत्तपत्र छायाचित्रकार संघ द्वारा आयोजित समारोह में प्रसिद्ध फोटोग्राफर यशोगोपाल सिंह के स्मरण में छायाचित्रकार 2011 का पुरस्कार सुरक्षा व जनसंपर्क महासंचालनक के सेवानिवृत्त फोटोग्राफर गिरीश देशमुख को प्रदान करते हुए सार्वजनिक निर्माण कार्यमंत्री छगन भुजबल साथ में संघ के पदाधिकारी.

नागपुर स्थित ए.के. गांधी के नैनो कार शो रूम का निरीक्षण करते हुए टाटा उद्योग समूह के अध्यक्ष रतन टाटा, शोरूम के संचालक ए.के. गांधी व अन्य.

लव ब्रेकअप ज़िंदगी के प्रचार के लिए नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेत्री दीया मिर्ज़ा, अभिनेता जायेद ख़ान व अन्य.

सद्गुरुदत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट के प्रदेश प्रमुख प. पू. भय्यूजी महाराज के मानसपुत्र पुनीतजी बालन के जन्मदिन पर आयोजित समारोह के दौरान सूर्योदय स्वरोज़गार योजना का उद्घाटन किया गया. मंचासीन पुनीतजी बालन व अन्य.

क्या राहुल के दौरे से बदलेंगे हालात

पृष्ठ 17 का शेष

है यानी अनुपयोगी है. बचे 274 दस लाख घनमीटर पानी में से वाष्पीभवन के लिए 24 दलघमी, पिंपरी-चिंचवड़ के लिए 158.67 दलघमी निर्धारित किया गया है. एमआईडीसी के लिए 59 दलघमी पानी वर्तमान में दिया जा रहा है. बचा हुआ 32 दलघमी पानी किसानों के हिस्से आता है. इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो साफ़ ज़ाहिर होता है कि पवना बांध निर्माण के लिए सबसे अधिक त्याग तो किसानों ने किया. उन्होंने अपनी खेती की ज़मीन पवना बांध बनाने के लिए दी, पर उन्हें ही सबसे कम पानी मिला. होना यह चाहिए था कि सबसे पहले अपनी ज़मीन खोने वालों के खेतों को पानी दिया जाता. अब पवना पाइप लाइन द्वारा उनके खेतों को मिल रहे पानी पर भी डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है. उनकी बची-खुची खेती की ज़मीन भी पाइप लाइन के लिए अधिग्रहीत की जा रही है. मावल के किसानों को भूमिहीन कर उनके हिस्से का पानी औद्योगिक इकाइयों को दिया जाने वाला है. लिहाज़ा भूमिहीन होने पर किसानों को रोज़ी-रोटी के लिए भटकना होगा और उन पूंजीपतियों के आगे जी हुज़ूरी करनी होगी जो उनके त्याग के कारण अपने उद्योगों को विस्तार देकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं. राहुल गांधी यदि किसानों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो उन्हें यह व्यवस्था शासन के स्तर पर करानी चाहिए कि जिन्होंने योजनाओं के लिए अपनी ज़मीन दी है उनका पानी पर पहला हक़ बने. उसके बाद औद्योगिक क्षेत्रों को पानी दिया जाए.

अब सवाल यह नहीं है कि मावल में जो हुआ उसपर राजनीतिक रोटियां सेंकी जाएं. यहां यह ध्यान देना होगा कि आम आदमी को न्याय के लिए क़ानून की अवहेलना करने की नौबत क्यों आती है. लोगों को क़ानून हाथ में लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? राज्य में निरंकुश सत्ताधीश और अफ़सरशाहों के चलते न विकास कार्य हो पा रहे हैं और न ही नागरिकों की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है. जैतापुर सुलग रहा है, पर तारापुर परमाणु संयंत्र को स्थापित हुए वर्षों बीत गए, लेकिन सरकार वहां केविस्थापितों केलिए पीने के पानी की व्यवस्था अब तक नहीं कर पाइ.

इसके लिए न्यायालय को आदेश देने पड़ रहे हैं. मतलब यह है कि पानी मात्र मावल-तारापुर या विदर्भ क्षेत्र केलोगों की ही समस्या नहीं है. पूरे महाराष्ट्र में पानी के लिए आंदोलन हो रहे हैं. राज्य में लगभग 22845 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है. इसमें से सिर्फ 15 प्रतिशत यानी 3426.75 लाख हेक्टेयर खेती को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है. मावल जैसी स्थिति कई जगह विदर्भ में भी है. महाराष्ट्र के सिंचित क्षेत्र में से मात्र 22.45 लाख हेक्टेयर खेती विदर्भ की है. कभी बरसाती पानी पर निर्भर विदर्भ के खेत हरियाली से लहलहाते थे, पर आज वहां के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं. इसका कारण यह है कि विदर्भ में जो भी सिंचाई योजनाएं बनाई गई हैं या जिनका निर्माण हो रहा है उनमें कई ख़ामियां हैं. इससे इनका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है. कुछ योजनाओं का पानी सरकार मनमाने ढंग से औद्योगिक इकाइयों को दे रही है और विदर्भ के किसान पानी को तरस रहे हैं. सरकार की इस मनमानी के कारण उन्हें खेतीबाड़ी के लिए मानसूनी बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है. राहुल गांधी विदर्भ का दौरा कर कलावती को उपकृत करके गए थे. उसकेबाद प्रधानमंत्री ने विदर्भ

केलिए किसानों को राहत देने के लिए 1100 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया था. मगर विदर्भ के हालात आज भी नहीं बदले हैं. किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है. कहीं ऐसा न हो कि विदर्भ के किसान व सामाजिक संगठन अपने हक़ के लिए मावल जैसा रास्ता अख्तियार कर लें.

feedback@chauthiduniya.com

आबा की छुट्टी तय

आलोक मिश्रा

राज्य के गृहमंत्री आर.आर. पाटिल उर्फ़ आबा की छुट्टी अब तय मानी जा रही है. अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले महानगर पालिकाओं और ज़िला परिषदों के चुनाव के मद्देनज़र अब न तो कांग्रेस और न ही राष्ट्रवादी कांग्रेस इसमें अधिक ख़तरा मोल लेना चाहती है. आबा लंबे समय से राज्य के गृह मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं. प्रदेश में कई बम विस्फोट हुए, जिस वजह से राज्य में क़ानून और व्यवस्था पर कई बार सवालिया निशान खड़े हुए. बावजूद इसके आबा का डंडा पुलिस महकमे पर चलता रहा, लेकिन अब हालात काफ़ी बदले हुए हैं. पिछले माह मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के एक माह बीत जाने के बाद भी इस दिशा में की जा रही जांच संतोषजनक नहीं है. हालांकि, इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय राकांपा को देना एक ग़लती थी. सूबे के सियासी हलक़ों में इस बयान को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस के इस तल्ख़ बयान के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजीत पवार भी आबा से ख़ासे नाराज़ बताए जा रहे हैं. वैसे तो आबा ने 13 जुलाई को मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद अपना दामन दाग़दार होने से बचा लिया था. ठीक वैसे ही जैसे तब उन्होंने पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में अपना मंत्रालय सुरक्षित कर लिया था. विधानमंडल के अधिवेशन के दौरान भी उन्होंने विपक्ष के तमाम तीखे हमलों को बख़ूबी झेल लिया था. हालांकि, कांग्रेस और राकांपा दोनों ही पार्टियों को यह बात समझ में आ गई है कि किसी भी आतंकी हमलों में विदेशी ताक़तों का हाथ बताकर इससे कन्नी काटी जा सकती है, लेकिन पुणे स्थित मावल में हुए गोलीबारी की घटना का जवाब न तो कांग्रेस को देते बन रहा है और न ही राकांपा को. जबकि, दोनों ही मामले राज्य की क़ानून और व्यवस्था से जुड़े हुए हैं. उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई को पंढरपुर की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को एक कंटेनर ने कुचल दिया था. इस हादसे में 17 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में नाराज़ तीर्थयात्रियों ने तोड़फोड़ व आगज़नी की थी. वैसे तो यह मामला दब गया था, लेकिन पिछले दिनों मावल में पाइप लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई ज़मीन के मुआवज़े को लेकर जमा हुए ग्रामीणों पर पुलिस ने फायरिंग की. इस घटना के बाद समूचे पश्चिम महाराष्ट्र में सत्ताधारी कांग्रेस और राकांपा के ख़िलाफ़ जनता में आक्रोश पैदा हो गया. आबा ने इस मामले में भी पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसकेबाद जारी हुए वीडियो फुटेज ने पुलिस और आबा के दावों की पोल खोल दी. वीडियो फुटेज में यह दिखाया गया है कि मारे गए किसान को पुलिस ने पहले पीटा और फिर भागने दिया. बाद में उस पर गोली चला दी. इस ख़ुलासे के बाद दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया. मानवाधिकार आयोग ने भी पुणे की पुलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर से इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की पाटिल से नाराज़गी की एक और वजह यह है कि विधानसभा में इस मामले पर हंगामे के दौरान गृह मंत्री ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश से जांच कराने की घोषणा की थी, लेकिन इसकी जानकारी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री को नहीं दी गई थी. इस कारण अब दोनों ही आबा से नाराज़ बताए जा रहे हैं. वैसे भी विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मुंबई में भू-माफ़िया की हरकत भी सिरदर्द बनी हुई है. मराठवाड़ा में तीर्थयात्रियों पर गोलीबारी के साथ ही किसानों की ख़राब हालत सर्वविदित है. ऐसे में अजीत पवार के गढ़ में ऐसी घटनाएं विपक्ष को ताक़त देने जैसी ही हैं. जैतापुर का मुद्दा अब भी बना हुआ है. सूत्र बताते हैं कि अजीत पवार ने अपनी नाराज़गी राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के सामने भी व्यक्त कर दी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी कई नेता आबा की कार्य प्रणाली से नाराज़ बताए जाते हैं. कई पुलिस अधिकारी भी अब राकांपा नेताओं की नहीं सुनते. राज्य के नक्सलग्रस्त इलाके गढ़चिरोली का पालकमंत्री बन कर आबा ने जो वाहवाही बटोरने का प्रयास किया था, वह अब नेपथ्य में चला गया है. नक्सली वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं. कुल मिलाकर अब बाबा (पृथ्वीराज चव्हाण), दादा (अजीत पवार) के बीच फंसे आबा का क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

feedback@chauthiduniya.com

पुलिस किसकी ? ये क्या हो रहा है...

गांधीवादी पार्टी के युवा मंडली के चुनाव हो और उसमें पुलिस का बंदोबस्त हो, कुछ हज़म नहीं होता है. गांधीवादी तो शांतिपूर्वक अनुशासित होकर अपना काम करते हैं. अपनी उपेक्षा और दिल की पीड़ा को भी शांति से व्यक्त करते हैं. अपनी बातों को मनवाने के लिए शासन-प्रशासन पर यदि कुछ ज़्यादा ज़ोर डालना पड़ा तो सत्याग्रह या अनशन पर बैठ जाते हैं. इसका ताज़ा उदाहरण है अन्ना हज़ारे का दिल्ली का अनशन. उनके समर्थक हज़ारों की संख्या में उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन क्या मजाल कि कोई अनुशासन तोड़े. समूचा रामलीला मैदान अन्नामय और देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है. आख़िर अन्ना भी तो गांधी की विरासत को लेकर चल रहे हैं, फिर बात-बात पर जिस पार्टी के नेता महात्मा गांधी का नाम रटते हों उसकी युवा मंडली के चुनाव में पुलिस का भारी बंदोबस्त करना किसी आश्चर्य से कम नहीं है. ख़बर है कि उपराजधानी से निर्वाचित नेता जो राज्य के मंत्री भी हैं, उन्होंने पुलिस कप्तान से ख़ासतौर पर पुलिस बंदोबस्त करने का अनुरोध किया है. कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि इन मंत्री महोदय के इशारे पर उपराजधानी की पुलिस नाचती है. ख़ास बात है कि मंत्री जी के बेटे भी इस चुनावी समर में मैदान में हैं. यहां मसला यह नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं. यहां सवाल यह है कि जब एक गांधीवादी विचारधारा को मानने वाली पार्टी की युवा मंडली का चुनाव होने जा रहा है, तो पुलिस तैनात करने की ज़रूरत क्या है? वैसे भी यहां हत्या, बलात्कार, डकैती, झपटमारी जैसे अपराध दिन-दहाड़े होते रहते हैं. मौक़े पर पुलिस पहुंच नहीं पाती है और अपराधी अपने नापाक इरादों को अंजाम देकर छुट्टा घूमते रहते हैं. ऐसे हालात में वहां पुलिस को होना चाहिए, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि ऐसी तमाम घटनाओं के बाद भी पुलिस कहीं नज़र नहीं आती. सूबे में पुलिस महकमा तो वैसे भी कर्मियों की कमी से जूझ रहा है. उससे आम आदमी सुरक्षा की मांग करता है तो पहले पैसे की मांग की जाती है. उसके बिना सुरक्षा मिलना असंभव है. फिर पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन दे सकता है. ऐसे में यह सवाल लाज़िमी है कि जिन मंत्री महोदय ने कांग्रेस पार्टी की युवा मंडली के चुनाव के लिए पुलिस बंदोबस्त करने का आग्रह किया है, क्या वह पुलिस विभाग पर पड़ने वाले आर्थिक भार का भुगतान करेगा? क्या कांग्रेस पार्टी पुलिस बंदोबस्त पर होने वाला ख़र्च उठाएगी? ऐसे में युवा मंडली के आदर्श महात्मा गांधी नहीं हैं, राहुल गांधी नहीं हैं, तो इनका आदर्श फिर कौन हो सकता है. आज गांधी परिवार में तो कोई तोड़फोड़ करने वाला नहीं है. मगर पूरी पार्टी वोट मांगते समय महात्मा गांधी का उल्लेख कर जनता को याद दिलाती है कि उसका इतिहास सौ साल पुराना है. क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी की युवा मंडली को पार्टी का इतिहास नहीं बताती है कि कभी एक महात्मा गांधी हुए थे, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने सत्याग्रह का हथियार अपना कर अंग्रेज जैसे शक्तिशाली दुश्मन को बिना तलवार-ढाल, बिना बंदूक़-तोप के देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था. यदि अब तक नहीं बताया है तो अन्ना हज़ारे व उनके समर्थकों का उदाहरण सामने रखकर यह बताया जा सकता है कि आज अन्ना के भय से केंद्र व राज्य सरकारें कैसे कांपने लगी हैं. यदि गांधी की बात मानोगे, तो कभी पुलिस बंदोबस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जनता आपके साथ रहेगी. आपकी हालत आज के प्रधानमंत्री जैसी निर्बल नहीं हो जाएगी. इसलिए हिंसक विचारों को त्याग कर चुनाव लड़ो. मगर लगता नहीं कि जिन मंत्री महोदय ने पुलिस बंदोबस्त करने को कहा है, वह ख़ुद महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं. देखो बापू तुम्हारी कांग्रेस की क्या दशा हो गई है.

नीतिन राउत

पूरी पार्टी वोट मांगते समय महात्मा गांधी का उल्लेख कर जनता को याद दिलाती है कि उसका इतिहास सौ साल पुराना है. क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी की युवा मंडली को पार्टी का इतिहास नहीं बताती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र के अन्ना बने जन-जन के अन्ना

राजेश नामदेव

अन्ना नहीं यह आंधी है, देश का दूसरा गांधी है- यह नारा आज दिल्ली से लेकर रामेश्वरम और जयपुर से लेकर पटना तक गूंज रहा है. अन्ना हज़ारे आज एक ऐसा नाम बन गया है जिसे सुनते ही देश के युवाओं का रोम-रोम जोश से भर उठता है. अन्ना भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू कर महाराष्ट्र की सीमा से निकलकर विश्वव्यापी हो गए. आंदोलनों के दौरान होने वाली हिंसा की वजह से अपने बच्चों को दूर रहने की हिदायत देने वाले लोग भी अपने नन्हें-मुन्नों को लेकर आंदोलन स्थल जाकर न सिर्फ़ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, बल्कि रैलियों, कैंडल मार्च में उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं. उन्हें पुलिस के लाठी चलाने या गोली बरसाने का बिल्कुल भी भय नहीं सता रहा है. अन्ना के आंदोलन से केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक चिंतित है. सत्ताधीश आंदोलन को समाप्त करने का उपाय खोजने में लगे हैं. महाराष्ट्र की मायानगरी का आज़ाद मैदान हो या नागपुर का रिज़र्व बैंक चौक, पुणे हो या औरंगाबाद, राज्य के हर शहर में रालेगांव सिद्धी के संत अन्ना हज़ारे के समर्थक दिन भर न केवल नारे लग रहे हैं, बल्कि रैलियों के रूप में प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं. उनका नारा है-अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. जन लोकपाल बिल लाना है भ्रष्टाचार को दूर भगाना है. नारे लगाने वाले लोग किसी राजनीतिक दल द्वारा जुटाई गई भीड़ का हिस्सा नहीं है. इस आंदोलन में ग्रामीण क्षेत्र के महिला-पुरुष भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. अन्ना ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है कि आज महाराष्ट्र सहित पूरा देश आंदोलित हो उठा है. एक गांव से समाजसेवा की लौ जलाने वाले अन्ना आज देश की मशाल बन गए हैं.

आंदोलन पर आमजन की प्रतिक्रिया

मैं अन्ना हज़ारे के साथ हूं. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त जन लोकपाल क़ानून बनाया जाना चाहिए. -तेजस क्षीरसागर, वर्धा

भ्रष्टाचार को सहते बहुत समय गुज़र गया है. अब इससे मुक्ति दिलाने के लिए अन्ना हज़ारे ने आंदोलन शुरू किया है तो सरकार को सख्त जन लोकपाल बिल को पास करना चाहिए. - विलास दिग्रसे, नागपुर

भ्रष्टाचार देश में बढ़ता ही जा रहा है. हर कोई इससे परेशान है. इसलिए जन लोकपाल बिल बनाना चाहिए. मैं इसी वजह से अन्ना का समर्थन करती हूं. - संगीता मिश्रा, नागपुर

जब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं कसी जाती, तब तक मैं अन्ना ही रहूंगा. - श्रीप्रकाश पंडा (छात्र एमएसडब्ल्यू)

जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, उन्हें सत्ता में न रहने दिया जाए. उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. इसलिए हम सब चाहते हैं कि जन लोकपाल क़ानून जल्द से जल्द बने. - ललिता नंदकर, सेंट्रल इंडिया मज़दूर संघ की कार्यकर्ता

अन्ना का समर्थन करने के लिए मैं अपने मित्रों के साथ आई हूं. भ्रष्टाचार को मिटाना है, जन लोकपाल बिल को लाना है. - कल्पना चिंचखेड़े, कोराड़ी

मैं अपना व्यवसाय बंद कर आंदोलन में शामिल हुआ हूं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता हूं. साथ की अन्य लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन में शामिल हों. - सचिन गुमगांवकर (वीडियोग्राफर)

आज़ादी के बाद 63 सालों में चार बार लोकपाल बिल बनाने की मांग की गई, लेकिन सरकार ने अब तक नहीं बनाया है. भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जन लोकपाल बिल का बनना ज़रूरी है, इसलिए मैं इस आंदोलन में शामिल होने आया हूं. - अविनाश पटवर्धन (सामाजिक कार्यकर्ता)

जन लोकपाल क़ानून बनना चाहिए. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में हम अन्ना के साथ हैं. - सचिन खेड़े, दहेगांव

भ्रष्टाचार ख़त्म हो, सब की इच्छा है. इसलिए सरकार को जन लोकपाल क़ानून को शीघ्र मंज़ूरी देनी चाहिए. - मयूर अग्रवाल

मुझे यह पता है कि भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म नहीं होगा, परंतु जन लोकपाल क़ानून बन जाने से इसपर रोक लगेगी. अन्ना ने देश को एक राह दिखाई है. इसलिए परिवार के साथ आंदोलन में हिस्सा लेने आया हूं. - रमेश पारधी, वडधामना

हम अन्ना के साथ हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के नासूर को ख़त्म करना है. - उर्वशी डूंभरे (छात्रा), नागपुर

लोकशाही में जन आंदोलन महत्व भूल गए थे लोग, लेकिन अन्ना ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ इसे छेड़ कर लोगों को चैतन्यमय कर दिया है. सरकार को जनभावना का आदर करना चाहिए. - रवि कामखेडिकर, जनाक्रोश संस्था के पदाधिकारी

मैं अपनी दुकान बंद कर अन्ना के आंदोलन में शामिल हूं. भ्रष्टाचार को हर हाल में ख़त्म करना है. पूरा देश अन्ना हज़ारे के साथ है. - अरविंद भास्कर (फोटोग्राफर)

मंत्री-अफ़सर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं. बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं. हमारा नौकरी करने के बाद भी गुज़ारा नहीं हो पाता है. अन्ना का आंदोलन भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए है. मैं उनकी आभारी हूं. - सायमवार (नौकरी)

भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वह ग़लत है. हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है. भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए अन्ना ने जो आंदोलन छेड़ा है, वह बिल्कुल सही है. हम इसका समर्थन करते हैं. - पिंकी खानोकर (टी.वी. रिपोर्टर)

बहुत दिनों बाद इतना बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हो रहा है. सभी को इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए. अन्ना ज़िंदाबाद. - उज्ज्वल सिंह (छात्र), वर्धा

भ्रष्टाचार को हटाने के लिए जनलोकपाल क़ानून का बनना ज़रूरी है. - मनीष (छात्र)

मैं अन्ना के साथ हूं. अन्ना हमारे लिए ही आंदोलन कर रहे हैं. भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हर शख़्स त्रस्त है. इसे हटाने के लिए जन लोकपाल बिल का पास होना ज़रूरी है. - वेद जोशी

किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं. ग़रीब महंगाई से त्रस्त हैं और हमारे नेता भ्रष्टाचार करने में मस्त हैं. इसलिए जन लोकपाल क़ानून बनना ही चाहिए. - रिंकू मदनराव, (दुकानदार)

- निशा वर्मा, अजंता भौमिक

जीवन यात्रा

अन्ना हज़ारे का जन्म 15 जून, 1937 को महाराष्ट्र के अहमद नगर के भिंगारी गांव के एक किसान परिवार में हुआ. उनके पिता का नाम बाबूराव हज़ारे और मां का नाम लक्ष्मीबाई हज़ारे है. उनका बचपन ग़रीबी में गुज़रा. पिता मज़दूर थे और दादा फ़ौज में थे. दादा की पोस्टिंग भिंगनगर में थी. वैसे अन्ना के पुरखों का गांव अहमद नगर ज़िले में ही स्थित रालेगांव सिद्धि में था. दादा की मौत के सात साल बाद अन्ना का परिवार रालेगांव आ गया. अन्ना के छह भाई हैं. परिवार में तंगी का आलम देखकर अन्ना की बुआ उन्हें मुंबई ले गईं. वहां उन्होंने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की. परिवार पर कष्टों का बोझ देखकर वह दादर स्टेशन के बाहर फूल बेचनेवाले की दुकान में 40 रुपये की पगार में काम करने लगे. इसके बाद उन्होंने फूलों की अपनी दुकान खोल ली और अपने दो भाइयों को भी रालेगांव से बुला लिया. वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद सरकार की युवाओं से सेना में शामिल होने की अपील पर अन्ना 1963 में सेना की मराठा रेजीमेंट में भर्ती हो गए. उनकी पहली नियुक्ति पंजाब में हुई. 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अन्ना हज़ारे खेमकरण सीमा पर तैनात थे. 12 नवंबर 1965 को चौकी पर पाकिस्तानी हवाई बमबारी में वहां तैनात सारे सैनिक मारे गए. इस घटना ने अन्ना की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया. उनकी नियुक्ति मुंबई और जम्मू-कश्मीर में भी हुई. 1975 में जम्मू पदस्थापन के दौरान उन्होंने सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली. वह रालेगांव सिद्धि में रहने लगे और इसी को अपनी सामाजिक कर्मस्थली बना लिया. कहते हैं कि 1965 के युद्ध में मौत से साक्षात्कार के बाद वह बहुत निराश हो गए थे. वह आत्महत्या करने तक की सोचने लगे थे. मगर जब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने विवेकानंद की एक बुकलेट कॉल टु द यूथ फॉर नेशन देखी. इसका उनके मन पर गहरा असर पड़ा, तभी उन्होंने अपना जीवन समाज को समर्पित करने का फ़ैसला कर लिया. उन्होंने गांधी और विनोबा की भी पुस्तकें पढ़ीं. 1970 में उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर स्वयं को सामाजिक कार्यों के लिए पूर्णतः समर्पित करने का संकल्प लिया. रालेगांव में बिजली और पानी की कमी थी. अन्ना ने गांव वालों को नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया और ख़ुद भी इसमें योगदान दिया. गांव में जगह-जगह पेड़ लगाए गए. गांव में सौर ऊर्जा और गोबर गैस के ज़रिए बिजली की सप्लाई शुरू कराई. उन्होंने अपनी ज़मीन बच्चों के हॉस्टल के लिए दान कर दी और अपनी पेंशन का सारा पैसा गांव के विकास के लिए समर्पित कर दिया. वह गांव के मंदिर में रहते हैं और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए बनने वाला खाना खाते हैं. आज गांव का हर शख़्स आत्मनिर्भर है. आस-पड़ोस के गांवों के लिए भी यहां से चारा, दूध आदि जाता है. यह गांव आज शांति, सौहार्द एवं भाईचारे की मिसाल बन गया है.

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन

पहली बार 1991 में अन्ना हज़ारे ने महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा की सरकार के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की. ये मंत्री थे-शशिकांत सुतार, महादेव शिवणकर और बबन घोलाप. अन्ना ने उन पर आय से ज़्यादा संपत्ति जोड़ने का आरोप लगाया था. सरकार को दो मंत्रियों सुतार और शिवणकर को हटाना पड़ा था. घोलाप ने अन्ना के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा कर दिया था. अन्ना अपने आरोप के समर्थन में न्यायालय में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए और उन्हें तीन महीने की जेल हो गई. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने उन्हें एक दिन की हिरासत के बाद छोड़ दिया था. एक जांच आयोग ने शशिकांत सुतार और महादेव शिवणंकर को निर्दोष बताया था, लेकिन अन्ना हज़ारे ने कई शिवसेना और भाजपा नेताओं पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए थे. 1997 में अन्ना हज़ारे ने सूचना के अधिकार क़ानून के समर्थन में मुंबई के आज़ाद मैदान से अपना अभियान शुरू किया था. 9 अगस्त, 2003 को मुंबई के आज़ाद मैदान में ही अन्ना हज़ारे आमरण अनशन पर बैठ गए. 12 दिन तक चले आमरण अनशन के दौरान अन्ना हज़ारे और सूचना के अधिकार आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला. आख़िरकार 2003 में ही महाराष्ट्र सरकार को इस क़ानून के एक मज़बूत मसौदे को पास करना पड़ा. बाद में इसी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया. नतीजतन 12 अक्टूबर 2005 को भारतीय संसद ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया. अगस्त, 2006 में सूचना के अधिकार में संशोधन प्रस्ताव के ख़िलाफ़ अन्ना ने 11 दिन तक आमरण अनशन किया, जिसे देशभर में समर्थन मिला. इसके परिणामस्वरूप सरकार ने संशोधन का इरादा बदल दिया. 2003 में अन्ना ने कांग्रेस और एनसीपी सरकार के चार मंत्रियों-सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पद्मसिंह पाटिल को भ्रष्ट बताकर उनके ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ दी और भूख हड़ताल पर बैठ गए. महाराष्ट्र सरकार ने इसके बाद एक जांच आयोग का गठन किया. नवाब मलिक ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया. आयोग ने जब सुरेश जैन के ख़िलाफ़ आरोप तय किए तो उन्हें भी त्यागपत्र देना पड़ा.

व्यक्तित्व व विचारधारा

व्यक्तित्व और विचारधारा गांधी की विरासत उनकी थाती है. क़द-काठी में वह साधारण ही हैं. सिर पर गांधी टोपी और बदन पर खादी है. आंखों पर मोटा चश्मा है, लेकिन उनको दूर तक दिखता है. महात्मा गांधी के बाद अन्ना हज़ारे ने ही भूख हड़ताल और आमरण अनशन को सबसे ज़्यादा बार बतौर हथियार इस्तेमाल किया है. इसके ज़रिए उन्होंने भ्रष्ट प्रशासन को पद छोड़ने एवं सरकारों को जनहितकारी क़ानून बनाने पर मजबूर किया है. आज वह फिर पिछले 40 साल से अटके लोकपाल बिल को पास कराने के लिए अनशनरत हैं. अन्ना और सरकार के बीच मतभेद के कई कारण हैं.

सरकारी बिल

1. सामान्य जनता को जो भ्रष्टाचार सहन करना पड़ता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अधिकार लोकपाल के पास नहीं है. लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास शिकायत आने पर वह जांच करने के बाद निर्णय लेंगे कि कार्रवाई की जाए या नहीं.

2. लोकपाल केवल एक सलाहकार संस्था है और वह सिर्फ़ सक्षम प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम करेगी.

3. लोकपाल को पुलिस को आदेश देने का अधिकार नहीं रहेगा. वह एफ़आईआर भी नहीं दर्ज करा सकेगा. फ़ौजदारी मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा.

4. लोकपाल और सीबीआई का आपस में कोई संबंध नहीं होगा. दोनों अपना काम अलग-अलग करेंगे.

5. भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए जाने पर किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को 6 माह से 6 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है.

6. प्रधानमंत्री, न्यायपालिका से जुड़े मामलों की जांच लोकपाल नहीं कर सकेगा. सांसदों के मामले की जांच कर सकेगा. मात्र संसद के अंदर सांसदों द्वारा किए जाने वाले क्रिया-कलापों की जांच नहीं कर सकेगा.

7. केवल अराजपत्रित अधिकारियों की लोकपाल जांच कर सकेगा, बाक़ियों की नहीं.

8. लोकपाल को सज़ा देने का अधिकार नहीं है. वह सज़ा के लिए मामले को न्यायालय के समक्ष पेश करेगा, जहां क़ानून व प्रावधानों के अनुसार सज़ा दी जा सकेगी.

9. केवल उच्चस्तर पर होने वाले भ्रष्टाचारों की जांच लोकपाल द्वारा की जा सकेगी.

जन लोकपाल बिल

1. आम जनता से शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई करने का अधिकार लोकपाल को रहेगा.

2. यदि कोई जांच में दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार लोकपाल को होगा.

3. लोकपाल को पुलिस के अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह एफ़आईआर भी दर्ज कर सकेगा.

4. लोकपाल और सीबीआई मिलकर एक स्वतंत्र प्राधिकरण होगा. सीबीआई का लोकपाल में विलय किया जाएगा.

5. भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को कम से कम 6 साल की और अधिक से अधिक उम्रक़ैद की सज़ा होनी चाहिए.

6. प्रधानमंत्री और न्यायाधीशों की जांच भी लोकपाल कर सकेगा. इसके लिए मात्र सात सदस्यीय समिति की मंज़ूरी लेनी होगी. सांसदों की सभी तरह से जांच की जा सकेगी.

7. सभी अधिकारियों की जांच कर सकेगा.

8. लोकपाल एक स्तर तक स्वयं दोषी को सज़ा दे सकेगा अथवा प्रकरण को न्यायालय के सामने पेश कर सकेगा. नौकरी से बर्ख़ास्त करना, कारावास, संपत्ति ज़ब्त करने की सज़ा सुना सकेगा.

9. भ्रष्टाचार से संबंधित सभी तरह के मामले की जांच लोकपाल कर सकेगा.

feedback@chauthiduniya.com

फोटो-प्रभात पाण्डेय

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

विधायक फडणवीस ने कहा कि कथित शिक्षा सम्राटों की सुविधा के लिए सरकार ने निजी विश्वविद्यालय शुरू करने को मंज़ूरी दी है.

अजीत पवार को कब समझ आएगी

राज्य सरकार के सीमित आर्थिक सोत होने के कारण विश्वविद्यालयों का आर्थिक बोझ उठाना संभव नहीं है. यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने के बाद निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना समय की मांग है. उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रसिद्ध विप्रो कंपनी के मालिक अज़ीम प्रेमजी ने कहा था कि सरकार यदि निजी विश्वविद्यालय शुरू करने की अनुमति देती है तो विप्रो आगे आने के लिए तैयार है. अज़ीम प्रेमजी जैसे उद्योगपति अगर राज्य में निजी विश्वविद्यालय शुरू कर रहे हैं तो उसका विरोध करना राज्य को शिक्षा के क्षेत्र पीछे ढकेलने जैसा होगा. कारपोरेट क्षेत्र के कुछ औद्योगिक घरानों ने स्कूल, कॉलेज शुरू किए हैं और उन संस्थानों में उपलब्ध सुविधाएं, शैक्षणिक सामग्रियां, योग्य शिक्षकों की व्यवस्था सराहनीय है.

युधिष्ठिर जोशी

महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून अधिवेशन तीन हफ्ते पूर्व ख़त्म हो चुका है. आख़िरी हफ्ते में मुंबई–पुणे महामार्ग पर मावल क्षेत्र में किसानों पर हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मृत्यु से विधानमंडल गूंज रहा था. सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस गड़बड़ी में सरकार ने कुछ विधेयक पेश किए. उसमें एक महत्वपूर्ण विधेयक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मान्यता देने वाला था. इस विधेयक पर विधिवत चर्चा होना आवश्यक था, लेकिन विपक्षी दलों के मावल क्षेत्र में हुई गोलीबारी मामले में व्यस्त होने और विधानसभा में हुए हंगामे, बहिष्कार के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी. निजी विश्वविद्यालय के विधेयक पर सिर्फ़ नागपुर के भाजपा के युवा विधायक देवेंद्र फडणवीस द्वारा चैनलों को दी गई प्रतिक्रिया सुनने को मिली. विधायक फडणवीस ने कहा कि कथित शिक्षा सम्राटों की सुविधा के लिए सरकार ने निजी विश्वविद्यालय शुरू करने को मंज़ूरी दी है. वर्तमान में पतंगराव कदम, दत्ता मेघे, डी.वाय. पाटिल प्रभृति कांग्रेसी जन शिक्षा सम्राट हैं. उसमें कुछ अभिमत विश्वविद्यालय हैं. उसमें से कुछ में विश्वविद्यालयों का कार्य व्यवहार उलट–पलट है. ऐसे ग़ैर क़ानून सम्मत व्यवहार करने वाले अभिमत विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर हैं. ऐसे विश्वविद्यालयों की सुविधा के लिए ही सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को मंज़ूरी देने वाला विधेयक पेश किया है, ऐसा विधायक देवेंद्र फडणवीस का कहना है. उनकी टिप्पणी पूरी तरह से ग़लत है, यह कहना उचित नहीं है. लेकिन सिर्फ़ एक कारण के लिए निजी विश्वविद्यालय शुरू करने की मंज़ूरी को नकारना ग़लत होगा. समाज में अच्छी–बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं. कोई क़ानून या नियम का पालन अपने स्वार्थ के लिए करता है तो कोई समाज के उद्धार के लिए इसका उपयोग करता है, परंतु ऐसा नियम या क़ानून उपयोग का नहीं है इसलिए यह नहीं होना चाहिए, यह ग़लत है. विधायक देवेंद्र फडणवीस एकतरफ़ा टिप्पणी करेंगे, ऐसी अपेक्षा नहीं थी. उच्च और तांत्रिक शिक्षा मंत्री राजेश टोपे ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक पेश करने के लिए जो अध्ययन किया और अपने भाषण में जो कहा उससे राज्य के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है.

वर्तमान में विश्वविद्यालय सरकार के अधिकार में हैं. सरकार ही विश्वविद्यालयों की संचालक और मालिक है. विकेंद्रीकरण की नीति राज्य सरकार की है, पर विश्वविद्यालय स्वायत्त हैं. ऐसा कहा जाता है, फिर भी सरकारी नौकरशाही, मंत्रियों के अदृश्य हाथ सरकार के आधिपत्य के नीचे विश्वविद्यालय में भरपूर प्रमाण में उलट–पलट करते रहते हैं, यह जगज़ाहिर है. मात्र विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्था चलाना सरकार का काम नहीं है. राज्य सरकार के सीमित आर्थिक स्रोत होने के कारण विश्वविद्यालयों का आर्थिक बोझ उठाना संभव नहीं है. यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने के बाद निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना समय की मांग है.

उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रसिद्ध विप्रो कंपनी के मालिक अज़ीम प्रेमजी ने कहा था कि सरकार यदि निजी विश्वविद्यालय शुरू करने की अनुमति देती है तो विप्रो आगे आने के लिए तैयार है. अज़ीम प्रेमजी जैसे उद्योगपति अगर राज्य में निजी विश्वविद्यालय शुरू कर रहे हैं तो उसका विरोध करना राज्य को शिक्षा के क्षेत्र पीछे ढकेलने जैसा होगा.

कारपोरेट क्षेत्र के कुछ औद्योगिक घरानों ने स्कूल, कॉलेज शुरू किए हैं और उन संस्थानों में उपलब्ध सुविधाएं, शैक्षणिक सामग्रियां, योग्य शिक्षकों की व्यवस्था सराहनीय है. औद्योगिक घरानों के स्कूल सिर्फ़ महंगे हैं, ऐसी टिप्पणी करना एकपक्षीय है, क्योंकि कारपोरेट क्षेत्र में स्पर्धा होगी ही. उससे मेरा उद्योग प्रथम श्रेणी का होना चाहिए, इसके लिए स्पर्धा रहती है. मैं किसी भी स्पर्धा में नहीं हूं, ऐसा कहने वाला व्यक्ति रास्ते पर मोटर–कार चलाते समय जाने–अनजाने स्पर्धा करने लगता है. ऐसा ही निजी उद्योगों में रहता है. स्पर्धा होनी ही चाहिए, नहीं तो प्रगति नहीं होगी. स्पर्धा सिर्फ़ गला काटने वाली और फंसाने वाली नहीं होनी चाहिए.

निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए तो विदेशी शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालय सहयोग व क़रार करके वहां की सशक्त शिक्षा पद्धति का लाभ विद्यार्थियों को होगा. शिक्षकों के आदान–प्रदान के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों से क़रार करके उन विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ शिक्षकों का लाभ राज्य के विद्यार्थियों को मिलेगा. आज यहां से हज़ारों विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं और लाखों रुपये ख़र्च करते हैं. वहीं अगर महाराष्ट्र में उद्योगपति अज़ीम प्रेमजी, अंबानी, गोदरेज या टाटा जैसे औद्योगिक घरानों ने विश्वस्तरीय साधन संपन्न विश्वविद्यालय उपलब्ध करा दिए तो उनका स्वागत नहीं करना चाहिए क्या? अगर शासकीय विश्वविद्यायल में सुधार करके व नियमों को ढीला कर निजी विश्वविद्यालय को खोला गया तो उच्च शिक्षा में क्रांति आ जाएगी. इसलिए राज्य सरकार को जागरूक होने की ज़रूरत है. शासकीय स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ना समय गंवाना है, ऐसी धारणा रूढ़ होना ग़लत है. पुणे ज़िले के मावल क्षेत्र के किसानों को पानी के लिए सड़क पर आना पड़ा. भारी भीड़ पर पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी. तीन लोगों की मौत हुई. इस घटना पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है. केवल आरोप–प्रत्यारोप करने से, एक–दूसरे के उपर कीचड़ उछालने से काम नहीं चलेगा. यह भविष्य सूचक घटना है. यह बात शासनकर्ता, विपक्षी दल और संपूर्ण समाज को शांतिपूर्वक समझ लेनी चाहिए. सत्तापक्ष को अत्यंत संयम से काम लेना चाहिए. राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की टिप्पणी उचित नहीं है. अजीत पवार को अपने चाचा शरद पवार से संयम और प्रामाणिकता का ज्ञान लेना चाहिए.

मावल में पवना नदी है. यह मावल के किसानों की जीवनदायिनी नदी है. पवना नदी पर ही उन किसानों का जीवन निर्भर है. पिंपरी–चिचवड़ महानगर पालिका अजीत पवार के निजी क्षेत्र के समान है. वहां उनका एकछत्र राज्य है. पिंपरी–चिचवड़ महानगर पालिका मुंबई के बाद राज्य की सबसे अमीर महानगर पालिका समझी जाती है. पिपरी–चिंचवड़ में बढ़ती जनसंख्या, उद्योग क्षेत्र के बढ़ने से वहां पानी की आपूर्ति होना आवश्यक है. पवना नदी के बांध से पिंपरी–चिंचवड़ को जलापूर्ति करने की योजना पिछले दस साल पूर्व बनाई गई थी. भूमिगत दो पाइप लाइन डालकर पवना नदी का पानी शहरवासियों को देने की योजना बनाई थी, लेकिन यह सब दस साल पूर्व की योजना थी. इन दस सालों में तापमान और पर्यावरण के सभी गणित बदल चुके हैं. सभी को इसका अनुभव है. बढ़ता तपामान, अनिश्चित मानसून ऐसे बहुत से कारणों से प्रकृति का चक्र घूम रहा है. शहर बढ़ रहे हैं. वहां की जनसंख्या बढ़ गई यानी निर्माण कार्य बढ़े, उद्योग–धंधे बढ़े. पिंपरी–चिंचवड़ का भी वही हाल हुआ. उनकी पानी की आवश्यकता बढ़ी. अगर पिंपरी–चिंचवढ़ को जलापूर्ति ज़्यादा होगी तो किसानों की खेती कैसे होगी? इस डर से मावल के किसानों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी. अगर शिवसेना या भाजपा ने इसका लाभ उठा लिया तो उसमें उनकी क्या ग़लती है? राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस ऐसा फ़ायदा नहीं उठाती है क्या?

पवना के पानी से उपजे असंतोष व राजनीतिक घटनाक्रम को थोड़ी देर के लिए अगल रख दें, लेकिन वहां के किसानों की व्यथा भी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने निष्पक्ष भाव से क्यों नहीं समझी. पिंपरी–चिंचवड़ महानगर पालिका ही सर्वस्व है क्या? सब जगह दादागिरी, अकड़बाज़ी, भड़कना नहीं चलता है. यह समझ उपमुख्यंमत्री अजीत पवार को कब आएगी? पानी के लिए विवाद की यह शुरुआत है. दिन–ब–दिन जल संग्रहण की क्षमता कम हो रही है. जनसंख्या बढ़ रही है. 2050 तक भारत की जनसंख्या 150 करोड़ तक पहुंच जाएगी. उस समय पानी की एक बोतल के लिए मारामारी होना तय है. तब एक हज़ार घनमीटर पानी भी एक आदमी को नहीं मिलेगा. यह संकट अजीत पवार को कब नज़र आएगा?

feedback@chauthiduniya.com

शंकरराव चव्हाण की दूरदर्शिता पर ध्यान दें

मराठवाड़ा की पानी की समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण ने अपने मंत्रित्वकाल में विपक्ष की कड़ी आलोचना के बावजूद औरंगाबाद के पास पैठण क्षेत्र में जायकवाड़ी बांध का निर्माण कराया था. उससे औरंगाबाद का विकास हुआ. वहां उद्योग बढ़े, बस्तियां बढ़ीं. उसी तरह मराठवाड़ा के किसानों की बंजर भूमि में फ़सल लहलहा उठी. दस-बारह साल पहले जब शंकरराव चव्हाण सत्ता में नहीं थे, उन्होंने औरंगाबाद में एक जल परिषद में कहा था कि जायकवाड़ी बांध का निर्माण मराठवाड़ा के किसानों के लिए हुआ है, लेकिन आज अधिकांश पानी औरंगाबाद शहर के औद्योगिक क्षेत्र, शहरवासियों के लिए इस्तेमाल होता है. इसीलिए किसानों को आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिलता. इसलिए नया बांध बनाकर औरंगाबाद की पानी की समस्या सुलझाना आवश्यक है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण के शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है.

शंकरराव चव्हाण

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 05 सितंबर–11 सितंबर 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9661337777 / 9472722024

9472727767 / 9162779209

बिना लग्न की शादी

सरोज सिंह

बिना लग्न के शादी होने लगे तो गांव–टोले में खुसुर–फुसुर होने लगती है. तरह–तरह के काल्पनिक तथ्यों को स्थापित करने के लिए तर्कों के तीर चलने शुरू हो जाते हैं. कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ. हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक नज़रिये से जो चीज़ पूरी सही दिखती है, वही चीज़ दूसरे नज़रिये से पूरी ग़लत दिखाई पड़ने लगती है. नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इन दिनों दूसरे दलों के नेताओं व विधायकों को दिल खोलकर गले लगा रही है. आमतौर पर इस तरह का राजनीतिक खेल तब होता है जब कोई सरकार अल्पमत में हो या फिर चुनाव का मौसम हो. सभी जानते हैं कि नीतीश सरकार को प्रचंड बहुमत हासिल है और विधानसभा की बात छोड़ भी दें तो अभी लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी वक़्त है. इसलिए राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बिना लग्न के इस तरह की शादियों की ख़ासी चर्चा है.

नीतीश कुमार को क़रीब से जानने वाले बताते हैं कि वह बिना वजह कोई राजनीतिक गोटी नहीं खेलते. अगर एनडीए पार्ट–2 के पहले ही साल में दूसरे दलों के नेताओं व विधायकों को जदयू में शामिल किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा दांव भी खेल सकते हैं या फिर वह आने वाले किसी दबाव व संकट से बचने की पूर्व तैयारी कर रहे हैं. ग़ौरतलब है कि लोजपा के दो विधायकों को शामिल कर लेने के बाद जदयू के विधायकों की संख्या 118 तक पहुंच गई है यानी अपने बलबूते बहुमत से महज़ पांच क़दम दूर. लेकिन भाजपा के साथ बेहतर तालमेल से चल रही सरकार से छेड़छाड़ क्यों. जानकारों का कहना है कि कुछ ऐसे मसले हैं जिसे लेकर भाजपा व जदयू में मतभेद हैं. सिमरिया घाट में कुंभ के आयोजन को लेकर कड़वाहट बढ़ी है. भाजपाई सार्वजनिक तौर पर भले ही चुप हैं, पर अंदरख़ाने उनकी पीड़ा साफ़ झलकती है. इसके अलावा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शाख़ा खोलने, कुलपतियों की नियुक्ति और सरकार के सारे अच्छे कामों का श्रेय ख़ुद बटोर लेने की प्रवृति भी भाजपा को रास नहीं आ रही है. इसके अलावा कुछ नीतिगत मामलों में भी खटपट की बात कही जा रही है. नीतीश कुमार को भी इसका पूरा अहसास है. इसलिए भाजपा के किसी भी तरह के दबाव को टालने के लिए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की क़वायद की जा रही है. यह ज़रूरी नहीं है कि अपने बलबूते 123 का आंकड़ा पाने पर भाजपा का साथ छोड़ दिया जाएगा. लेकिन एक लाइन ज़रूर खींच दी जाएगी कि भले ही आपकी ताक़त बढ़ गई है, पर सरकार के रोज़मर्रा के कामों में दबाव व दख़ल की गुंजाइश नहीं है. इसके अलावा जिस तरह से अल्पसंख्यकों का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति हो रहा है, उससे जदयू को लगता है कि एक ऐसा मंच हमेशा तैयार रहे, जहां से अगर ज़रूरत पड़ी तो आर–पार की घोषणा की जा सके. पौधारोपण व सदस्यता अभियान के लिए 13 मंत्रियों को प्रभारी बनाया जा रहा है. मतलब एक प्रभारी मंत्री के ज़िम्मे तीन ज़िले. प्रत्येक ज़िले में पहले ही एक प्रभारी मंत्री है, इसमें भाजपा के मंत्री भी शामिल हैं. लगता है कहीं न कहीं से यह एक समानांतर शक्ति केंद्र स्थापित करने की कोशिश है. एक उदाहरण से इसे समझिए. मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी में जदयू के एक मंत्री व दो वज़नदार नेता आपस में पौधारोपण अभियान पर बात कर रहे थे. कांग्रेस से आए इस नेता ने नीतीश कुमार के बेहद क़रीबी मंत्री से पूछा कि इस अभियान का मतलब क्या है. एनडीए पार्ट 2 में मंत्री न बन पाए नेता जी ने कहा कि ग्रीन बिहार. इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र में तो यही है, पर बीच–बीच में हवा पानी भी दिया जाएगा. इसके बाद सुधा दही का मज़ा लेते हुए कहा कि चलो फोटोग्राफर ने दही खाते हुए तस्वीर उतारी, कहीं बिंदेश्वरी दुबे की तरह मुर्ग़ा खाते हुए उतारी होती तो दिक्क़त हो जाती. मतलब अभियान एक साथ कई लक्ष्य भेदने की परिकल्पना वाला है. ग्रीन बिहार के नाम पर पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत करने की हरसंभव कोशिश शुरू हो गई है, ताकि पार्टी की जड़ को बेहद मज़बूत बनाया जा सके.

बिना लग्न की शादी को कुछ जानकार पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने की क़वायद के तौर पर भी देख रहे हैं. विधान परिषद व राज्यसभा की भरी जाने वाली सीटों को लेकर बढ़ रहे दबाव को अभी से ही कम करने के लिए और पार्टी में कुछ नेताओं को अपने क़द में रहने का संदेश देने के लिए दूसरे दलों के नेताओं व विधायकों को जदयू में शामिल कराया जा रहा है. बलियावी जी के अरमानों को घेरे में रखने के लिए शकील अहमद ख़ां को पार्टी में शामिल किया गया है. इसी तरह महाचंद्र सिंह को कुछ भूमिहार नेताओं पर दबाव बनाने के लिए लाया गया है. डॉ. रामवचन राय भी परिषद में दबाव कम करने की दवा बनेंगे. कोशिश डॉ. जाबिर हुसैन को भी पार्टी में शामिल कराने की हो रही है, ताकि परिषद के गणित को अपने हिसाब से सुलझाया जा सके. इसके अलावा कुछ जानकारों का कहना है कि अन्ना हज़ारे के आंदोलन के कारण कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह गिरा है और जाने अनजाने इसका फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है, ऐसे में गठबंधन को लेकर भाजपा के तेवर कुछ तल्ख़ भी हो सकते हैं. एक पत्रिका द्वारा हाल में ही कराए गए सर्वेक्षण में भाजपा को काफ़ी बढ़त मिलने का आकलन किया गया है. बिहार भाजपा भी इस सर्वे से पूरे जोश में है. कुछ स्थानीय नेताओं को लगने लगा है कि अब देश की बागडोर पार्टी के हाथ में आने ही वाली है. यही वजह है कि नीतीश कुमार हर उस सवाल का जवाब पहले ही ढूंढ लेना चाहते हैं, जो आने वाले समय में सिरदर्द बन सकता है. इसलिए विधायकों को शामिल किया जा रहा है. विधायक नौशाद कह रहे हैं कि मैं लोजपा में हूं, पर स्पीकर साहब ने कह दिया है कि आपने आवेदन दे दिया है, इसलिए आप जदयू के सिपाही ही माने जाएंगे. लोजपा स्पीकर के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है. कांग्रेस के विधायकों को भी आसान चारा माना जा रहा है. बताया जाता है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग ऑपरेशन कांग्रेस पर भी काम कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि देरी जदयू की तरफ़ से ही है. सही वक़्त का इंतज़ार हो रहा है. आला कमान की हरी झंडी मिलते ही ऑपरेशन कांग्रेस को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा. बहुमत का आंकड़ा पार कर लेने के बाद जदयू पूरी आक्रामकता के साथ अपने विस्तार कार्यक्रम को अंजाम देने में जुट जाएगा, भले ही इससे भाजपा को दिक्क़त ही क्यों न हो.

feedback@chauthiduniya.com

अल्पसंख्यकों का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति हो रहा है, उससे जदयू को लगता है कि एक ऐसा मंच हमेशा तैयार रहे, जहां से अगर ज़रूरत पड़ी तो आर-पार की घोषणा की जा सके. पौधारोपण व सदस्यता अभियान के लिए 13 मंत्रियों को प्रभारी बनाया जा रहा है. मतलब एक प्रभारी मंत्री के ज़िम्मे तीन ज़िले. प्रत्येक ज़िले में पहले ही एक प्रभारी मंत्री है, इसमें भाजपा के मंत्री भी शामिल हैं. लगता है, कहीं न कहीं से यह एक समानांतर शक्ति केंद्र स्थापित करने की कोशिश है. मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी में जदयू के एक मंत्री व दो वज़नदार नेता आपस में पौधारोपण अभियान पर बात कर रहे थे. कांग्रेस से आए इस नेता ने नीतीश कुमार के बेहद क़रीबी मंत्री से पूछा कि इस अभियान का मतलब क्या है ?

चौथी दुनिया

शहर के नाले से निकलने वाले गंदे जल से इसके उत्तरी छोर के खेतों की सिंचाई व्यवस्था भी होती थी.

पूर्णिया ज़िले समेत बिहार के अन्य ज़िलों एवं देश के अन्य राज्यों से सबसे पहले पशुओं को पूर्णिया ज़िले की सीमाओं में पहुंचाया जाता है.

चौथी दुनिया

एक नज़र

महाकवि आरसी इस सदी के बड़े साहित्यकार : सुलभ

[illegible]

सुजय कुमार पार्षद बने

[illegible]

– चौथी दुनिया ब्यूरो

कुमार कालिका जयंती धूमधाम से मनेगी

[illegible]

– इमरान ख़ान

आईपीसी का बाबाधाम में आवासीय अपार्टमेंट

[illegible]

देवघर झारखंड का पहला सोलर सिटी बना

[illegible]

– रणजीत झा

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

गया

घोटालेबाज़ों की मनमानी

सुनील सौरभ

आने वाले समय में बिहार में कथित सुशासन घोटाले के शासन के रूप में तब्दील जो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी पदाधिकारियों की मनमानी के कारण जिस तरीक़े से सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की जा रही है, उससे अंदाज़ा लगाना सहज हो जाता है कि आने वाले समय में राज्य के एक प्रखंड से करोड़ों-अरबों के घोटाले उजागर होंगे. वहीं दूसरी ओर घोटाले-गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद भी निचले स्तर के पदाधिकारी चांदी के जूते की मार से इतने मदहोश हैं कि अपने उच्च अधिकारयों के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं. ऐसा ही मामला है गया ज़िले के नक्सल प्रभावित कोंच प्रखंड का, जहां काम के बदले अनाज योजना के नाम पर आवंटित क़रीब 3 हज़ार क्विंटल अनाज न तो जनवितरण के डीलर के पास पहुंचा और न ही मज़दूरों को मिला. लगभग 40 लाख रुपये के मूल्य का यह अनाज कोंच प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की मिलीभगत से एक दबंग बिचौलिये ने बाज़ार में बेच डाला. इस मामले में मज़ेदार बात तो यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच के बाद जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन कमजोर डीलरों विजय पासवान, (अदई), व्यास चौधरी (कोंच) तथा तपेश्वर पासवान के नाम पर आवंटित काम के बदले अनाज योजना का खाद्यान्न उठाकर बाज़ार में बेचने वाले बिचौलिये कमलेश शर्मा पर दो-दो थाने में 7 ईसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद कोई कारवाई नही हो सकी.

हालांकि ज़िला पदाधिकारी ने टिकारी के अनुमंडल पदाधिकारी को क़रीब 3 हज़ार क्विंटल अनाज की राशि की वसूली संबंधित जनवितरण के डीलरों से करने का आदेश दिया है. टिकारी के अनुमंडल पदाधिकारी ने कोंच के प्रखंड विकास पदाधिकारी को राशि वसूल करने का आदेश दिया है, लेकिन आजतक डीलरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा 2006-07 में हुए इस घोटाले में काम के बदले अनाज येाजना के अंतर्गत जनवितरण के डीलर विजय पासवान को 175.10 क्विंटल, व्यास चौधरी को 1403.03 क्विंटल, तपेश्वर पासवान को 1328.00 क्विंटल चावल का आवंटन किया गया था, जिसकी प्रति क्विंटल सरकारी दर 1370 रुपये थी. इस प्रकार कुल आवंटित चावल की क़ीमत 39, 81, 507 रुपया 70 पैसे हुई. फूड फॉर वर्क योजना में 40 लाख रुपये के घोटाले की शिकायत क्षेत्रीय जदयू के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को पूरे प्रमाण के साथ लिखित रूप से भेज चुके हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. वहीं दूसरी ओर जनवितरण के डीलर प्राथमिकी दर्ज होने के डर से सहमे हैं और इस बात पर तैयार भी है कि यदि प्राथमिकी दर्ज हुई तो वे अपने को निर्दोष साबित करने के लिए सच्चाई को उगलने से बाज़ नहीं आएंगे. फ़िलहाल घोटालेबाज़ और बिचौलिए मस्ती में हैं और घोटाले की शिकायत करने वाले सरकारी महकमे में सुशासन के भ्रष्टाचार से परेशान हैं.

feedback@chauthiduniya.com

आरा

काम के बदले अनाज योजना
भोजपुर में भारी लूट-खसोट

डॉ. सुरेंद्र सागर

भोजपुर ज़िले में सरकार द्वारा ग़रीबों के उत्थान को लेकर चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की हवा निकल रही है. ग़रीबों के हक़ को, अधिकारी और उनके संरक्षित लोगों द्वारा मिलने से पहले ही छीन लिया जाता है. काम के बदले अनाज योजना एक ऐसी ही कल्याणकारी योजना है, जिसका लाभ लेकर ग़रीब और मज़दूर अपनी रोज़ी रोटी का बख़ूबी इंतज़ाम कर लेते थे. लेकिन इस योजना को भी लूट-खसोट का माध्यम बना दिया गया. जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों ने इस योजना में जमकर हेराफेरी की है. भोजपुर ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में वर्ष 2001 से 2005 तक काम के बदले अनाज योजना के तहत पीडीएस दुकानदारों ने खाद्यान्न घटक से चावल का भारी मात्रा में उठाव किया था. कई प्रखंडों में पी.डी.एस. दुकानदारों द्वारा मज़दूरों को चावल वितरित नहीं किया गया. एस.जी.आर वार्ड के तहत लाखों रुपये मूल्य का चावल मज़दूरों को वितरित न किए जाने का मामला जब सार्वजनिक हुआ तो भोजपुर की डी.एम. डॉ. प्रतिमा एस. वर्मा ने गंभीरता दिखाई. डी.एम. के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हुई है. अब तक ज़िले के आठ प्रखंडों के कुल 32 पीडीएस दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई हो चुकी है. कइ दुकानदारों पर अभी गाज गिरने वाली है. ज़िले के सहार प्रखंड के 09, उदवंतनगर के 06 गड़हनी के 03, बड़हरा के 05, पीरो के 05, कोउलवर के 01, अगीआंव के 02 तथा बिहियां के 01 जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों पर एफ.आई.आर दर्ज की गई है. पी.डी.एस. दुकानदारों पर सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया गया है. 85 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. काम के बदले अनाज योजना के चावल के गबन और हेराफेरी से स्पष्ट हो गया है कि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को ग़रीबों तक पहुंचाने से कैसे रोका गया है. पी.डी.एस. दुकानदारों पर एफ.आई.आर दर्जकर गबन के विरुद्ध प्रशासनिक शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लाखों रुपये के चावल गबन करने के मामले में सबंधित प्रखंडों के बी.डी.ओ और ज़िले के अधिकारियों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है. प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश के बावजूद कई प्रखंडों के बीडीओ द्वारा पीडीएस दुकानदारों को बचाने की कार्रवाई से ऐसा लगने लगा है. शाहपुर के बी.डी.ओ पर इस मामले में तो कार्रवाई होने के संकेत भी मिलने लगे हैं. ज़िले के लगभग सभी प्रखंडों में एसजीआरवाई में चावल की बड़े पैमाने पर हेराफेरी गबन और गड़बड़ी को लेकर भले ही प्रशासन की नींद देर से खुली हो, लेकिन एक बात तय है कि इस योजना में जमकर लूट की गई है. ग़रीबों मज़दूरों को दिए जाने वाले चावल को खुले बाज़ार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता रहा है. ग़रीब मज़दूरों के जीवनयापन को लेकर चलाई गई काम के बदले अनाज योजना का लाभ ग़रीबों को तो नहीं मिला, लेकिन जनवितरण प्रणाली के दुकानदार और अधिकारी मालामाल हो गए. चावल के गबन और हेराफेरी के मामले सामने आने के बाद ग़रीबों की कल्याणकारी योजनाओं और इसके कार्यान्वयन पर सवाल खड़ा हो गया है. इस योजना के अंतर्गत ग़रीब मज़दूरों को काम के बदले अनाज दिए जाने का प्रावधान निर्धारित था. काम करने वाले मज़दूरों को दो रुपये दस पैसे प्रतिकिलो की दर से चावल उपलब्ध कराना था. सस्ते दर पर चावल की क़ीमत को देख पीडीएस दुकानदारों ने इसमें कालाबाज़ारी का रास्ता निकाल लिया. इसमें प्रखंड के बीडीओ और वरीय अधिकारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित कराई गई. दुकानदार और अधिकारियों की साठगांठ से ग़रीबों के हक़ पर हमला बोला गया. कई प्रखंडों में काम के बदले पैसे दे दिए गए और चावल को ज़्यादा दर पर बाज़ार में बेच दिया गया. ऐसा कर पीडीएस दुकानदारों ने ख़ूब लूट मचाई. दुकानदारों का मनोबल इस क़दर बढ़ा हुआ है कि वे सरकारी आदेश की भी परवाह नहीं करते. डीआरडीए के डायरेक्टर स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिन 32 पी.डी.एस. दुकानदारों पर चावल गबन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, वे सरकारी एवं प्रशासनिक आदेश को नहीं मानते. ऐसे आदेश को न मानने के पीछे कहीं न कहीं वरीय अधिकारियों या सत्ता में बैठे राजनेताओं का इन दुकानदारों पर संरक्षण प्राप्त होना कारण हो सकता है. पीडीएस दुकानदारों की छवि शुरू से आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं, हक़ों से खिलवाड़ करने की रही है. चाहे ए.पी.एल., बी.पी.एल धारकों को अनाज और मिट्टी तेल के वितरण का मामला हो या फिर काम के बदले अनाज योजना से ग़रीबो को चावल वितरण करने का. भोजपुर ज़िला प्रशासन ने ऐसे दुकानदारों पर बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई शुरू की है, लेकिन एक बात तय है की ज़िले के वरीय अधिकारियों की नाक के नीचे ग़रीबों का हक़ छीना गया है.

> सस्ते दर पर चावल की क़ीमत को देख पीडीएस दुकानदारों ने इसमें कालाबाज़ारी का रास्ता निकाल लिया. इसमें प्रखंड के बीडीओ और वरीय अधिकारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित कराई गई. दुकानदार और अधिकारियों की साठगांठ से ग़रीबों के हक़ पर हमला बोला गया. कई प्रखंडों में काम के बदले पैसे दे दिए गए और चावल को ज़्यादा दर पर बाज़ार में बेच दिया गया. ऐसा कर पीडीएस दुकानदारों ने ख़ूब लूट मचाई. दुकानदारों का मनोबल इस क़दर बढ़ा हुआ है कि वे सरकारी आदेश की भी परवाह नहीं करते.

feedback@chauthiduniya.com

जानकारी ही टीबी का बचाव : डॉ. साह

बी. पी. साह

वर्तमान में टीबी जैसी संक्रामक बीमारी का फैलाव तीव्र गति से जारी है, जिससे सीमांचल में इस बीमारी से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है. इस बीमारी के फैलाव व रोकथाम पर पूर्णिया के प्रसिद्ध चिकित्सक बी. पी. साह ने अहम जानकारी दी.

● **टीबी जैसी संक्रामक बीमारी के तीव्र गति से फैलाव के क्या कारण हैं?**

टीबी जीवाणु जनित रोग है, यह सफ़ाई की व्यवस्था के अभाव, ओवर क्राउडिंग, टीबी पीड़ित व्यक्तियों द्वारा शारीरिक डिस्पोजल थूक आदि का खुले में फेंकना, घरों में खिड़कियों का अभाव जिससे सूर्य रोशनी का न पहुंचना, वातावरण में आद्रता, पीड़ित व्यक्तियों के श्वास आदि से इसके जीवाणु व बीमारी फैलती है. अक्सर देखा जाता है कि महानगरों में काम करने वाले मज़दूरों का एक ही कमरे में सोना टीबी का कारण बनता है.

● **टीबी की जांच व रोकथाम के बारे में बताएं.**

बलग़म की जांच, सीने का एक्स-रे, एलीसा टेस्ट आदि से टीबी रोग का पता चलता है. टीबी की जानकारी ही इसका बचाव है. इसमें साफ़-सफ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. संक्रमित व्यक्ति से परहेज़ करना चाहिए. उच्च कैलोरीयुक्त भोजन करना चाहिए. चूंकि कमज़ोर व्यक्तियों के शरीर की रोग प्रतिरोधन क्षमता कम हो जाती है, जिससे वह टीबी से ग्रसित हो जाते हैं.

● **टीबी के इलाज के बारे में बताएं.**

अन्य बीमारी के जीवाणु की तरह टीबी के जीवाणु में भी प्रतिरक्षण क्षमता उत्पन्न हो गई है, जिससे इसके इलाज में 6 से 9 महीने का समय लगता है. टीबी फेफड़े से लेकर हड्डी तक में हो सकता है. इसके इलाज में रिफेवसीन के साथ पाइरेजीमाईड, इथॅमब्यूटाल एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा को 6 से 9 महीने तक खिलाया जाता है.

नीरज कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

नगर परिषद ने ही बिगाड़ी सूरत

छपरा

विजयेंद्र कुमार

प्रमंडलीय मुख्यालय छपरा शहर की जल निकासी की लाइफ लाइन के नाम से मशहूर खनुआ नाला नकारा बनकर रह गया है. नगर परिषद की कारगुज़ारी से टोडरमल के ज़माने से निर्मित 18 फीट चौड़ा व 40 फीट गहरे नाले के ऊपर दुकानों का निर्माण करा दिया गया. इससे बरसात के दिनों में जल निकासी का कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है और थोड़ी सी बरसात से सड़कों से लेकर हर गली-मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति व्याप्त हो जाती है. सन 1918 में निर्मित खनुआ नाले की पूर्ववत स्थिति यह रही है कि इस नाले से होकर समूचे शहर की जल निकासी आसानी से हो जाती थी. शहर के नाले से निकलने वाले गंदे जल से इसके उत्तरी छोर के खेतों की सिंचाई व्यवस्था भी होती थी. इसका निर्माण योजनाबद्ध तरीक़े से इस तरह किया गया था कि शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित घाघरा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो जाने पर रूपगंज व साहेबगंज में बने किवाड़ को खोलकर शहर की जल निकासी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचाई व्यवस्था भी समुचित ढंग से पूर्ण हो जाती थी. मगर कालांतर में यह व्यवस्था सरकार की ग़लत नीतियों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है. वर्तमान हालात यह है कि इस नाले के ऊपर नगर परिषद के कर्ता-धर्ताओं ने दुकान बनाकर पूरी तरह ढक दिया है तथा उक्त दुकानों की अच्छी क़ीमत वसूलकर नगरपालिका के माध्यम से व्यवसायियों को सेटलमेंट करा दिया गया. इस दरम्यान शहर की आबादी में कई गुणा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खनुआ नाले की चौड़ाई बढ़ने के बजाय इस पर एक स्ट्रक्चर 7 फीट चौड़ा और 8 फीट गहराई का बना दिया गया. बताते हैं कि उक्त नाले की भूमि गैर मजरूआ आम कैसरे हिंद के तौर पर खतियान में दर्ज है, जिसका सेटलमेंट करने का अधिकार निजी उपयोग के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं है. इसका मालिकाना हक़ राष्ट्रपति को है, लेकिन भू-माफ़िया से साठगांठ कर बंदोबस्ती दुकान के नाम पर शहर के कुछ चुनिंदा व्यक्तियों ने इसे अपने नाम करा लिया है. इसके कारण पुराने नाले की बग़ल में रहने वाले शहरवासियों के अपने घरों तक आने-जाने में भी भयावह परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अब जबकि शहर की जल निकासी के लिए ज़िला प्रशासन अपने स्तर से खनुआ नाले की सफ़ाई के लिए कार्य योजना बनाकर अमल करने की तैयारी करता है, तो शहर के भू-माफ़िया में हड़कंप की स्थिति पैदा हो जाती है. इस मामले में दो बार उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया जा चुका है, जिसके आलोक में न्यायालय ने ज़िला प्रशासन को इस मामले में यथोचित कार्रवाई करने का आदेश भी पारित किया है. यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि नगरपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बहुत सारे नाले की ज़मीन पर अपना क़ब्जा जमा चुकी है, जिसके कारण शहर की जल निकासी पूर्णरूपेण बाधित है और बरसात के दिनों में शहर की हालत जल जमाव के कारण बदतर हो जाती है. थोड़ी सी बरसात के कारण शहर के प्रभुनाथ नगर, दहियावां टोला साधनापुरी, शाक्तिनगर, भगवान बाज़ार, करीम चक, गुदरी व काशी बाज़ार आदि मोहल्लों में नाले का पानी सड़क पर बहने लगता है, जिसके चलते सड़क पर गंदे पानी व कीचड़ की सड़ांध आमजन को परेशानी में डाल देती है. शहर की जल निकासी व साफ़-सफ़ाई की पूर्ण जवाबदेही स्थानीय शासन के अंतर्गत नगरपालिका के ज़िम्मे आती है.

feedback@chauthiduniya.com

मवेशी तस्करी करोड़ों का धंधा बनी

विगत कई वर्षों से चले आ रहे मवेशी तस्करी के धंधे पर लगाम लगाने के लिए किशनगंज के वर्तमान पुलिस अधीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा ने जहां सभी थानों को निर्देश देकर कठोर क़दम उठाए, वहीं मवेशी तस्करों ने नए मार्ग से तस्करी को अंजाम देने का रास्ता ढूंढ निकाला है, जिसके द्वारा वर्तमान में मवेशी तस्करी चालू है. मालूम हो कि भारत का चिकेन नेक कहा जाने वाला किशनगंज विगत कई वर्षों से मवेशी तस्करी का प्रमुख केंद्र बना हुआ था, जिसपर वर्तमान पुलिस अधीक्षक ने पदभार ग्रहण करते ही विराम लगाया और पशुओं को ज़ब्त कर कई नामी तस्करों को जेल की हवा खिलाई. इससे मवेशी तस्करों में हड़कंप मच गया. तभी से मवेशी तस्करों ने तस्करी हेतु नए रास्ते ईजाद कर लिए हैं. अब दो नए मार्गों से होकर मवेशी तस्करी का धंधा बिना किसी बाधा के चालू है. बिहार एवं देश के अन्य राज्यों से सबसे पहले पशुओं को पूर्णिया ज़िले की सीमाओं में पहुंचाया जाता है.

पूर्णिया ज़िले के ज़ीरो माइल गुलाबबाग, बायसी अनुमंडल होते हुए पशुओं को पैदल व ट्रकों से कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र में उतारा जाता है, जहां से बंगाल के दालकोला चकुलिया होते हुए बांग्लादेश भेजा जाता है. वहीं दूसरा मार्ग अररिया बहादुरगंज, ठाकुरगंज व बंगाल के खरीबाड़ी मैनागुड़ी एवं कूचबिहार बॉर्डर होते हुए बांग्लादेश पहुंचाया जाता है. वर्तमान में यह धंधा सोने का अंडा देने वाली मुर्ग़ी बना हुआ है, जिसका सालाना व्यवसाय प्रतिवर्ष करोड़ों में है. इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि मवेशियों की इस प्रकार की तस्करी पर यह प्रश्न खड़ा कर रही है कि कहीं गौवंशीय पशु भविष्य में विलुप्त न हो जाएं. वहीं पुलिसिया कार्रवाई के संबंध में लोगों का कहना है कि जबतक पूर्णिया प्रमंडल के चारों ज़िलों की पुलिस अपने पुलिस कप्तान के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई नहीं करती है तब तक इस पर रोक लगाना असंभव दिख रहा है. वैसे सरकार ने गुलाबबाग ज़ीरो माईल, किशनगंज, अररिया जैसे जगहों पर एंटी एनिमल क्रूवेल थानेदार को नियुक्त कर रखा है, जिनकी इस संबंध में भूमिका नगन्य रहती है.

अर्जुन सिंह
feedback@chauthiduniya.com

विक्रम गरजे तो मनोज भड़के

धनंजय मिश्रा

सीवान में भाजपा के दो बड़े नेता, विधायक विक्रम कुंवर और विधान पार्षद मनोज कुमार सिंह आमने-सामने हैं. दोनों के बीच टिप्पणियां जारी हैं. दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध भ्रष्ट और चारित्रिक पतन की दास्तां बयान कर रहे हैं, विरोधी दलों के नेता-कार्यकर्ता ही नहीं अपितु आमजन भी मज़ा ले रहे हैं. इससे भाजपा की भी छवि भी धूमिल हो रही है. दरअसल बिहार के मुख्य सचिव को प्रेषित अपने पत्र में बिक्रम कुंवर ने इस बात का ज़िक्र किया कि विधान पार्षद मनोज कुमार सिंह पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन का शूटर और अपराधी है. इस बात की जानकारी जब मनोज सिंह को हुई तो वह गुस्से में आ गए. उन्होंने इस आरोप-पत्र को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दस लाख रुपये का मानहानि का मुक़दमा बिक्रम कुंवर के विरुद्ध दायर कर दिया. आरोप लगाया कि राजद शासनकाल में बिक्रम कुंवर, जब राज्यमंत्री थे तो वह अपराधियों को सरंक्षण और शरण देते थे. सुशासन में ऐसे नेता भी सुधर रहे हैं, बावजूद इसके परिसदन में जब कुंवर ठहरते हैं तो आदतन वह अधिकारियों को बुलाकर हड़काते हैं और धन उगाही करते हैं, पंचायत सचिव से इंदिरा आवास मद की राशि में से भी प्रति यूनिट एक हज़ार रुपये रिश्वत की मांग करते हैं और मांग पूरी होती न देख पंचायत सचिव अमरेंद्र कुमार सिंह के ख़िलाफ़ मोबाइल फोन पर धमकी देने की सनहा दर्ज करा दी, ताकि उनकी रिश्वत मांगने की बात पर अविश्वसनीय पर्दा पड़ जाए.मनोज सिंह के आरोपों से बौखलाए कुंवर ने कहा कि सरकार हम दोनों की संपत्ति की जांच करा ले, ताकि मालूम हो जाए कि किसके पास कितनी संपत्ति है, इतना ही नहीं महज़ एक दशक में मनोज सिंह धन कुबेर कैसे बने हैं, उसकी असलियत भी सामने आ जाएगी. मगर इन दोनों बड़े नेताओं में कब और क्यों दरार पड़ी, इसकी बानगी भी राजनीतिक विश्लेषकों की ज़ुबानी जानें. बात विगत बिहार विधानसभा चुनाव काल की है. मनोज सिंह अपने छोटे भाई धनंजय सिंह को रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ाना चाहते थे, क्योंकि नए परिसीमन के पश्चात ज़िले का क्षत्रिय बहुल यह विधानसभा क्षेत्र जदयू से कटकर भाजपा के खाते में आ गया था. वस्तुत: अपने भाई को भाजपा का टिकट दिलाने हेतु मनोज सिंह ने काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन दल बदलने में माहिर राजनीतिक खिलाड़ी माने जाने वाले नेता बिक्रम कुंवर ने राजद से नाता तोड़ भाजपा का टिकट लेकर जीत हासिल कर ली. यहीं से इन दोनों के बीच आंतरिक विवाद शुरू हो गया, जो अब सतह पर आने लगा है. राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यह बात सच है कि राजद शासन काल में मो. शहाबुद्दीन के क़रीबी बिक्रम कुंवर भी रहे थे, लेकिन मो. शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद और एनडीए का बिहार में संवरते भविष्य के मद्देनज़र बिक्रम पाला बदलकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मो. शहाबुद्दीन के विरुद्ध तीखी बयानबाज़ी करने लगे और एनडीए की सराहना और गुणगान करने लगे. इससे जेपी आंदोलन की उपज बिक्रम भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने और बीजेपी का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए. दूसरा वाक़िया मनोज कुमार सिंह का है, जो प्रारंभिक दौर में मो. शहाबुद्दीन के जेल में जाने के बाद राजद और मो. शहाबुद्दीन के कुछ आपराधिक मामलों में बतौर सरकारी गवाह बनकर उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया. मो. शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ अंत से आक्रोशित जनता की एक बड़ी जमात का उन्हें समर्थन मिलने लगा और वह ज़िला कोऑपरेटिव चुनाव में वे भारी मतों से विजयी हो गए और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. मगर इसके बाद से विधान परिषद चुनाव में एनडीए के ही भाजपा-राज्य प्रत्याशी गर्णजीत सिंह उर्फ़ न्यास सिंह के ख़िलाफ़ वे बाग़ी उम्मीदवार खड़े होकर भारी मतों से विजयी हो गए. भाजपा के बाग़ी उम्मीदवार होने के कारण भाजपा ने अपनी पार्टी से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, लेकिन किंतु कुछ महीनों के बाद अपनी मज़बूत पहुंच के कारण भाजपा के प्रांतीय शीर्ष नेताओं से अच्छे तालमेल क़ायम करने में वे सफल रहे और पुन: भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली. सीवान में भाजपा के वे अब एक सशक्त युवा हैं, जिनका राजनीतिक वर्चस्व और जनमत बढ़ता ही जा रहा है. यह दीगर बात है कि सीवान में उनकी बढ़ती राजनीतिक साख और लोकप्रियता से घबराए-बौखलाए भाजपा के स्थानीय नेता भी उनका विरोध रहे हैं, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर पाते. इतना तय है कि इन दोनों क्षेत्रीय नेताओं की आपसी लड़ाई से दोनों का ही कुछ न कुछ नुक़सान तो होगा ही.

बिक्रम कुंवर

मनोज कुमार सिंह

feedback@chauthiduniya.com